आज का विचार

इच्छाएं, आवश्यकताएं और नींद जीवन में कभी पूरी नहीं होती, जो जितनी सुविधा में वो उतनी ही दुविधा में है।

दैनिक

सिटी दर्पण

आईना सच का

सिटी दर्पण-राष्ट्रीय दैनिक हिंदी समाचार पत्र की अधिकारिक वेबसाइट पर जाने के लिए स्कैन करें।

चंडीगढ़ । वीरवार, 2 अप्रैल, 2026 वर्ष 24, अंक 79, मूल्य: 3 रुपए, पृष्ठ 8 RNI Regn No.: CHAHIN/2003/09265 Established 2003 www.citydarpan.com

पंजाब में समान विकास के लिए पहली बार जाति आधारित सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण करवाया जाएगा: भगवंत मान

सभी समुदायों के जीवन स्तर का मूल्यांकन किया जाएगा; पूरी जानकारी गोपनीय रखने वाला यह सर्वेक्षण पहली अप्रैल से शुरू

यज्ञांश शर्मा

चंडीगढ़

पंजाब सरकार की शानदार चार साल भगवंत मान दे नाल श्रृंखला के हिस्से के रूप में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आज ग्रामीण विकास और पंचायत विभाग का चार साल का व्यापक रिपोर्ट कार्ड पेश किया, जिसमें यह दिखाया गया कि निरंतर नीतिगत हस्तक्षेप ने गांवों के बुनियादी ढांचे को कैसे बदला है, जमीनी स्तर पर प्रशासन को मजबूत किया है और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाए हैं। ग्रामीण विकास को समग्र विकास के केंद्रीय स्तंभ के रूप में बताते हुए मुख्यमंत्री ने पंजाब के पहले जाति आधारित सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण की शुरूआत से लेकर बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचा निर्माण, पारदर्शी भूमि प्रबंधन के माध्यम से राजस्व उत्पन्न करने और युवा-केंद्रित विकास कार्यक्रमों सहित प्रमुख पहलों की रूपरेखा पेश की।

पहली अप्रैल से शुरू होने वाले जाति आधारित सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण को समानता और नीति निर्माण सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इसका उद्देश्य कार्रवाई को गोपनीय रखते हुए सभी समुदायों के जीवन स्तर का मूल्यांकन करना है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण विकास रिपोर्ट कार्ड एक व्यापक शासन ढांचे का हिस्सा है, जिसके तहत आप सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, सिंचाई, कृषि और अन्य प्रमुख क्षेत्रों में सेक्टर-वार प्रदर्शन के साथ-साथ जवाबदेही, पारदर्शिता और परिणामों पर अपना ध्यान केंद्रित कर रही है। ग्रामीण विकास और पंचायत विभाग का रिपोर्ट कार्ड पेश करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, पिछले चार वर्षों में गांवों का पूर्ण विकास हुआ है, जिसमें बड़े पैमाने पर निर्माण कार्य, तालाबों की सफाई शामिल है क्योंकि राज्य ने सरकारी जमीनों से अवैध कब्जे हटाकर और अन्य तरीकों से पैसा कमाया है।

मुख्यमंत्री ने कहा, राज्य के सख्त प्रयासों के कारण पंचायत चुनावों में सर्वसम्मति में वृद्धि हुई है। पंजाब में 13,236 पंचायतों के लिए चुनाव 2024 में हुए थे, जिनमें बड़ी संख्या में पंचायतें सर्वसम्मति से चुनी गईं। 2018 में लगभग 1,870 पंचायतें सर्वसम्मति से चुनी गई थीं, लेकिन 2024 में 2,970 पंचायतें सर्वसम्मति से चुनी गईं थी। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, 1,100 से अधिक पंचायतें सर्वसम्मति से चुनी गईं, जिससे गांवों में सामुदायिक सौहार्द मजबूत होता है और गांवों का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित होता है। उन्होंने कहा, पंजाब सरकार ने सरपंचों का मानभत्ता 1,200 रुपये से बढ़ाकर 2,000 रुपये प्रति माह कर दिया है।

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, ग्रामीण विकास के लिए 15वें वित्त आयोग के तहत वर्ष 2025-26 में ग्रामीण विकास पर 2,367.64 करोड़ रुपये खर्च किए गए थे, जो 2024-25 के मुकाबले दोगुने थे। वर्ष 2017-22 के दौरान पांच वर्षों में गांवों के विकास पर 1,883 करोड़ रुपये खर्च किए गए थे, जबकि राज्य सरकार ने इस नेक कार्य के लिए पिछले चार वर्षों में 3,847 करोड़ रुपये खर्च किए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा, पंचायत इमारतों, लाइब्रेरियों, आंगनवाड़ी केंद्रों, खेल मैदानों, गलियों, नालियों और अन्य विकास कार्यों पर 1,030.94 करोड़ रुपये खर्च किए गए थे। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, पीने के पानी, स्वच्छता, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और अन्य जरूरी सेवाओं पर 1,336.70 करोड़ रुपये खर्च किए गए थे और यह फंड जिला परिषदों, पंचायत समितियों और पंचायतों के माध्यम से जारी किए गए थे।

उन्होंने आगे कहा, पंजाब सरकार ने गांवों में शामलात जमीनों को लीज पर देकर आय में वृद्धि की है। पंचायती जमीनों से अवैध कब्जे हटाए गए हैं, जिससे राज्य का राजस्व बढ़ा है। चार वर्षों में राज्य सरकार ने शामलात जमीन को लीज पर देकर 1,842.78 करोड़ रुपये कमाए हैं। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, वर्ष 2025-26 में पिछले साल के मुकाबले राजस्व 50.75 करोड़ रुपये बढ़ा है। लगभग 1.35 लाख एकड़ जमीन लीज पर दी गई, जिससे 520.54 करोड़ रुपये का राजस्व आया, जबकि 2024-25 में 469.79 करोड़ रुपये आए थे। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, नौजवानों की असीम ऊर्जा को सकारात्मक दिशा देने के लिए लगभग 3,000 ग्रामीण खेल मैदान विकसित किए जा रहे हैं और इस पर 1,166 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं। ये मैदान 6,500 एकड़ क्षेत्र में फैले होंगे, जिनके लिए 3,148 स्थानों की पहचान की गई है।

कांग्रेस असम में सत्ता में आई तो घुसपैठियों को संरक्षण देने वाला कानून लाएगी: नरेन्द्र मोदी

असम में चुनाव रैली के दौरान प्रधानमंत्री ने किया दावा

एजेंसी (हि.स.)

बिस्वनाथ

भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बुधवार को यहां एक चुनावी जनसभा में कांग्रेस पर तीखा हमला बोला और आरोप लगाया कि यदि कांग्रेस सत्ता में आती है तो वह घुसपैठियों को संरक्षण देने के लिए कानून बनाएगी, जिसे भाजपा और उसके सहयोगी कभी लागू नहीं होने देंगे।

प्रधानमंत्री ने असम के बिस्वनाथ जिले में अपनी दूसरी रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर विकास विरोधी, भ्रष्टाचार की जननी और राज्य की पहचान, सुरक्षा तथा सांस्कृतिक विरासत से खिलवाड़ करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने सत्ता के लिए असमिया अस्मिता को दांव पर लगाया और घुसपैठियों को मुख्यधारा में शामिल कर राज्य को नुकसान पहुंचाया।

मोदी ने कहा, पूरा देश जानता है कि कांग्रेस विकास विरोधी है और आजाद भारत में भ्रष्टाचार की जननी बन चुकी है, लेकिन असम में कांग्रेस ने ऐसे पाप किए हैं, जिनकी कीमत यहां की जनता ने चुकाई है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने वोट बैंक की राजनीति के तहत अवैध कब्जों को बढ़ावा दिया, जिससे लाखों बीघा जमीन पर अतिक्रमण हो गया।

प्रधानमंत्री ने कहा कि भाजपा सरकार ने इन अवैध कब्जों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए हजारों बीघा जमीन मुक्त कराई है और राज्य की विरासत एवं पारिस्थितिकी को पुनर्स्थापित किया है। उन्होंने लाओखोवा और बुरहाचापोरी अभयारण्यों का जिक्र करते हुए कहा कि एक समय यहां से गैंडे गायब हो गए थे, लेकिन अब उनके संरक्षण के प्रयासों से वे वापस लौट रहे हैं।

मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस का सबसे बड़ा पाप घुसपैठियों को संरक्षण देना रहा है। अब वही कांग्रेस सत्ता में आने पर उन्हें बचाने के लिए कानून लाना चाहती है। उन्होंने स्पष्ट किया कि भाजपा और एनडीए इस तरह के किसी भी प्रयास को सफल नहीं होने देंगे। विक स कार्यों का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 10-11 वर्षों में असम में बुनियादी ढांचे, कनेक्टिविटी और आर्थिक गतिविधियों में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। उन्होंने कहा कि आज असम के हाई-वे पर लड़ाकू विमान उतर रहे हैं, जो राज्य की बदली हुई तस्वीर को दर्शाता है।

उन्होंने एक बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे देश की पहली अंडरवाटर ट्विन ट्यूब सड़क और रेल सुरंग बनाई जाएगी, जिस पर करीब 18,662 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और कनेक्टिविटी मजबूत होगी।

प्रधानमंत्री ने कहा कि असम कच्चे तेल के उत्पादन में नए रिकॉर्ड बना रहा है और वैश्विक संकट के बीच देश को ऊर्जा के क्षेत्र में मजबूती दे रहा है। उन्होंने कहा कि बेहतर सड़क, पुल और रेल नेटवर्क से कृषि, उद्योग और पर्यटन को बढ़ावा मिल रहा है और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा हो रहे हैं।

असम में 40 लाख लखपति दीदी बनाने का दावा

महिला सशक्तीकरण पर जोर देते हुए मोदी ने कहा कि सरकार का लक्ष्य असम में 40 लाख लखपति दीदी बनाना है। उन्होंने कहा कि पिछले वर्षों में महिलाओं की सुरक्षा, शिक्षा और आय बढ़ाने के लिए अभूतपूर्व काम हुआ है। उन्होंने बताया कि 22 लाख से अधिक परिवारों को पक्के घर दिए गए हैं और महिलाओं को घर की मालिक बनाने की दिशा में काम किया जा रहा है। भूमि अधिकारों का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि मिशन वसुंधरा के तहत 23 लाख से अधिक स्वदेशी परिवारों को जमीन का मालिकाना हक मिला है। उन्होंने इसे जनजातीय और वंचित समुदायों के लिए सुरक्षा कवच बताया और कहा कि यह सच्चा सामाजिक न्याय है। चाय बागान श्रमिकों का मुद्दा उठाते हुए मोदी ने कहा कि बिस्वनाथ की पहचान चाय बागानों से है, लेकिन कांग्रेस ने दशकों तक इन श्रमिकों की उपेक्षा की। उन्होंने कहा कि 200 साल की मेहनत और परंपरा के बावजूद चाय बागान के श्रमिकों को बुनियादी सुविधाओं से वंचित रखा गया। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर इतिहास और विरासत के प्रति उदासीनता का आरोप लगाते हुए कहा कि पार्टी ने स्वतंत्रता संग्राम के योगदान का श्रेय एक ही परिवार को देने की कोशिश की। उन्होंने असम की जनता उनके अपमान को बर्दाश्त नहीं करेगी।

जनता ने राजनीतिक कचरा हटाया तो नौ वर्षों में स्वच्छ हुआ उत्तर प्रदेश : योगी

एजेंसी (हि.स.)

लखनऊ

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ नगर निगम के बेहतर कूड़ा प्रबंधन के लिए 250 इलेक्ट्रिक एवं सीएनजी वाहनों को किया फ्लैग ऑफ

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को लखनऊ नगर निगम के बेहतर कूड़ा प्रबंधन के लिए पर्यावरण अनुकूल हरित ऊर्जा से संचालित 250 इलेक्ट्रिक एवं सीएनजी वाहनों को फ्लैग ऑफ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश की जनता ने जब राजनीतिक कचरे को हटाकर बदलाव की नींव रखी, उसी का परिणाम है कि स्वच्छता के क्षेत्र में डबल इंजन सरकार द्वारा शुरू किए गए प्रयास सफल रहे और रैंकिंग में उल्लेखनीय सुधार हुआ। मुख्यमंत्री ने दो टूक कहा कि प्रदेश में 2017 के पहले सत्ताधारी दलों को अंधेरा पसंद था, लेकिन हम सूर्य के उपासक हैं और सूर्यवंशी श्रीराम के अनुज लक्ष्मणजी के नाम पर लक्ष्मणपुरी (लखनऊ) में विकास को आगे बढ़ा रहे हैं। मुख्यमंत्री आवास पांच कालिदास मार्ग पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि नव निर्माण के नौ वर्षों में आज हमारा लखनऊ स्वच्छता रैंकिंग में देश के टॉप-3 शहरों में शामिल हुआ है। अब इस उपलब्धि को नई ऊंचाई देने के लिए हम नेट जीरो लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं, जहां कार्बन उत्सर्जन न्यूनतम हो और प्रदूषण रहित व्यवस्था विकसित हो। इसी दिशा में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा देना एक महत्वपूर्ण और सराहनीय पहल है, जो स्वच्छ और हरित भविष्य की नींव रखेगी।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की प्रेरणा से वर्ष 2017 में हमने स्ट्रीट लाइट व्यवस्था में व्यापक बदलाव किया। पहले हैलोजन की पीली लाइटें होती थीं। वह अधिक ऊर्जा खपत करती थीं। पिछली सरकारों के लिए यह व्यवस्था इसलिए सुविधाजनक थी, क्योंकि उन्हें बिजली देनी ही नहीं थी। जिनकी आदत डकैती डालना था, उनके लिए अंधेरा ठीक था। हमारी सरकार ने तय किया कि बिना भेदभाव के 24 घंटे बिजली मिले और शहर की लाइटिंग भी एक समान, बेहतर और आधुनिक हो। इसी सोच के तहत पूरे शहर को एलईडी लाइटों से दूधिया रोशनी में बदलने का कार्य किया गया।

पिछले नौ वर्षों में लखनऊ ने स्वच्छता रैंकिंग के साथ-साथ हर क्षेत्र में विकास की नई ऊंचाइयां हासिल की हैं। शहर का दायरा बढ़ा है। लोगों के जीवन स्तर में सुधार हुआ है। मेट्रो संचालन शुरू हुआ है। सड़कों के चौड़ीकरण, जल निकासी तथा बुनियादी सुविधाओं के विस्तार से कनेक्टिविटी मजबूत हुई है। आज लखनऊ डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के एक उभरते हब के रूप में भी स्थापित हो चुका है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश और केंद्र सरकार के संयुक्त प्रयासों से 17 नगर निगमों तथा नोएडा-ग्रेटर नोएडा को मिलाकर 18 नगर निकायों को सेफ सिटी के रूप में इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से जोड़ते हुए सीसीटीवी कवरेज दिया गया है। अब इन्हें सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है। सूर्यवंशी श्रीराम की पावन नगरी अयोध्या सोलर सिटी के रूप में विकसित हो गई है।

असम की वर्तमान सरकार महिलाओं की प्रगति नहीं चाहती : प्रियंका गांधी

एजेंसी (हि.स.)

डिब्रूगढ़

कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने बुधवार को असम की सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार पर तीखा हमला करते हुए आरोप लगाया कि राज्य की सरकार महिलाओं को आगे बढ़ते नहीं देखना चाहती और महिला सशक्तिकरण की योजनाएं भी जमीनी स्तर पर प्रभावी नहीं हैं।

नाजीरा के मेकिपुर पूजा मैदान में आयोजित चुनावी सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि अरुणोदय जैसी योजनाएं वास्तव में महिलाओं को कोई ठोस लाभ नहीं पहुंचा पाई हैं। उन्होंने दावा किया कि इन योजनाओं के बावजूद राज्य की महिलाएं अब भी कई समस्याओं से जूझ रही हैं।

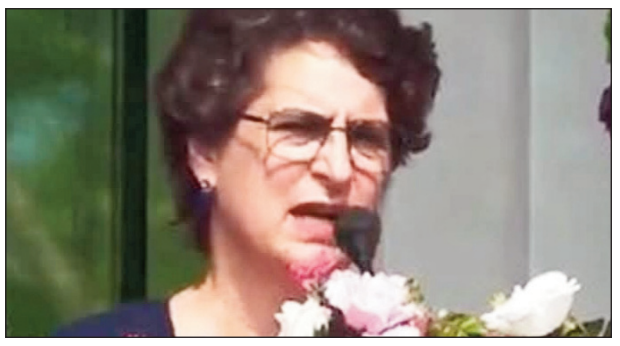

कांग्रेस उम्मीदवार देवव्रत सैकिया के समर्थन में नाजीरा में प्रचार करते हुए प्रियंका गांधी ने खोवांग में असम जातीय परिषद (एजेपी) नेता लुरिनज्योति गोगोई और टिंगखोंग में कांग्रेस उम्मीदवार बिपुल गोगोई के पक्ष में भी चुनावी सभाएं कीं। इस दौरान उन्होंने भाजपा सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए।

उन्होंने कहा कि जुबीन गर्ग को न्याय दिलाना उनकी जिम्मेदारी है और इस मुद्दे का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। चाय बागान श्रमिकों का मुद्दा उठाते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी मजदूरी आज तक नहीं बढ़ाई गई है।

कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने यह भी आरोप लगाया कि भाजपा सरकार के कार्यकाल में आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में लगातार वृद्धि हुई है और पूरे शासनकाल में भ्रष्टाचार ही देखने को मिला है। विधानसभा चुनाव से पहले उनके इन बयानों से राज्य की राजनीति और गर्मा गई है।

सिद्धगंगा मठ की सेवा देश के विकास के लिए प्रेरणा: द्रौपदी मुर्मू

एजेंसी (हि.स.)

तुमकुरु

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि सिद्धगंगा मठ ने देश के समग्र विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है और गरीब एवं अनाथ बच्चों को शिक्षा व आश्रय देकर मानवीय मूल्यों को मजबूत किया है।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बुधवार को कर्नाटक के तुमकुरु स्थित सिद्धगंगा मठ के वस्तु प्रदर्शनी मैदान में आयोजित श्री श्री शिवकुमार स्वामीजी की 119वीं जयंती समारोह को सम्बोधित कर रही थीं' उन्होंने कहा कि मठ की सेवा परंपरा पूरे देश के लिए आदर्श है। सिद्धगंगा मठ आकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हुई है। दासोह और शिक्षा के माध्यम से मठ ने गरीब बच्चों के जीवन में उजाला लाया है। दया ही धर्म का मूल है इस सिद्धांत को मठ ने वास्तविक रूप से अपनाया है।

उन्होंने कहा कि वीरशैव-लिंगायत मठों में सिद्धगंगा मठ का विशेष स्थान है और यह निरंतर सेवा कार्यों के कारण अग्रणी बना हुआ है।

इस अवसर पर सिद्धलिंग स्वामीजी ने कहा कि शिवकुमार स्वामीजी का जीवन त्याग और सेवा का प्रतीक था। गरीब और बालिकाओं को शिक्षा देना ही उनके जीवन का मुख्य उद्देश्य था। उनकी उपलब्धियां किसी चमत्कार से कम नहीं हैं। इस मौके पर कर्नाटक के राज्यपाल थावर चंद गेहलोत ने कहा कि मानव कल्याण के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाले शिवकुमार स्वामीजी की सेवा अद्वितीय है। उन्होंने सबका साथ, सबका विकास के सिद्धांत को अपने जीवन में उतारा।

केंद्रीय मंत्री प्राद जोशी ने कहा कि शिवकुमार स्वामीजी अनाथ बच्चों के लिए पिता समान थे और मानवता के प्रतीक थे। वे मनुष्य से महादेव बने।

राज्य के गृह मंत्री जी. परमेश्वर ने कहा कि सिद्धगंगा मठ केवल धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि शिक्षा और सामाजिक क्रांति का केंद्र है।ि

फल उत्पादन, प्राकृतिक खेती और क्लस्टर आधारित मॉडल से बढ़ेगी किसानों की आय: नायब सैनी

सिटी दर्पण संवाददाता

चंडीगढ़

हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने आज चंडीगढ़ में सिविल सचिवालय में कृषि एवं बागवानी विभाग के अधिकारियों की समीक्षा बैठक में किसानों की आय बढ़ाने के लिए फसल विविधीकरण, बागवानी और उच्च मूल्य वाली फल फसलों के विस्तार पर विशेष जोर दिया। उन्होंने निर्देश दिए कि प्रदेश में मिट्टी और जलवायु के अनुसार क्लस्टर आधारित खेती मॉडल विकसित किया जाए, ताकि किसानों को कम समय में अधिक उत्पादन और बेहतर मूल्य मिल सके।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पारंपरिक फसलों के साथ-साथ फल उत्पादन को बड़े स्तर पर बढ़ावा दिया जाए। उन्होंने विशेष रूप से स्ट्रॉबेरी, नींबू, अमरूद और ड्रैगन फ्रूट जैसी प्रमुख फल फसलों के लिए उपयुक्त क्षेत्रों की पहचान कर क्लस्टर विकसित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इन फलों की बाजार में मांग और लाभकारी मूल्य को देखते हुए किसानों को इनके उत्पादन, पौध उपलब्धता, प्रसंस्करण और विपणन से जोड़ा जाए, ताकि उनकी आय में उल्लेखनीय वृद्धि हो सके।

मुख्यमंत्री ने अरहर, सोयाबीन, मूंगफली, दलहन, फल फसलों तथा गन्ने के ऊतक संवर्धन आधारित उत्पादन को बढ़ावा देने के निर्देश देते हुए कहा कि हर जिले की कृषि और बागवानी क्षमता का वैज्ञानिक आकलन किया जाए। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य किसानों को बहु-फसली, बहु-उत्पाद और उच्च मूल्य आधारित खेती से जोड़कर स्थायी आय के अवसर प्रदान करना है।

बैठक में मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि नरमा, सरसों, अरहर, सोयाबीन, मूंगफली और दलहनी फसलों की नई संकर एवं अधिक उत्पादन देने वाली किस्में विकसित की जाएं। साथ ही ऐसे बीजों और पौधों के अनुसंधान को बढ़ावा दिया जाए जो ओलावृष्टि, जलवायु परिवर्तन और प्रतिकूल मौसम के प्रभाव को सहन कर सकें।

उन्होंने कहा कि कृषि विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों और पंचायत स्तर पर उपलब्ध भूमि को अनुसंधान एवं परीक्षण के लिए चिन्हित किया जाए, ताकि नई किस्मों और तकनीकों का स्थानीय परिस्थितियों में परीक्षण कर किसानों तक तेजी से पहुंचाया जा सके। विद्यार्थियों और शोध संस्थानों को भी इस अभियान से जोड़कर नवाचार को गति देने के निर्देश दिए गए।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि अन्य राज्यों के विश्वविद्यालयों में विकसित सफल संकर किस्मों, फल पौधों और आधुनिक तकनीकों का अध्ययन कर उन्हें हरियाणा की परिस्थितियों के अनुरूप अपनाया जाए, ताकि प्रदेश के किसानों को बेहतर गुणवत्ता वाली पौध और बीज उपलब्ध हो सकें।

सेम एवं लवणीय भूमि सुधार और जैव निकास

वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए राज्य सरकार ने 1,40,000 एकड़ सेम एवं लवणीय भूमि के सुधार का लक्ष्य निर्धारित किया है। इस अभियान को और प्रभावी बनाने के लिए मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि जैव निकास के तहत सफेदा (यूकेलिप्टस) के पेड़ किसानों के खेतों की मेड़ों, नहरों के किनारों तथा नालों की मेड़ों पर बड़े पैमाने पर लगाए जाएं, ताकि जलभराव वाले क्षेत्रों से अतिरिक्त पानी को प्राकृतिक रूप से कम किया जा सके। सफेदा के पेड़ अपनी गहरी जड़ों और अधिक जल अवशोषण क्षमता के कारण सेम प्रभावित भूमि के सुधार में अत्यंत उपयोगी सिद्ध होते हैं।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रदेश में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए क्लस्टर चिन्हित किए जाएं। इन क्लस्टरों में किसानों को जीवामृत, जैविक घोल, ड्रम और अन्य आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराए जाएं तथा उन्हें व्यावहारिक प्रशिक्षण भी दिया जाए। उन्होंने कहा कि गुरुकुल कुरुक्षेत्र में आचार्य देवव्रत द्वारा अपनाई जा रही प्राकृतिक खेती पद्धति को आधार बनाकर इसे लागू किया जाए, ताकि अधिक से अधिक किसान कम लागत और टिकाऊ खेती से जुड़ सकें। मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिए कि जिन क्लस्टरों में किसान प्राकृतिक खेती को अपनाते हैं और उसमें उत्पादकता कम होती है, तो ऐसे क्लस्टर वाले किसानों के नुकसान की भरपाई सरकार द्वारा की जाए। किसानों को आर्थिक सहायता और तकनीकी मार्गदर्शन देकर उनका विश्वास मजबूत किया जाए, ताकि प्राकृतिक खेती को अभियान रूप में आगे बढ़ाकर इसे जनआंदोलन बनाया जा सके।

बैठक में मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव श्री राजेश खुल्लर, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री विजेंद्र कुमार, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव डॉ. साकेत कुमार, विभाग के महानिदेशक श्री राजनारायण कौशिक, मुख्यमंत्री के ओएसडी श्री वीरेंद्र बढ़खालसा सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

हिमाचल प्रदेश में एंट्री टैक्स पर विवाद: सरकार ने घटाईं दरें, सीमा पर जत्थेबंदियों का उग्र प्रदर्शन

निजी वाहनों और स्थानीय टैक्सियों को मिली बड़ी राहत

एजेंसी (हि.स.)
शिमला

- अधिसूचना जारी
- बिलासपुर सीमा पर पंजाब के संगठनों ने रोका रास्ता

पंजाब और हरियाणा की ओर से बढ़ते विरोध और सीमावर्ती इलाकों में तनाव की स्थिति के बीच हिमाचल प्रदेश सरकार ने एंट्री टैक्स की दरों में संशोधन करते हुए राहत देने का फैसला किया है। मंगलवार देर शाम जारी सरकार की नई अधिसूचना के अनुसार बाहरी राज्यों से आने वाली पांच से 12 सीट तक की निजी गाड़ियों पर प्रवेश शुल्क घटाकर 100 रुपये कर दिया गया है। पहले इन श्रेणियों की गाड़ियों पर शुल्क बढ़ाकर 130 रुपये किया गया था, जिसे एक अप्रैल से लागू किया जाना था, लेकिन विरोध के बाद सरकार ने इसमें बदलाव किया।

राज्य कर एवं आबकारी विभाग की ओर से जारी संशोधित अधिसूचना में बताया गया है कि टोल नीति 2026झ्र27 के तहत कुछ श्रेणियों के लिए राहत के प्रावधान जोड़े गए हैं। सरकार ने स्पष्ट किया है कि पांच से 12 सीट क्षमता तक की निजी गाड़ियों के लिए अब 24 घंटे का प्रवेश शुल्क 100 रुपये ही लिया जाएगा। इसे सरकार का विवाद के बीच एक महत्वपूर्ण संशोधन माना जा रहा है, जिससे सीमावर्ती क्षेत्रों में तनाव कम करने की कोशिश की गई है। नई अधिसूचना के अनुसार हिमाचल प्रदेश में पंजीकृत हल्के वाहनों को भी राहत दी गई है। पहले केवल पांच सीट तक की टैक्सियों को प्रवेश शुल्क से छूट थी, लेकिन अब 12 सीट तक की हिमाचल नंबर वाली टैक्सियों को भी एंट्री टैक्स से पूरी तरह छूट दे दी गई है।

इससे सीमावर्ती इलाकों में चलने वाले स्थानीय टैक्सी चालकों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। सरकार ने टोल बैरियर के आसपास रहने वाले लोगों के लिए भी नियम सरल किए हैं। अब टोल बैरियर के पांच किलोमीटर के दायरे में रहने वाले हिमाचल और पड़ोसी राज्यों के लोगों के निजी वाहनों के लिए रियायती पास बनाए जाएंगे। पहले यह सुविधा केवल हिमाचल के निवासियों तक सीमित थी। नई व्यवस्था के तहत संबंधित एसडीएम या तहसीलदार द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र के आधार पर टोकन सुविधा का लाभ मिलेगा। सरकार ने कहा है कि इस कदम से सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को रोजमर्रा की आवाजाही में राहत मिलेगी। प्रदेश में कुल 55 टोल बैरियरों पर 24 घंटे के आधार पर प्रवेश शुल्क लिया जाता है। इनमें से सात टोल बैरियरों को फास्टैग सुविधा से जोड़ा गया है। सरकार का कहना है कि टोल नीति 2026-27 में स्थानीय लोगों और हल्के व्यावसायिक वाहनों को राहत देने के उद्देश्य से कई नियमों को आसान बनाया गया है। हालांकि भारी वाहनों की अधिकांश श्रेणियों में शुल्क पहले जैसा ही रखा गया है, जबकि कुछ श्रेणियों में मामूली बढ़ोतरी की गई है। इधर एंट्री टैक्स को लेकर विवाद पूरी तरह शांत नहीं हुआ है। बिलासपुर जिले में हिमाचल-पंजाब सीमा पर स्थित गारमोडा टोल प्लाजा के पास बुधवार सुबह पंजाब की विभिन्न जत्थेबंदियों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए वाहनों की एंट्री रोक दी। इस प्रदर्शन में किसान यूनियन, टैक्सी यूनियन और ट्रक यूनियन सहित कई संगठन शामिल रहे। प्रदर्शनकारियों का आरोप था कि जब उन्होंने सीमा पार की तो उनसे बढ़ी हुई दरों के अनुसार ही शुल्क वसूला गया, जिससे उनमें नाराजगी और बढ़ गई

प्रदर्शन कर रहे संगठनों के नेताओं ने कहा कि सरकार ने पहले दरें बढ़ाईं और बाद में बदलाव किया, जिससे भ्रम की स्थिति बनी। उनका कहना था कि इस फैसले से सीमावर्ती क्षेत्रों के लोगों और कारोबार पर असर पड़ रहा है। वहीं दूसरी ओर पर्यटकों और श्रद्धालुओं ने वाहनों को रोकने का विरोध किया और कहा कि आम लोगों को परेशान करने के बजाय इस मुद्दे को सरकार के स्तर पर उठाया जाना चाहिए।

शिमला के टूटू क्षेत्र में एक किलो से अधिक चरस के साथ कुल्लू के दो तस्कर गिरफ्तार

- गुप्त सूचना के आधार पर बालूगंज पुलिस ने बिछाया जाल, कार से बरामद हुई नशीली खेप एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज

एजेंसी (हि.स.)
शिमला

शिमला के टूटू क्षेत्र में चरस की डिलीवरी देने आए कुल्लू के दो युवकों को जिला शिमला पुलिस ने करीब 1.055 किलोग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है और उन्हें अदालत में पेश करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

पुलिस के अनुसार 31 मार्च की शाम थाना बालूगंज की पुलिस टीम नियमित गश्त पर थी। इसी दौरान पुलिस को विश्वसनीय गुप्त सूचना मिली कि कुल्लू जिले के दो युवक एक कार में चरस की डिलीवरी देने के लिए टूटू क्षेत्र में पहुंचे हैं। सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए बताए गए स्थान पर पहुंचकर संदिग्ध वाहन को रोककर जांच की। जांच के दौरान वाहन में कमलेश कुमार (35 वर्ष) और इन्द्रजीत (28 वर्ष), दोनों निवासी गांव मशाडा, डाकघर नगर, तहसील और जिला कुल्लू मौजूद पाए गए। पुलिस ने स्वतंत्र गवाहों की मौजूदगी में नियमानुसार वाहन की तलाशी ली। तलाशी के दौरान वाहन से एक कैरी बैग बरामद हुआ, जिसमें अलग-अलग पाउच में कुल 1.055 किलोग्राम चरस बरामद की गई।

बरामदगी के बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया। इस संबंध में थाना बालूगंज में एनडीपीएस एक्ट की धारा 20 और 29 के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस का कहना है कि आरोपियों से पूछताछ की जा रही है और यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि नशे की यह खेप कहां से लाई गई थी और इसे आगे किसे सप्लाई किया जाना था। पुलिस के अनुसार मामले की सभी पहलुओं से गहन जांच की जा रही है, जिससे इस तस्करी से जुड़े संभावित नेटवर्क का भी पता लगाया जा सके।

एसएसपी शिमला गौरव सिंह ने कहा है कि नशा तस्करी के खिलाफ अभियान आगे भी सख्ती के साथ जारी रहेगा।

गांदरबल में रातभर चली मुठभेड़ एक आतंकवादी मारा गया

एजेंसी (हि.स.)
श्रीनगर

सेना ने बुधवार को बताया कि जम्मू-कश्मीर के गांदरबल जिले में रात भर चली मुठभेड़ में एक आतंकवादी मारा गया है। क्षेत्र में संदिग्ध गतिविधियों की सूचना मिलने पर सुरक्षाबलों ने मंगलवार रात गांदरबल जिले के अरहामा इलाके में घेराबंदी और तलाशी अभियान शुरू किया।

श्रीनगर स्थित चिनार कोर ने एक्स पोस्ट में बताया कि विशिष्ट खुफिया जानकारी के आधार पर सेना और जम्मू-कश्मीर पुलिस ने गांदरबल के अरहामा क्षेत्र में संयुक्त तलाशी अभियान चलाया। सेना ने कहा कि तलाशी के दौरान सतर्क सैनिकों ने संदिग्ध गतिविधि देखी। चुनौती मिलने पर आतंकवादियों ने गोलीबारी शुरू कर दी और हमारे सैनिकों ने जवाबी कार्रवाई की। सेना ने लिखा कि रुक-रुक कर हो रही गोलीबारी के बीच घेराबंदी को रणनीतिक रूप से पुनर्गठित किया गया और सैनिकों ने सुनियोजित जवाबी कार्रवाई करते हुए एक आतंकवादी को मार गिराया। अधिकारियों ने बताया कि आतंकवाद विरोधी अभियान जारी है।

विधायकों की चुनिंदा सुरक्षा लोकतंत्र का मजाक है: सुरिंदर कुमार चौधरी

एजेंसी (हि.स.)
जम्मू

जम्मू-कश्मीर के उपमुख्यमंत्री सुरिंदर कुमार चौधरी ने बुधवार को विधायकों की सुरक्षा वापस लेने और चुनिंदा विधायकों को सुरक्षा आवंटित करने के पीछे के तर्क पर सवाल उठाते हुए कहा कि इस तरह की कार्रवाई जमीनी स्थिति के बारे में भ्रम पैदा करती है और लोकतांत्रिक सिद्धांतों को कमजोर करती है।

चौधरी ने विधायकों की सुरक्षा वापस लेने के संबंध में पूछे गए सवालों का जवाब दिया और पुलिस महानिदेशक से स्पष्टीकरण मांगा। उन्होंने विधानसभा के बाहर पत्रकारों से कहा कि महानिदेशक महोदय से पूछिए। एक तरफ आप मंत्रियों की सुरक्षा वापस ले रहे हैं तो दूसरी तरफ आप कमजोर विधायकों की सुरक्षा में कटौती कर रहे हैं। मेरी अपनी सुरक्षा भी कम कर दी गई है। इसलिए कृपया महानिदेशक महोदय से पूछिए। उन्होंने क्षेत्र में सामान्य स्थिति के दावों पर सवाल उठाते हुए कहा कि मुठभेड़ें अभी भी हो रही हैं। उन्होंने पूछा कि अगर स्थिति सामान्य है, तो ये मुठभेड़ें क्यों हो रही हैं। अगर उग्रवाद नहीं है, तो ये मुठभेड़ें किस बारे में हैं। अगर मुठभेड़ें हो रही हैं तो सुरक्षा का क्या मुद्दा है। पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला पर हाल ही में हुए हमले का जिक्र करते हुए चौधरी ने कहा कि जमीनी हालात पूर्ण सामान्यता के दावों के विपरीत हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनिंदा प्रतिनिधियों को मनमानी सुरक्षा प्रदान करना लोकतंत्र का मजाक उड़ाने जैसा है। हालांकि, चौधरी ने विश्वास जताया कि उपराज्यपाल मनोज सिन्हा इस मामले में व्यक्तिगत रूप से हस्तक्षेप करेंगे। उन्होंने कहा कि चूंकि पुलिस का प्रभार उपराज्यपाल के पास है इसलिए मुझे विश्वास है कि सदन में उठाए गए मुद्दों का समाधान वे स्वयं करेंगे। वे हस्तक्षेप करेंगे और खतरे की आशंका के आधार पर सुरक्षा का उचित आवंटन सुनिश्चित करेंगे झ्र जिन्हें वास्तव में सुरक्षा की आवश्यकता है, उन्हें तदनुसार सुरक्षा मिलेगी।

इसके अतिरिक्त उपमुख्यमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि मौजूदा सुरक्षा व्यवस्था को यथावत नहीं रखा जा सकता। उन्होंने जोर देकर कहा कि सुरक्षा सख्ती से खतरे के आकलन के आधार पर ही प्रदान की जानी चाहिए। व्यापक सुरक्षा परिदृश्य पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि जम्मू और कश्मीर चुनौतियों का सामना कर रहा है और जोर देकर कहा कि यदि स्थिति वास्तव में सामान्य है तो राज्य का दर्जा बहाल किया जाना चाहिए।

सरकार ने माना जम्मू-कश्मीर के कई प्रमुख पर्यटन स्थलों पर अभी भी अवैध निर्माण

जम्मू। सरकार ने कहा कि पिछले तीन वर्षों में पूरे जम्मू और कश्मीर में पर्यटन विकास प्राधिकरणों ने 800 से अधिक भवन निर्माण की अनुमति दी है, जबकि कई प्रमुख पर्यटन स्थलों पर अवैध निर्माण अभी भी जारी है। विधायक वहीद-उर-रहमान पारा के प्रश्न के जवाब में पर्यटन मंत्री ने कहा कि 2023 और 2026 के बीच कुल 807 निर्माण अनुमतियां जारी की गईं। 2023-24 में यह संख्या 245 थी, 2024-25 में घटकर 147 हो गई और 2025-26 में तेजी से बढ़कर 415 हो गई। स्वीकृतियों में सबसे अधिक 544 आवासीय मकानों के लिए हैं। इसके बाद 121 वाणिज्यिक भवनों के लिए और 26 होटलों, 14 झोपड़ियों, दो गेस्ट हाउसों को भी निर्माण की अनुमति दी गई। सरकार ने प्रवर्तन कार्रवाई के साथ पर्यटक केंद्रों में बड़ी संख्या में अवैध और अनधिकृत निमार्णों को भी चिह्नित किया है। गुलमर्ग में 21 अवैध संरचनाओं की पहचान की गई, जिनमें 20 को सील कर दिया गया और एक को ध्वस्त कर दिया गया। पहलगाम में ऐसे 28 निमार्णों की सूचना मिली है, जिनमें से तेरह को सील कर दिया गया है और शेष मामलों में कार्रवाई जारी है। पटनीटॉप में 15 अवैध संरचनाओं को ध्वस्त कर दिया गया और कई अन्य को प्रारंभिक चरण में ही रोक दिया गया।

संक्षिप्त-समाचार

उपराज्यपाल सिन्हा ने पांच निरीक्षकों को उप पुलिस अधीक्षक के पद पर पदोन्नत करने का दिया आदेश

जम्मू। जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज पांच निरीक्षकों (मंत्रालयी) को तत्काल प्रभाव से पुलिस उप अधीक्षक (मंत्रालयी) के पद पर पदोन्नत करने का आदेश दिया। सरकारी आदेश संख्या 187-गृह, 2026 के अनुसार निरीक्षकों (मंत्रालयी) को वेतनमान में पुलिस उप अधीक्षक (मंत्रालयी) के पद पर तत्काल प्रभाव से पदोन्नत करने की स्वीकृति दी जाती है। पदोन्नत अधिकारियों में फिदा हुसैन शेख, फारूक अहमद नाइकू, मोहम्मद फारूक मीर, मंजूर हुसैन और अब्दुल राशिद मीर शामिल हैं। आदेश में कहा गया है कि पदोन्नतियां वेतन स्तर-8 में की गई हैं और किसी भी सक्षम न्यायालय में लंबित रिट याचिकाओं के परिणाम के अधीन होंगी।

एनएचएम कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर श्रीनगर में 48 घंटे का धरना किया शुरू

श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत काम करने वाले सैकड़ों कर्मचारियों ने बुधवार को विरोध प्रदर्शन किया और अपनी लंबे समय से लंबित मांगों पर दबाव बनाने के लिए 48 घंटे के धरने का आह्वान किया। प्रदर्शनकारियों ने अन्य राज्यों के अनुरूप तत्काल वेतन संशोधन, सुरक्षित नौकरी नीति और ईपीएफ, ईएसआई, बीमा और सेवानिवृत्ति के बाद के समर्थन जैसे सामाजिक सुरक्षा लाभों के कार्यान्वयन सहित अपनी मांगों को दोहराया। उन्होंने कहा कि प्रशासन के बार-बार आश्वासन के बावजूद कोई ठोस प्रगति नहीं हुई जिससे उन्हें सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर होना पड़ा। एनएचएम कर्मचारी स्वास्थ्य सेवा वितरण में सबसे आगे रहे हैं खासकर आपात स्थिति के दौरान लेकिन वेतन और नौकरी की सुरक्षा पर अनिश्चितता का सामना करना पड़ रहा है। प्रदर्शनकारी कर्मचारियों ने चेतावनी दी कि उनकी चिंताओं को दूर करने में विफलता के कारण आने वाले दिनों में विरोध प्रदर्शन बढ़ सकता है हालांकि चल रहा धरना 48 घंटे तक जारी रहने वाला है।

विदेशी नौकरी घोटाला मामले में श्रीनगर के सीजेएम कोर्ट में चार्जशीट दाखिल

श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर की विशेष अपराध शाखा ने श्रीनगर के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट समक्ष विदेशी नौकरी घोटाला मामले में एक आरोपित के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया है। विशेष अपराध शाखा के मुताबिक जिला डोडा तेंदाला, तहसील चिलिपिंगल निवासी फरहत अब्बास मलिक के खिलाफ आईपीसी की धारा 420 और 201 के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी। यह मामला एक ऐसे व्यक्ति की शिकायत के बाद सामने आया, जो कोरोना काल के दौरान अपना रोजगार खोने के बाद विदेश में नौकरी की तलाश कर रहा था। इस दौरान वह 'फ्लाई हाई बिजनेस कंसल्टेंट' नामक संस्था के संपर्क में आया, जिसे फरहत अब्बास मलिक संचालित कर रहा था। उसने विदेश में अच्छी तनख्वाह वाली नौकरी दिलाने का वादा किया और इस बहाने शिकायतकर्ता को अच्छी खासी रकम देने और अपने मूल दस्तावेज जमा करने के लिए मना लिया। जांच के दौरान यह स्थापित हुआ कि आरोपित ने विदेश में रोजगार का झूठा वादा करके शिकायतकर्ता को धोखा दिया था। उसने न तो नौकरी लगवाई और न ही पैसे लौटाए। साक्ष्य से यह भी पता चला कि आरोपित ने जानबूझकर गलत वित्तीय लाभ के लिए शिकायतकर्ता को गुमराह किया था। पूछताछ के दौरान आरोपित ने विदेश में नौकरी की व्यवस्था करने के वादे पर शिकायतकर्ता से पैसे लेने की बात स्वीकार की, लेकिन प्रतिबद्धता को पूरा करने में विफल रहा। उसने यह भी खुलासा किया कि शिकायतकर्ता का मूल पासपोर्ट दस्तावेज खो गया है। गिरफ्तारी के बाद न्यायालय ने उसकी जमानत खारिज कर दी थी और वह वर्तमान में सेंट्रल जेल श्रीनगर में बंद हैं।

विधायकों ने विधानसभा में नौकरशाहों की अनुपस्थिति का किया विरोध

जम्मू। पार्टी लाइन से ऊपर उठकर विधायकों ने बुधवार को विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान नौकरशाहों की अनुपस्थिति पर चिंता व्यक्त की। जैसे ही प्रश्नकाल समाप्त होने वाला था एनसी विधायक नाजी गुरेजी ने आरोप लगाया कि नौकरशाह सदन को हल्के में ले रहे थे। विधायक ने अधिकारियों की गैलरी की ओर इशारा करते हुए कहा कि आप गैलरी की ओर देखें। इस सदन को हल्के में लिया जा रहा है। मैं 22 साल से इस सदन का सदस्य हूं। यह गैलरी खचाखच भरी रहती थी। प्रश्नकाल के दौरान मुख्य सचिव मौजूद रहते थे। आयुक्त सचिव मौजूद रहते थे। उन्हें लगता है कि यहां बेकार लोग (विधायक) बैठे हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री से नौकरशाहों के खिलाफ कार्रवाई करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि उन्हें सदन में आना चाहिए। मुख्यमंत्री को इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। वे सदन में क्यों नहीं आ रहे हैं क्या वे सोचते हैं कि वे मुख्यमंत्री और सदन से ऊपर हैं, वे अपने बारे में क्या सोचते हैं वे सरकारी कर्मचारी है और हम जन प्रतिनिधि हैं। गुरेजी को सभी भाजपा विधायकों का समर्थन प्राप्त था जो नौकरशाहों की अनुपस्थिति के विरोध में खड़े हुए थे। जल्द ही एनसी, पीडीपी, कांग्रेस, पीसी और निर्दलीय विधायक भी विरोध में खड़े हो गए। इस मामले में हस्तक्षेप करते हुए स्पीकर अब्दुल रहीम राथर ने कहा कि जिस विभाग के सवाल उठाए जाने हैं उनके शीर्ष अधिकारियों को सदन में मौजूद रहना चाहिए। उन्होंने बताया हम पूरे सचिवालय को सदन में बैठने के लिए नहीं कह सकते। अधिकारियों की गैलरी में ज्यादा जगह नहीं है। इस मुद्दे को उठाते हुए भाजपा के शाम लाल शर्मा ने कहा कि नियम पुस्तिका उस विभाग के संबंधित प्रशासनिक सचिव की उपस्थिति को अनिवार्य करती है जिसके प्रश्न उठाए जाने हैं। उन्होंने सुझाव दिया कि जिस भी विभाग के अधिकारी गैलरी से अनुपस्थित हों, उसका कार्य स्थगित कर देना चाहिए। उनकी पार्टी के सहयोगी पवन गुप्ता ने भी सदन में नौकरशाहों की अनुपस्थिति पर सवाल उठाया।

जयराम ठाकुर का सुक्खू सरकार पर तीखा प्रहार, 'आरक्षण रोस्टर' पर वॉकआउट

- डीसी को दी गई 5% फेरबदल की शक्ति को बताया सत्ता का दुरुपयोग

एजेंसी (हि.स.)
शिमला

हिमाचल प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र बुधवार को राजनीतिक गहमागहमी और हंगामे की भेंट चढ़ गया। पंचायत चुनाव के आरक्षण रोस्टर में किए गए बदलावों को लेकर भाजपा विधायक दल ने नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अगुवाई में सदन के बाहर और भीतर जोरदार प्रदर्शन किया।

जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पर सीधा हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि वर्तमान सरकार को रबिना सोचे-समझे उल-जलूल फैसलेर लेने की आदत हो गई है, जिससे प्रदेश भर में सरकार की किरकिरी हो रही है। विवाद की मुख्य जड़ राज्य सरकार का वह हालिया निर्णय है, जिसमें जिला उपायुक्तों (डीसी) को आरक्षण रोस्टर में पांच प्रतिशत तक बदलाव करने की विशेष छूट दी गई है। विपक्ष इसे लोकतंत्र और पंचायती राज संस्थाओं की स्वायत्तता पर सीधा प्रहार मान रहा है। जयराम ठाकुर ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि भौगोलिक विषमताओं के नाम पर डीसी को दी गई यह शक्ति केवल कांग्रेस समर्थित कार्यकर्ताओं को लाभ पहुँचाने के लिए है। विधानसभा की कार्यवाही शुरू होते ही भाजपा विधायक रणधीर शर्मा ने नियम 67 के तहत स्थगन प्रस्ताव लाकर इस मुद्दे पर तुरंत चर्चा की मांग की। विपक्ष के भारी हंगामे और नारेबाजी के कारण विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया को सदन की कार्यवाही 20 मिनट के लिए स्थगित करनी पड़ी। जब अध्यक्ष ने स्थगन प्रस्ताव को खारिज कर दिया, तो भाजपा विधायकों ने सदन से वॉकआउट कर दिया।

जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया कि सरकार की मंशा निष्पक्ष चुनाव कराने की नहीं, बल्कि हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना कर चुनावों को टालने की है।

बीबीएन पर आर्थिक संकट: कच्चे माल और मालभाड़े में भारी उछाल से कई इकाइयां बंदी की कगार पर

- दवा उद्योगों ने रोके सार्वजनिक ऑर्डर

एजेंसी (हि.स.)
बद्दी (सोलन)

हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र बद्दी-बरोटीवाला-नालागढ़ वर्तमान में गंभीर आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा है। कच्चे माल की आसमान छूती कीमतों, मालभाड़े में भारी बढ़ोतरी और व्यावसायिक एलपीजी की कमी के कारण क्षेत्र के छोटे और मध्यम उद्योग बंदी की कगार पर पहुंच गए हैं। स्थिति इतनी विकट हो गई है कि कई उद्यमियों ने अपने प्लांट में 15-15 दिन का 'शटडाउन' घोषित कर दिया है, जबकि दवा उद्योगों ने नए ऑर्डर लेने से इनकार करना शुरू कर दिया है।

औद्योगिक क्षेत्र से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार, पैकेजिंग सामग्री से लेकर सक्रिय दवा सामग्री (अढक) तक के दामों में 30 से 50 प्रतिशत तक का उछाल आया है। प्लास्टिक दाना, जो पहले 80 रुपये प्रति किलो मिलता था, अब 190 रुपये प्रति किलो के पार पहुंच गया है। इसके परिणामस्वरूप दवाइयों की पैकिंग में इस्तेमाल होने वाली बोतलों और अन्य प्लास्टिक उत्पादों के दाम दोगुने हो गए हैं। दवा उद्योग वर्तमान में केवल सरकारी ऑर्डर्स को ही प्राथमिकता दे रहे हैं ताकि समय पर आपूर्ति न होने की स्थिति में भारी पेनल्टी से बचा जा सके।

उद्योगों के संचालन में उपयोग होने वाली आवश्यक सामग्रियों की कीमतों में अप्रत्याशित वृद्धि दर्ज की गई है। एल्यूमीनियम फॉयल की कीमत 400 रुपये से बढ़कर 550 रुपये प्रति किलो हो गई है, जबकि पीवीसी के दाम 115 रुपये से बढ़कर 170 रुपये तक पहुंच गए हैं। इसके अलावा, गत्ते की कीमतों में 40 प्रतिशत की तेजी आई है। उद्यमियों का कहना है कि इंजन ऑयल, गियर ऑयल और ग्रीस जैसे लुब्रिकेंट्स की कीमतों में भी 10 से 15 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है, जिससे मशीनों का रखरखाव और उत्पादन अब घाटे का सौदा बन गया है। लघु उद्योग भारती और विभिन्न औद्योगिक संघों ने स्थिति पर गहरी चिंता व्यक्त की है। महासचिव संजीव शर्मा के अनुसार, बाजार में व्यावसायिक एलपीजी (19 किलो का सिलेंडर) की भारी किल्लत है, जिसके कारण फैक्ट्रियों की कैंटीन चलाना भी दूभर हो गया है।

मोड़ते समय एचआरटीसी बस 100 फीट गहरी खाई में बस, चालक ने कूदकर बचाई जान

एजेंसी (हि.स.)
मंडी

हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में बुधवार सुबह हिमाचल पथ परिवहन निगम की एक बस भीषण हादसे का शिकार हो गई। मंडी डिपो की यह बस कुन्नू-कुफरी-नशधरा रूट पर बटाहर के पास मोड़ काटते समय अनियंत्रित होकर लगभग 100 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। इस दर्दनाक हादसे में बस के पूरी तरह परखच्चे उड़ गए हैं, लेकिन राहत की बात यह रही कि बस में कोई सवारी मौजूद नहीं थी और चालक ने समय रहते छलांग लगाकर अपनी जान बचा ली। जानकारी के अनुसार, हादसा सुबह करीब 6:30 बजे पेश आया जब बस मंडी के लिए रवाना होने की तैयारी में थी। बस चालक गोपाल सिंह 'बटाहर' बस ठहराव के पास वाहन को मोड़ रहा था। उस समय परिचालक जितेंद्र कुमार बस से बाहर खड़ा होकर चालक को बैक करने का इशारा दे रहा था। इसी दौरान सड़क के किनारे मौजूद दलदली मिट्टी धंसने के कारण बस का टायर फिसल गया और वाहन अनियंत्रित होकर ट्रैक से बाहर खाई में लुढ़क गया। जैसे ही चालक गोपाल सिंह को बस के फिसलने का अहसास हुआ, उन्होंने सूझबूझ दिखाते हुए तुरंत खिड़की से बाहर छलांग लगा दी। देखते ही देखते बस पहाड़ी से नीचे गिरती चली गई और गहरी खाई में जा रुकी। परिचालक जितेंद्र कुमार सुरक्षित दूरी पर खड़ा था, जिसके कारण वह भी बाल-बाल बच गया। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस और स्थानीय लोगों ने पाया कि बस का ढांचा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुका है। चूंकि बस स्टैंड से चलने की प्रक्रिया में थी, इसलिए उस समय कोई यात्री बस के भीतर सवार नहीं था, जिससे एक बड़ा जानी नुकसान टल गया। स्थानीय निवासियों का कहना है कि क्षेत्र में हाल ही में हुई बारिश के कारण सड़क किनारे की मिट्टी काफी कच्ची और दलदली हो गई थी, जो भारी वाहन का भार सहन नहीं कर सकी।

मौसम

दो दिन की राहत के बाद 3 अप्रैल से फिर बरसेंगे बादल

पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से 6 अप्रैल तक बारिश के आसार, अंधड़ और ओलावृष्टि का 'येलो अलर्ट' जारी

- मैदानी इलाकों में पारा 30 डिग्री के पार; ऊना सबसे गर्म, शिमला और मनाली में खिली धूप

एजेंसी (हि.स.)
हमीरपुर

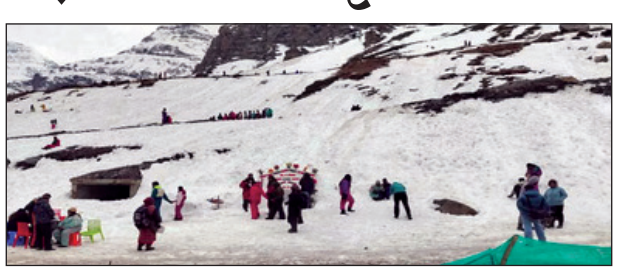

हिमाचल प्रदेश में मौसम के मिजाज में एक बार फिर बड़ा बदलाव आने वाला है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के ताजा पूवार्नुमान के अनुसार, प्रदेशवासियों को बुधवार और गुरुवार को मौसम साफ रहने से थोड़ी राहत मिलेगी, लेकिन 2 अप्रैल की रात से एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है। इसके प्रभाव से 3 से 6 अप्रैल तक पूरे प्रदेश में गरज-चमक के साथ बारिश, अंधड़ और ओलावृष्टि की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर और चंबा सहित कई जिलों के लिए 'येलो अलर्ट' जारी किया है। मंगलवार को राजधानी शिमला सहित अधिकांश क्षेत्रों में धूप खिली रही, जिससे तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। हालांकि, मंगलवार शाम को कुल्लू के सैंज में ओलावृष्टि और धर्मशाला में देर रात हल्की बारिश ने पारे में हल्की गिरावट दर्ज कराई थी।

वर्तमान में प्रदेश के मैदानी इलाकों में गर्मी का असर दिखने लगा है। ऊना 30.4 डिग्री सेल्सियस के साथ राज्य का सबसे गर्म स्थान रहा, जबकि मंडी में अधिकतम तापमान 29.2 डिग्री दर्ज किया गया। जनजातीय क्षेत्रों जैसे केलांग में पारा अभी भी 10.9 डिग्री के आसपास बना हुआ है। आगामी दो दिनों तक धूप खिलने के कारण दिन के तापमान में और वृद्धि होने का अनुमान है, जिससे लोगों को अप्रैल की शुरूआत में गर्मी का अहसास होगा।

मौसम विभाग के अनुसार, 3 अप्रैल से सक्रिय होने वाले पश्चिमी विक्षोभ के कारण तेज हवाएं (अंधड़) चलने और ओलावृष्टि होने की प्रबल संभावना है। यह स्थिति सेब के बगीचों और तैयार खड़ी फसलों के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है। किसानों और बागवानों को सलाह दी गई है कि वे मौसम की स्थिति को देखते हुए फसलों की कटाई और छिड़काव के कार्यों का प्रबंधन करें। ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में हल्की बर्फबारी की भी संभावना जताई गई है। आगामी 48 घंटों के दौरान मौसम के साफ रहने से सैलानियों के लिए शिमला, मनाली और डलहौजी की यात्रा सुखद रहेगी, लेकिन सप्ताहांत पर आने वाले पर्यटकों को भारी बारिश और ओलावृष्टि के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। प्रशासन ने स्थानीय लोगों और पर्यटकों को खराब मौसम के दौरान नदी-नालों और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में न जाने की हिदायत दी है।

दैनिक सिटी दर्पण आईना सच का

न्वोन्मेषक: स्व. कृष्णा शर्मा
स्व. गीता शर्मा
संस्थापक: स्व. सतपॉल शर्मा

स्वामी, प्रकाशक मुद्रक एवं संपादक भूपिंद्र शर्मा द्वारा इंप्रेशन्ज प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग लिमिटेड, प्लॉट नं. 22, ग्राउंड फ्लोर, फेस-2, इंडस्ट्रियल एरिया, पंचकूला-134113 (हरियाणा) पर मुद्रित एवं 801/1, सेक्टर 40ए, चंडीगढ़ से प्रकाशित-160036

सभी विवादों का केंद्र न्यायालय चंडीगढ़ होगा।

स्थानीय कार्यालय
801/1, सेक्टर-40ए, चंडीगढ़।

संपर्क: 7888450261
Email: citydarpan1@gmail.com

हरियाणा में सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने की दिशा में बड़ा कदम

एसीएस स्वास्थ्य डॉ. सुमिता मिश्रा ने राज्यव्यापी समीक्षा कर व्यापक सुधार के निर्देश किए जारी

सिटी दर्पण संवाददाता
चंडीगढ़

हरियाणा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. सुमिता मिश्रा ने हरियाणा में सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक प्रभावी, जवाबदेह और मरीजों की उपचार सेवाओं को बेहतर बनाने के उद्देश्य से कई सुधारों की शुरूआत की है।

सिविल सर्जनों और स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ राज्यस्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए डॉ. मिश्रा ने दवा प्रबंधन, बेहतर जांच सुविधाओं और अस्पतालों के सुचारु संचालन पर केंद्रित एक स्पष्ट कार्ययोजना प्रस्तुत की। उन्होंने कहा कि यह सिविल सर्जनों की जिम्मेदारी है कि प्रत्येक सोमवार को दवाओं के स्टॉक का डेटा अपडेट किया जाए और सभी स्वास्थ्य संस्थानों में आवश्यक दवाओं की उपलब्धता बिना किसी रुकावट के सुनिश्चित की जाए।

दवा आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत बनाने पर सुधार एजेंडा केंद्रित है, जिसके लिए रियल-टाइम मॉनिटरिंग और जवाबदेही सुनिश्चित की जाएगी। डॉ. मिश्रा ने निर्देश दिए कि सभी जिलों में आवश्यक दवाओं की सूची (एउ्छ) के अनुसार दवाओं की निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित की जाए, साथ ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सटीक और समयबद्ध डेटा एंट्री की जाए।

उन्होंने असंगत खपत डेटा, वास्तवित स्टॉक और पोर्टल रिकॉर्ड में अंतर तथा डेटा अपडेट में देरी जैसी समस्याओं को रेखांकित किया, जो पूवार्नुमान और खरीद प्रक्रिया को प्रभावित करती हैं। इन समस्याओं के समाधान के लिए जिलों को नियमित स्टॉक मिलान, सिस्टम वैलिडेशन जांच और मासिक स्टॉक का सत्यापन करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त, सिविल सर्जनों को समय-समय पर स्टॉक की औचक जांच करने के निर्देश भी दिए गए हैं ताकि आमजन को किसी प्रकार की असुविधा न हो। संभावित वैश्विक आपूर्ति व्यवधानों को ध्यान में रखते हुए आवश्यक दवाओं का बफर स्टॉक बनाए रखने और इस संबंध में एसओपी जारी करने के भी निर्देश दिए गए हैं।

डॉ. मिश्रा ने सिविल सर्जनों को साप्ताहिक मॉनिटरिंग करने और जिला स्तर पर समीक्षा प्रणाली स्थापित करने को कहा है, ताकि हर स्तर पर जवाबदेही सुनिश्चित हो सके। उन्होंने स्पष्ट किया कि समग्र निगरानी और अनुपालन की जिम्मेदारी सिविल सर्जनों की होगी, समय पर डेटा एंट्री और स्टॉक सत्यापन की जिम्मेदारी फार्मासिस्टों की तथा दवाओं के विवेकपूर्ण उपयोग और एउ्छ के अनुपालन की जिम्मेदारी चिकित्सा अधिकारियों की होगी। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि दवाओं की मांग, प्राप्ति और खपत से संबंधित सभी रिकॉर्ड नियमित रूप से अपडेट किए जाएं, जिससे रियल-टाइम मॉनिटरिंग और प्रभावी निर्णय संभव हो सके।

बैठक में जिला अस्पतालों, उपमंडल अस्पतालों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में मुफ्त जांच सेवाओं के विस्तार की भी समीक्षा की गई। इस बात की जानकारी दी गई कि जिलों में एकीकृत सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयोगशालाओं के संचालन से नागरिकों को किफायती और समय पर जांच सुविधाएं मिल रही हैं।

बुनियादी ढांचे के विकास को गति देने के लिए उन्होंने अस्पतालों के अपडेशन के कार्यों को तेज करने और स्वच्छता एवं हाइजीन प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। स्वास्थ्य संस्थानों में साफ-सफाई बनाए रखने के लिए सिविल सर्जन सीधे तौर पर जवाबदेह होंगे।

समीक्षा बैठक में 100-दिवसीय टीबी उन्मूलन अभियान की प्रगति की भी समीक्षा की गई, जिसमें प्रयासों को तेज करने और समयबद्ध कार्ययोजना लागू करने के निर्देश दिए गए। इसके साथ ही सिविल सर्जनों को लिंगानुपात के रुझानों पर कड़ी निगरानी रखने और हालिया सुधारों को बनाए रखने के निर्देश दिए गए। बैठक में डॉ. मिश्रा को अवगत कराया कि सभी जिलों में पीएनडीटी प्रावधानों के सख्त पालन को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है।

खाद्य नागरिक, आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग मंत्री राजेश नागर ने सोहना की अनाज मंडी का किया निरीक्षण

सिटी दर्पण संवाददाता
चंडीगढ़

हरियाणा के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री श्री राजेश नागर ने कहा कि राज्य सरकार किसानों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी के दिशा-निदेर्शों के तहत प्रदेश की सभी अनाज मंडियों में सरसों और गेहूं की खरीद प्रक्रिया को सुव्यवस्थित, पारदर्शी एवं सुचारू बनाने के लिए व्यापक तैयारियां की गई हैं। उन्होंने कहा कि मंडियों में किसानों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए आवश्यक सुविधाओं और व्यवस्थाओं को और अधिक सुदृढ़ किया गया है, ताकि उनकी उपज का समय पर और सरल तरीके से उठान सुनिश्चित किया जा सके। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के मंत्री श्री राजेश नागर बुधवार को गुरूग्राम जिला के सोहना अनाज मंडी का निरीक्षण करने उपरांत बोल रहे थे। इस दौरान उन्होंने आढ़तियों और किसानों से संवाद कर उनकी समस्याएं भी जानीं।

निरीक्षण के दौरान मंत्री ने किसानों के लिए स्थापित हेल्प डेस्क पर दी जा रही सेवाओं, एंट्री गेट व मुख्य द्वार पर बनाए गए कक्ष, आढ़तियों के पास बारदाने की उपलब्धता तथा शिकायत रजिस्टर का भी बारीकी से निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसानों से प्राप्त शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र समाधान सुनिश्चित किया जाए। श्री नागर ने मंडी में आने वाले किसानों के लिए अटल कैंटीन में उपलब्ध कराए जा रहे भोजन की व्यवस्था की भी जानकारी ली और इसे बेहतर बनाए रखने के निर्देश भी दिए।

उन्होंने बताया कि राज्य सरकार द्वारा खाद्यान्न खरीद प्रक्रिया को और अधिक सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से वर्तमान में संचालित ई-खरीद पोर्टल को अपग्रेड किया गया है, जिसमें कई नए प्रावधान जोड़े गए हैं। उन्होंने बताया कि रबी खरीद सीजन 2026-27 के दौरान मंडियों और खरीद केंद्रों में किसान द्वारा बिक्री के लिए लाई जाने वाली गेहूं की आवक के समय, संबंधित वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर सहित फोटो कैप्चर किया जाएगा, ताकि प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके।

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव प्रक्रिया को निष्पक्ष, पारदर्शी एवं विश्वसनीय बनाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं : ए. श्रीनिवास

सिटी दर्पण संवाददाता
चंडीगढ़

हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री ए. श्रीनिवास ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 15 मार्च, 2026 को असम, केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु एवं पश्चिम बंगाल की विधानसभाओं के आम चुनाव तथा 6 राज्यों में उपचुनाव की घोषणा के अनुरूप चुनाव प्रक्रिया को निष्पक्ष, पारदर्शी एवं विश्वसनीय बनाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं।

उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि ईवीएम एवं वीवीपैट मशीनों का आवंटन एक पारदर्शी एवं निष्पक्ष प्रक्रिया के तहत दो चरणों में रैंडमाइजेशन के माध्यम से किया जा रहा है। चुनाव प्रक्रिया के दौरान पहले चरण में जिला स्तर के गोदामों से विधानसभा क्षेत्रों को मशीनों का आवंटन किया जाता है, जबकि दूसरे चरण में विधानसभा क्षेत्र स्तर से मतदान केंद्रों को मशीनें आवंटित की जाती हैं। उन्होंने आगे बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निदेर्शानुसार पहला रैंडमाइजेशन जिला निर्वाचन अधिकारियों द्वारा ईवीएम मैनेजमेंट सिस्टम के माध्यम से राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में सम्पन्न किया गया। इस प्रक्रिया के तहत लगभग 8.85 लाख ईवीएम यूनिट्स (बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट एवं वीवीपैट) चुनावों में उपयोग के लिए आवंटित की गईं। श्री श्रीनिवास ने बताया कि दूसरा रैंडमाइजेशन रिटर्निंग अधिकारियों द्वारा ईवीएम मैनेजमेंट सिस्टम के माध्यम से असम, केरल एवं पुडुचेरी में होने वाले विधानसभा चुनावों तथा गोवा, कर्नाटक, नागालैंड एवं त्रिपुरा में 9 अप्रैल, 2026 को होने वाले उपचुनावों के लिए सम्पन्न किया जा चुका है। यह प्रक्रिया भी सभी प्रत्याशियों की उपस्थिति में पूर्ण पारदर्शिता के साथ संपन्न की गई। उन्होंने कहा कि पहले एवं दूसरे रैंडमाइजेशन के तहत आवंटित ईवीएम एवं वीवीपैट की सूची सभी प्रत्याशियों के साथ साझा की जाएगी।

गेहूं खरीद कार्य में किसानों और व्यापारियों को अगर दिक्कत आई तो तय होगी अधिकारियों की जिम्मेदारी:जी अनुपमा

सिटी दर्पण संवाददाता
शाहाबाद

अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं प्रशासनिक सचिव जी अनुपमा ने कहा कि प्रदेश सरकार के आदेशानुसार सभी मंडियों में एक अप्रैल से गेहूं खरीद कार्य शुरू किया गया है। इस सीजन के दौरान किसानों व व्यापारियों को किसी प्रकार की दिक्कत और समस्या नहीं आने दी जाएगी। अगर किसी मंडी में किसानों को दिक्कत आई तो संबंधित अधिकारी के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। इस सीजन में पहली बार बायोमेट्रिक मशीन के माध्यम से खरीद कार्य को आगे बढ़ाया जाएगा। इससे किसानों को फायदा होगा और खरीद कार्य में पारदर्शिता नजर आएगी।

एसीएस जी अनुपमा बुधवार को शाहाबाद अनाज मंडी में गेहूं खरीद कार्य की व्यवस्थाओं का निरीक्षण कर रही थी। इससे पहले एसीएस जी अनुपमा व उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा ने शाहाबाद अनाज मंडी में सबसे पहले गेट पास व्यवस्था, बायोमेट्रिक प्रणाली का जायजा लिया और संबंधित कर्मचारी से बारीकी से किसानों की फसल के संबंध में होने वाली बायोमेट्रिक प्रक्रिया के बारे में जानकारी हासिल की। इसके उपरांत एसीएस ने अनाज मंडी में गेहूं लेकर पहुंचे किसान से बायोमेट्रिक मशीन, घर बैठे गेट पास की व्यवस्था के बारे में फीडबैक ली। इसके साथ ही गेहूं की नमी को भी चैक किया।

उन्होंने व्यापारियों से भी बातचीत की। इस बातचीत के दौरान मंडियों में बारदाने की तुरंत उपलब्धता और उठान कार्य को लेकर पिछले साल आई परेशानियों के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए कहा कि इस बार पर्याप्त मात्रा में बारदाना समय रहते उपलब्ध करवाना होगा। इसके साथ ही लिफ्टिंग का कार्य भी साथ के साथ करना होगा। उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा ने जिला खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की रिपोर्ट के अनुसार कहा कि संबंधित एजेंसी के माध्यम से जल्द से जल्द पर्याप्त मात्रा में बारदाना उपलब्ध करवाया जाएगा, ताकि किसानों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। एसीएस ने मार्केटिंग बोर्ड के अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि पिछली फसल को जल्द से जल्द उठवाया जाएगा, ताकि गेहूं खरीद कार्य में किसानों व व्यापारियों को कोई दिक्कत ना आए। इस उपमंडल की अनाज मंडियों व खरीद केंद्रों पर पीने का पानी, सफाई व्यवस्था, बिजली, शौचालय सहित बारदाने की व्यवस्था दुरुस्त होनी चाहिए। अगर दोबारा चेकिंग के दौरान कोई कमी पाई गई तो जांच के दौरान दोषी पाए जाने वाले अधिकारी के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

इस मौके पर मार्केट कमेटी के चेयरमैन कर्णराज तुर, वाइस चेयरमैन त्रिलोचन हाण्डा, मंडी प्रधान धनपत अग्रवाल, सब्जी मंडी प्रधान काला आहूजा, मार्केट कमेटी सचिव कृष्ण कुमार मलिक, पवन गुप्ता सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे।

संक्षिप्त-समाचार

चंडीगढ़ प्रशासन ने मांगा प्रतिनियुक्ति हेतु एचसीएस अधिकारियों का पैनल

चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने चंडीगढ़ प्रशासन में प्रतिनियुक्ति पर कार्य करने के इच्छुक हरियाणा सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) के अधिकारियों से सहमति मांगी है। मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी द्वारा इस संबंध में एक पत्र जारी किया गया है। जारी पत्र के अनुसार चंडीगढ़ प्रशासन ने हरियाणा सरकार से एचसीएस (कार्यकारी शाखा) के ऐसे अधिकारियों का पैनल भेजने का अनुरोध किया है, जिनकी सेवा में कम से कम पांच वर्ष की वरिष्ठता हो और जो चंडीगढ़ प्रशासन में प्रतिनियुक्ति पर कार्य करने के इच्छुक हों। इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा उपयुक्त वरिष्ठता वाले तीन एचसीएस अधिकारियों का पैनल तैयार किया जाना है। इसके लिए संबंधित अधिकारियों से अपनी सहमति भेजने को कहा गया है। इच्छुक अधिकारी पत्र जारी होने की तिथि से 10 कार्य दिवस के भीतर अपनी सहमति विभाग को ई-मेल २४स्त्ररी१ष्ठ्री२२.२ङ्क@१८.ङ्क५.ल्ल के माध्यम से भेज सकते हैं।

हरियाणा सरकार ने लगाए तीन जिलों के प्रभारी अधिकारी

चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने यमुनानगर, हांसी और रेवाड़ी जिलों के प्रभारी अधिकारी नियुक्त किए हैं। मुख्य सचिव कार्यालय द्वारा जारी आदेशानुसार, 'सभी के लिए आवास' विभाग के आयुक्त एवं सचिव मोहम्मद शाइन को यमुनानगर; खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के आयुक्त एवं सचिव श्री जे. गणेशन को हांसी और शहरी स्थानीय निकाय विभाग के आयुक्त एवं सचिव श्री अशोक कुमार मीणा को रेवाड़ी जिले का प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। प्रभारी अधिकारी को तिमाही रिपोर्ट मॉनिटरिंग एवं कोऑर्डिनेशन सेल को भेजनी होगी, जिसमें 25 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं की प्रगति, अपराधों व जघन्य अपराधों की स्थिति, सतर्कता संबंधी मामले, सेवा अधिकार अधिनियम के अंतर्गत सेवाओं की डिलीवरी व्यवस्था तथा स्वास्थ्य, शिक्षा व सामाजिक क्षेत्रों की कार्यप्रणाली की समीक्षा शामिल होगी। इसके अतिरिक्त, वे सांसदों, विधायकों एवं अन्य जनप्रतिनिधियों से जिला उपायुक्त एवं पुलिस अधीक्षक की उपस्थिति में संवाद करेंगे तथा समीक्षा के दौरान स्वास्थ्य एवं शिक्षा विभाग से संबंधित किसी एक महत्वपूर्ण स्थल का निरीक्षण भी करेंगे।

चालू वर्ष के लिए सूरजमुखी के बीज का एमएसपी है 7721 रुपये प्रति क्विंटल

चंडीगढ़। हैफेड ने 1 अप्रैल, 2026 को एक प्रमुख राष्ट्रीय हिंदी दैनिक में प्रकाशित उस समाचार को गलत, भ्रामक और तथ्यों से परे बताया है, जिसमें हैफेड द्वारा जारी खरीद संबंधी निदेर्शों में सूरजमुखी के बीज के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) का गलत उल्लेख किया गया था। आज यहां यह बताते हुए हैफेड के एक प्रवक्ता ने स्पष्ट किया कि खरीद संबंधी निर्देश हैफेड द्वारा दिनांक 19 मार्च 2026 के पत्र के माध्यम से जारी किए गए थे, जिसमें सभी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) का सही उल्लेख किया गया था। हालांकि, एक अनजाने लिपिकीय त्रुटि के कारण सूरजमुखी के बीज का एमएसपी चालू वर्ष के एमएसपी के बजाय गलती से 6540 रुपये प्रति क्विंटल दर्ज कर दिया गया था। उक्त त्रुटि को बाद में ध्यान में लाया गया और सुधारा गया। संशोधित निर्देश पूर्व निदेर्शों के स्थान पर 29 मार्च 2026 को ही जारी कर दिए गए थे, जिसमें चालू वर्ष के सूरजमुखी के बीज का सही एमएसपी यानी 7721 रुपये प्रति क्विंटल शामिल किया गया था। संशोधित निदेर्शों की सूचना सभी संबंधित पक्षों को यह बताना महत्वपूर्ण है कि समाचार रिपोर्ट में केवल प्रारंभिक निदेर्शों का उल्लेख किया गया है और पहले से जारी किए गए संशोधित निदेर्शों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया है, जिससे एक अधूरे और भ्रामक तथ्य प्रस्तुत किए हैं। इसके अलावा समाचार में कुरुक्षेत्र स्थित हैफेड के जिला प्रबंधक के हवाले से एक बयान दिया गया है। इस संबंध में यह स्पष्ट किया गया है कि किसी भी पत्रकार ने संबंधित जिला प्रबंधक से संपर्क नहीं किया है और उनके हवाले से दिया गया बयान गलत और अनधिकृत है।

मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना : तख्त सचखंड श्री हजूर साहिब नांदेड़ की नि:शुल्क यात्रा के लिए वरिष्ठ नागरिक 15 अप्रैल तक कराएं सरल पोर्टल पर पंजीकरण

सिटी दर्पण संवाददाता
चंडीगढ़

हरियाणा सरकार की मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के तहत श्री हजूर साहिब नांदेड़, महाराष्ट्र के लिए 5 मई को कुरुक्षेत्र से विशेष ट्रेन रवाना होगी। मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी इस ट्रेन को झंडी दिखाकर प्रदेश के विभिन्न जिलों से जाने वाली संगत को रवाना करेंगे।

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी 5 मई को कुरुक्षेत्र से विशेष रेलगाडी को झंडी दिखाकर श्री हजूर साहिब नांदेड़ के लिए करेंगे रवाना

सरकार के प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि वरिष्ठ नागरिक, जिनकी आयु 60 वर्ष से अधिक है और उनकी पारिवारिक आय एक लाख 80 हजार रुपए से कम है, वे इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। योजना का लाभ उठाने के लिए सरल हरियाणा पोर्टल पर 15 अप्रैल तक पंजीकरण किया जा सकता है। पात्र व्यक्ति नजदीकी सीएससी सेंटर या अपने स्मार्ट फोन से सरल हरियाणा पोर्टल पर घर बैठे इस निःशुल्क यात्रा के लिए पंजीकरण कर सकते हैं।

प्रवक्ता ने स्पष्ट किया कि मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के तहत आवेदन करने के लिए कुछ आवश्यक दस्तावेज अनिवार्य किए गए हैं, जिनमें वैध फोटो पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड या अन्य सरकारी आईडी), परिवार पहचान पत्र (पीपीपी), शारीरिक रूप से यात्रा के लिए फिट होने की स्वयं घोषणा तथा पिछले तीन वर्षों में योजना का लाभ न लेने की घोषणा शामिल है। उन्होंने पात्रता की जानकारी देते हुए बताया कि आवेदक का हरियाणा का निवासी होना और परिवार पहचान पत्र होना अनिवार्य है।

प्रवक्ता ने बताया कि वरिष्ठ नागरिक को एक सहायक को पूर्ण भुगतान पर साथ ले जाने की अनुमति है। वहीं 18 से 60 वर्ष आयु वर्ग या 1.80 लाख से अधिक आय वाले लोग इस योजना का लाभ पूर्ण भुगतान पर उठा सकते हैं। योजना के नियमों के अनुसार, कोई भी व्यक्ति हर तीन वर्षों में केवल एक बार ही इस सुविधा का लाभ ले सकता है। ह्लपहले आओ, पहले पाओह्व के आधार पर संचालित इस योजना में आवेदन के लिए परिवार पहचान पत्र अनिवार्य है।

इस योजना के तहत यात्रियों के रहने, खाने और स्थानीय परिवहन की पूरी व्यवस्था सरकार द्वारा अपने स्तर पर की जाएगी। प्रवक्ता ने बताया कि आवेदन करने के उपरांत आवेदक को सूचना अपने - अपने जिला में स्थित जिला सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी कार्यालय में अवश्य देनी होगी ताकि पात्र व्यक्तियों की सूचना रेलवे को समय पर भेजी जा सके। पंजीकृत व्यक्ति 16 अप्रैल से पहले यह सूचना डीआईपीआरओ कार्यालय में अवश्य दें।

युवाओं को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बिना खर्ची-पर्ची के योग्यता के आधार पर मुहैया करवा रहे सरकारी नौकरी: सुमन सैनी

सिटी दर्पण संवाददाता
चंडीगढ़

हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद की उपाध्यक्षा श्रीमती सुमन सैनी ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी लाडवा विधानसभा के गांवों में विकास कार्यों के लिए 21-21 लाख रुपए दे रहे हैं और इसके साथ ही गांव की तरफ से जिन विकास कार्यों की सूची सौंपी जा रही है, मुख्यमंत्री उन कामों को पूरा करने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने उन्हें विधानसभा वासियों की समस्याओं को सुनने के लिए जिम्मेदारी सौंपी हुई है। उसी जिम्मेदारी को निभाते हुए वो लगातार हल्का वासियों के बीच पहुंचकर उनकी समस्याओं और शिकायतों को सुनती हैं।

उपाध्यक्षा श्रीमती सुमन सैनी बुधवार को लाडवा विधानसभा में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रही थी। उन्होंने विधानसभा के गांव ईशरगढ़, गांव अटल नगर, गांव शंकर कॉलोनी, पूर्विया डेरा सिरसमा, गांव मथाना, गांव छारपुरा, गांव मुकरपुर और गांव बोडला में ग्रामीणों की समस्याओं को सुना। उन्होंने अधिकतर समस्याओं के लिए मौके पर ही अधिकारियों को समाधान करने के निर्देश दिए।

उन्होंने अभिभावकों से अपील करते हुए कहा कि सभी अपने-अपने बच्चों की पढ़ाई जरुर करवाएं, क्योंकि एक पढ़ा-लिखा नागरिक अपनी चार पीढ़ियों का सुधार तो करता ही है। इसके साथ ही देश की उन्नति और प्रगति में भी अपना अहम योगदान देते हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी प्रदेश में बिना खर्ची-पर्ची के युवाओं को योग्यता के आधार पर सरकारी नौकरी मुहैया करवा रहे हैं। इससे प्रदेश में बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिला है। पहले की सरकारों में युवा वर्ग नौकरी पाने के लिए खर्ची लेकर नेताओं के पीछे पर्ची पाने के लिए लगे होते थे और अब पढ़ाई के लिए कोचिंग सेंटर पर पढ़ाई कर रहे हैं।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री प्रदेश की सभी विधानसभाओं का समान रूप से विकास करवा रहे हैं। लाडवा विधानसभा में चार गुणा गति से विकास कार्य करवाए जा रहे हैं। प्रदेश में पहले की सरकारों में क्षेत्र और जाति को देखकर काम होते रहे थे, लेकिन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने क्षेत्रवाद, जातिवाद को तो खत्म किया ही है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी को लाडवा की ग्रामीण सीट से चुनाव लड़वाकर ग्रामीण विकास को बढ़ावा दिया है। उन्होंने कहा कि इस सोच से देश, प्रदेश व ग्रामीण क्षेत्र को विकसित करने में गति मिली है। ऐसी योजनाओं से ही वर्ष 2047 तक देश को विकसित भारत बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने प्रदेश के हर वर्ग के लिए योजनाएं बनाई है।

यूएचबीवीएन पंचकूला जोन के उपभोक्ताओं की अप्रैल में चार दिन करेगा शिकायतों का निवारण

सिटी दर्पण संवाददाता
चंडीगढ़

6, 13, 20 और 27 को विद्युत सदन, पंचकूला में की जाएगी सुनवाई

उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम उपभोक्ताओं को विश्वसनीय, अच्छी वोल्टेज और निर्बाध बिजली की आपूर्ति के लिए प्रतिबद्ध है। ह्यपूर्ण उपभोक्ता संतुष्टिह्ल के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बिजली निगम द्वारा अनेक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम प्रारंभ किये गए हैं ताकि उपभोक्ताओं की समस्याओं को त्वरित रूप में सुलझाया जा सके। उक्त जानकारी देते हुए बिजली निगम के प्रवक्ता ने बताया कि जोनल उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच रेगुलेशन 2.8.2 के अनुसार प्रत्येक मामले में 1 लाख रुपये से अधिक और 3 लाख रुपये तक की राशि के वित्तीय विवादों से संबंधित शिकायतों की सुनवाई करेगा। पंचकूला जोन के अंतर्गत आने वाले जिले कुरुक्षेत्र, अंबाला, पंचकूला, कैथल और यमुनानगर के उपभोक्ताओं की शिकायतों का निवारण 06, 13, 20 और 27 अप्रैल को जोनल उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच द्वारा पंचकूला में समाधान किया जाएगा। उन्होंने बताया कि पंचकूला जोन के अंतर्गत आने वाले जिलों के उपभोक्ताओं के गलत बिलों, बिजली की दरों से सम्बंधित मामलों, मीटर सिक्योरिटी से जुड़े मामलों, खराब हुए मीटरों से सम्बंधित मामलों, वोल्टेज से जुड़े हुए मामलों का निस्तारण किया जाएगा। इस दौरान बिजली चोरी, बिजली के दुरूप्योग और घातक गैर-घातक दुर्घटना आदि मामलों पर विचार नहीं किया जाएगा। प्रवक्ता ने बताया कि उपभोक्ता और निगम के बीच किसी भी विवाद के निपटान के लिए फोरम में वित्तीय विवादों से संबंधित शिकायत प्रस्तुत करने से पहले पिछले छह महीनों के दौरान उपभोक्ता द्वारा भुगतान किए गए बिजली के औसत शुल्क के आधार पर गणना की गई प्रत्येक माह के लिए दावा की गई राशि या उसके द्वारा देय बिजली शुल्क के बराबर राशि, जो कम है, उपभोक्ता को जमा करवानी होगी।

मजदूरों व व्यापारियों से की बातचीत, अटल किसान कैंटीनों को गैस उपलब्ध करवाने के डीएफएससी को दिए निर्देश,

अनाज मंडियों की अटल किसान कैंटीनों में मिलेगा अच्छी गुणवत्ता का भोजन : विश्राम कुमार मीणा

सिटी दर्पण संवाददाता
कुरुक्षेत्र

उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा ने कहा कि जिला की अनाज मंडियां की अटल किसान कैंटीनों पर अच्छी गुणवत्ता का भोजन उपलब्ध करवाया जाएगा। कैंटीनों में भोजन बनाने में किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो, इसके लिए डीएफएससी को गैस उपलब्ध करवाने के निर्देश भी दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि इस बार उठान कार्य में शामिल होने वाले वाहनों की जीपीएस के माध्यम से ट्रेकिंग की जाएगी। सभी अनाज मंडियों में समस्याओं का समाधान करने के लिए उच्च अधिकारी के नेतृत्व में टीम तैनात रहेगी।

उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा बुधवार को थानेसर अनाज मंडी की अटल किसान कैंटीन व अनाज मंडी का निरीक्षण कर रहे थे। इसके उपरांत उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा ने मार्केट कमेटी कार्यालय में खरीद एजेंसियों, उठान एजेंसी, अधिकारियों, आढ़तियों, व्यापारियों के साथ बैठक में समस्याओं पर चर्चा भी की। उन्होंने अनाज मंडी स्तर पर एक-एक टीम को समाधान के लिए नियुक्त किया गया है।

उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा ने कहा कि इस बार सरकार ने खरीद कार्य में नवाचार को शामिल किया गया है। इस प्रक्रिया में किसान अपने मोबाइल में एप के माध्यम से गेटपास बना सकेगा। गेटपास बनाने के बाद किसानों को अपनी बायोमेट्रिक करवानी होगी। अनाज मंडी में लगाए गए बायोमेट्रिक यंत्र से डाटा आगे बढने.के बाद ही ई-खरीद केंद्र पर किसानों की फसल का डाटा उपलब्ध होगा। उन्होंने कहा कि इस बारे में किसानों को आढ़ती, व्यापारी और अधिकारियों द्वारा जागरूक किया जाएगा। किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान करने के लिए और किसानों की सहायता के लिए अधिकारी कर्मचारी की टीम मौजूद रहेगी। उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा ने कहा कि अनाज मंडियों में शौचालयों, साफ-सफाई, बायोमेट्रिक और उठाने की उचित व्यवस्था की जाएगी। प्रशासन ने लिफ्टिंग को लेकर इस बार दिक्कत ना हो, इसको लेकर व्यापक स्तर पर तैयार की है। बैठक के दौरान आढ़तियों, व्यापारियों व अधिकारियों से सीजन में आने वाली समस्याओं को जानकर उनके समाधान की योजना भी तैयार की जा रही है। इस बारे लिफ्टिंग सहित अन्य व्यवस्थाओं की सभी प्रकार की तैयारियों व टेंडर प्रक्रिया को पूरा कर लिया गया है। लिफ्टिंग में लगने वाले वाहनों की जीपीएस सिस्टम के माध्यम से निगरानी की जाएगी।

उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा ने थानेसर अनाज मंडी में अटल किसान कैंटीन का किया निरीक्षण, स्वयं सहायता समूह की महिलाओं और किसानों, को मिलेगा लाभ

उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा ने कहा कि सरकार के आदेशानुसार 12 प्रतिशत नमी से कम वाली गेहूं की फसल की खरीद की जानी है। किसानों से आग्रह करते हुए कहा कि सभी किसान अपने खेतों में ही गेहूं की फसल को सूखा कर अनाज मंडी में लेकर आएं, ताकि दिन के दिन ही गेहूं की खरीद को किया जा सके। खरीद होने के साथ ही उठान भी समय पर होगा। उन्होंने कहा कि अनाज मंडी व सड़कों पर किसी भी प्रकार का जाम व अन्य व्यवस्थाएं की जाएंगी, ताकि किसानों, व्यापारियों और आमजनों को किसी भी प्रकार की दिक्कत परेशानी ना हो।

संपादकीय

जनगणना 2027 का नया नियम: अब खुद भरनी होगी अपनी जानकारी

भारत में जनगणना केवल आंकड़ों का संकलन नहीं, बल्कि देश की विकास यात्रा का आधार मानी जाती है। हर दस साल में होने वाली यह प्रक्रिया सरकार को यह समझने में मदद करती है कि देश की आबादी किस दिशा में बढ़ रही है, किन क्षेत्रों में विकास की आवश्यकता है और किन वर्गों को विशेष ध्यान देने की जरूरत है। अब आने वाली जनगणना 2027 को लेकर एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है- डिजिटल माध्यम से 'सेल्फ-एन्यूमरेशन' यानी स्वयं द्वारा जानकारी दर्ज करने की सुविधा। यह बदलाव न केवल तकनीकी दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि नागरिकों की सक्रिय भागीदारी को भी बढ़ावा देता है। सेल्फ-एन्यूमरेशन का मतलब है कि अब नागरिक स्वयं अपने घर और परिवार से जुड़ी जानकारी ऑनलाइन पोर्टल या मोबाइल एप के माध्यम से भर सकेंगे। पहले यह जिम्मेदारी गणनाकर्मियों की होती थी, जो घर-घर जाकर जानकारी इकट्ठा करते थे। हालांकि यह प्रणाली प्रभावी थी, लेकिन उसमें समय, संसाधन और कई बार डेटा की सटीकता से जुड़ी चुनौतियां सामने आती थीं। डिजिटल युग में सरकार ने इस प्रक्रिया को आसान और अधिक पारदर्शी बनाने के लिए यह नया विकल्प पेश किया है। इस नई व्यवस्था के तहत नागरिकों को जनगणना शुरू होने से पहले अधिकारिक जनगणना पोर्टल या ऐप पर पंजीकरण करना होगा। इसके लिए एक सक्रिय मोबाइल नंबर जरूरी होगा, जिस पर ओटीपी के जरिए सत्यापन किया जाएगा। पंजीकरण के बाद एक यूजर आईडी और पासवर्ड तैयार किया जाएगा, जिसके माध्यम से व्यक्ति लॉग इन कर सकेगा। लॉग इन करने के बाद 'सेल्फ-एन्यूमरेशन' का विकल्प दिखाई देगा, जहां से पूरी प्रक्रिया शुरू होती है। प्रक्रिया के पहले चरण में घर से संबंधित जानकारी भरनी होती है। इसमें मकान का प्रकार, स्वामित्व की स्थिति, पानी और बिजली जैसी मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता जैसी जानकारी शामिल होती है। यह डेटा सरकार के लिए बेहद महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इसके आधार पर आवास योजनाओं और बुनियादी सुविधाओं से जुड़े फैसले लिए जाते हैं। इसके बाद परिवार के सदस्यों की जानकारी दर्ज करनी होती है। हर सदस्य के लिए नाम, उम्र, लिंग, शिक्षा, पेशा और वैवाहिक स्थिति जैसी जानकारी भरनी होती है। यह जानकारी देश के सामाजिक ढांचे और रोजगार की स्थिति को समझने में मदद करती है। सेल्फ-एन्यूमरेशन के दौरान कुछ विशेष श्रेणियों से संबंधित प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं, जैसे प्रवास, विकलांगता की स्थिति, मातृभाषा और अन्य सामाजिक-आर्थिक पहलू। इन सवालों का उद्देश्य यह समझना है कि समाज के विभिन्न वर्ग किन परिस्थितियों में जीवन यापन कर रहे हैं। यह जानकारी भविष्य की नीतियों को अधिक समावेशी बनाने में मदद करती है। सभी जानकारी भरने के बाद उसे एक बार ध्यानपूर्वक जांचना बेहद जरूरी है। किसी भी प्रकार की त्रुटि आगे चलकर नीतिगत फैसलों को प्रभावित कर सकती है। जब पूरी तरह संतुष्टि हो जाए, तब अंतिम सबमिशन किया जाता है और एक संदर्भ संख्या या रसीद प्राप्त होती है। यह रसीद भविष्य में किसी भी प्रकार के सत्यापन या संदर्भ के लिए उपयोगी होती है। सेल्फ-एन्यूमरेशन की सबसे बड़ी खासियत इसकी सुविधा और समय की बचत है। अब नागरिकों को गणनाकर्मी का इंतजार नहीं करना पड़ेगा और वे अपनी सुविधा के अनुसार कभी भी यह प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। इसके अलावा, अपनी जानकारी खुद भरने से डेटा की सटीकता भी बढ़ती है। गोपनीयता के लिहाज से भी यह एक सुरक्षित तरीका माना जा रहा है, क्योंकि डेटा सीधे सरकारी सिस्टम में दर्ज होता है और बीच में किसी तीसरे व्यक्ति की भूमिका कम हो जाती है। हालांकि, इस प्रक्रिया के साथ कुछ सावधानियां भी जरूरी हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि केवल आधिकारिक वेबसाइट या ऐप का ही उपयोग किया जाए। इंटरनेट पर कई फर्जी लिंक और धोखाधड़ी के प्रयास सामने आ सकते हैं, इसलिए सतर्क रहना आवश्यक है। इसके अलावा, किसी अन्य व्यक्ति की जानकारी उसकी अनुमति के बिना भरना गलत है और इससे कानूनी समस्या भी उत्पन्न हो सकती है। सही और पूरी जानकारी देना नागरिक की जिम्मेदारी है, क्योंकि यही आंकड़े भविष्य की योजनाओं का आधार बनते हैं। डिजिटल भारत के परिप्रेक्ष्य में यह पहल एक बड़ा कदम है। इससे न केवल सरकारी प्रक्रियाओं में पारदर्शिता बढ़ेगी, बल्कि नागरिकों का भरोसा भी मजबूत होगा। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में इंटरनेट की पहुंच बढ़ने के साथ यह उम्मीद की जा रही है कि बड़ी संख्या में लोग इस सुविधा का लाभ उठाएंगे। हालांकि, जिन लोगों के पास डिजिटल साधनों की कमी है, उनके लिए पारंपरिक तरीके से गणनाकर्मी द्वारा डेटा संग्रह की व्यवस्था भी जारी रहेगी। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि सेल्फ-एन्यूमरेशन को व्यापक स्तर पर अपनाया गया, तो भारत की जनगणना प्रक्रिया अधिक सटीक, तेज और प्रभावी बन सकती है। यह न केवल प्रशासनिक दक्षता को बढ़ाएगा, बल्कि नीति निर्माण को भी अधिक डेटा-आधारित बनाएगा। इससे सरकार को यह समझने में मदद मिलेगी कि किन क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और बुनियादी सुविधाओं के लिए अधिक निवेश की जरूरत है। अंततः, जनगणना 2027 में सेल्फ-एन्यूमरेशन केवल एक तकनीकी बदलाव नहीं, बल्कि नागरिकों को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। यह हर नागरिक को यह अवसर देता है कि वह अपने देश के विकास में सीधे योगदान दे सके। सही जानकारी देकर नागरिक न केवल अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं, बल्कि एक मजबूत और समावेशी भारत के निर्माण में भी भागीदार बनते हैं।

आरएसएस @100: संघ की वैचारिक यात्रा का ऐतिहासिक दस्तावेज

पुरु शर्मा (हि.स)

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की 100 वर्ष की यात्रा पूरी होने पर देशभर में संघ की विचारधारा, उसकी उपलब्धियों एवं योगदान को लेकर चर्चा है। ऐसे में 'मीडिया विमर्श' का विशेषांक 'आरएसएस@100' का आना महत्वपूर्ण है। मीडिया विमर्श का यह विशेषांक संघ से संबंधित सामयिक एवं चर्चित विषयों पर प्रामाणिक जानकारी उपलब्ध कराता है। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के सहायक प्राध्यापक एवं लेखक डॉ. लोकेन्द्र सिंह इसके अतिथि संपादक हैं। संघ विषयों पर वे निरंतर लिखते हैं। संघ पर केंद्रित उनकी दो महत्वपूर्ण पुस्तकें- संघ दर्शनः अपने मन की अनुभूति और राष्ट्रध्वज एवं आरएसएस भी उल्लेखनीय हैं।

डॉ. सिंह के कुशल संपादन में तैयार मीडिया विमर्श का विशेषांक संघ की एक सदी की यात्रा को केवल एक संगठन के इतिहास के रूप में नहीं, बल्कि भारत की सांस्कृतिक और राष्ट्रीय चेतना के पुनर्जागरण की गाथा के रूप में प्रस्तुत करता है। यह विशेषांक उन सबके लिए उपयोगी है, जो संघ को जानना-समझना चाहते हैं। कहना होगा कि यह एक संदर्भ ग्रंथ की भाँति है।

'मीडिया विमर्श' के सलाहकार संपादक प्रो. संजय द्विवेदी ने संपादकीय लेख 'दिल से समझिए आरएसएस को' में स्पष्टता के साथ उन भ्रांतियों पर प्रहार किया है जो अक्सर बौद्धिक जगत में संघ के विरुद्ध प्रचारित की जाती हैं। उन्होंने इस बात को रेखांकित किया है कि संघ अपनी कार्यपद्धति के कारण प्रचार से दूर रहता है, जिसके कारण उसकी वास्तविक छवि और सेवा कार्यों का पूरा सच अक्सर सामने नहीं आ पाता।

इस विशेषांक की सबसे बड़ी विशेषता इसका व्यापक फलक है, जिसमें देश के शीर्ष नेतृत्व से लेकर संघ के वरिष्ठ प्रचारकों के विचारों को शामिल किया गया है। डॉ. लोकेन्द्र सिंह ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से लेकर संघ के वरिष्ठ प्रचारकों श्रीधर पराड़कर, निखिलेश माहेश्वरी, कैलाश चंद्र, सदानंद सप्रे और हितानंद शर्मा के विचारों को शामिल कर संघ के दृष्टिकोण को यथार्थ रूप में पाठकों के सामने लाने का प्रयास किया है। इसके अलावा संघ को नजदीक से देखने और उससे जुड़े अन्य लेखकों के आलेख भी विशेषांक में हैं।

संघ के वर्तमान सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले और अन्य वरिष्ठ पदाधिकारियों के वक्तव्य इस बात की पुष्टि करते हैं कि संघ का उद्देश्य समाज में कोई अलग गुट बनाना नहीं बल्कि पूरे समाज को संगठित और सामर्थ्यवान बनाना है। वहीं, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अपने आलेख में संघ को 'अनादि राष्ट्र चेतना का पुण्य अवतार' बताते हुए व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण की इसकी अनूठी कार्यपद्धति की सराहना की है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने डॉ. हेडगेवार और बाबा साहेब अंबेडकर के विचारों में निहित समानता को उजागर करते हुए संघ की सर्व-समावेशी समाज-दृष्टि का प्रमाण प्रस्तुत किया है। संपादक डॉ. लोकेन्द्र सिंह ने अपने लेख में संघ के सौ वर्षों को पांच चरणों में विभाजित कर यह समझाया है कि कैसे यह संगठन उपहास, उपेक्षा और विरोध के कठिन अवरोधों को पार करते हुए आज समाज की सज्जनशक्ति के साथ 'एकरस' होने की स्थिति में पहुँचा है।

विशेषांक के विभिन्न लेखों के माध्यम से यह स्पष्ट होता है कि संघ के लिए 'हिन्दू' शब्द कोई उपासना पद्धति नहीं बल्कि एक व्यापक सांस्कृतिक और राष्ट्रीय पहचान है जो 'वसुधैव कुटुंबकम' के मर्म को आत्मसात करती है। शिक्षा, सेवा और समाज सुधार के क्षेत्र में संघ के योगदान पर भी इस अंक में विस्तार से चर्चा की गई है। डॉ. सदानन्द दामोदर सप्रे ने अपने लेख में बहुत ही तार्किक ढंग से उन भ्रांतियों का निवारण किया है जिनमें संघ को किसी विशेष जाति या वर्ग का संगठन माना जाता है। निखिलेश माहेश्वरी के लेख में विद्या भारती के माध्यम से मैकाले की शिक्षा पद्धति के विकल्प के रूप में भारतीय मूल्य आधारित शिक्षा के सफल प्रयोग को दशार्या गया है। 'पंच परिवर्तन' की संघ की संकल्पना के एक-एक संकल्प पर विस्तार से चर्चा यह विशेषांक करता है।

विशेषांक के आखिर में 'अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों' को शामिल किया गया है, जो संघ को लेकर एक स्पष्ट सोच बनाते हैं। इसके साथ अन्य पठनीय पुस्तकों की सूची देकर उन पाठकों की सहायता की है, जो संघ के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं। कुल मिलाकर कहना होगा कि डॉ. लोकेन्द्र सिंह जैसे विद्वानों ने संघ, सत्ता और समाज के अंतसंर्बधों तथा शताब्दी वर्ष की चुनौतियों का सारगर्भित विश्लेषण प्रस्तुत कर इस अंक को ऐतिहासिक दस्तावेज बना दिया है।

विशेषांक : आरएसएस@100
संपादक : डॉ. लोकेन्द्र सिंह
पृष्ठ : 264
प्रकाशक : मीडिया विमर्श

आज का राशिफल

मेष: आज का दिन धैर्य और संतुलन की परीक्षा ले सकता है। आप दूसरों की मदद करने के लिए आगे आएंगे, जिससे आपकी सामाजिक छवि मजबूत होगी। आय-व्यय को संतुलित रखने की कोशिश करेंगे। परिवार में किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर सामूहिक चर्चा संभव है। *(सिटी दर्पण)*

वृषभ: आज आपको अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना बेहद जरूरी है। कार्यस्थल पर सहकर्मियों के साथ टकराव से बचें और संवाद के माध्यम से समस्याओं को सुलझाएं। व्यापार में अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है। *(सिटी दर्पण)*

मिथुन: व्यवसाय में स्थिरता बनी रहेगी और काम सुचारु रूप से चलता रहेगा। स्वास्थ्य के लिहाज से पेट से जुड़ी समस्या परेशान कर सकती है। कार्यस्थल पर अधीनस्थों पर नियंत्रण बनाए रखना जरूरी होगा। नई तकनीकों के प्रति आपका झुकाव बढ़ेगा। *(सिटी दर्पण)*

कर्क: लंबे समय से रुका हुआ कार्य आज पूरा होने की संभावना है। संयम और धैर्य से काम लेने पर सफलता मिलेगी। ज्ञान और कौशल बढ़ाने की दिशा में प्रयास करना फायदेमंद रहेगा। दोस्तों की मदद से व्यापार में लाभ मिल सकता है। *(सिटी दर्पण)*

सिंह: आज का दिन कार्यक्षेत्र में सामान्य रहेगा। स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही न करें, विशेषकर दवाइयों को नजरअंदाज न करें। आपकी सलाह दूसरों के लिए उपयोगी साबित होगी। लंबी दूरी की यात्रा संभव है। अचानक धनहानि से सतर्क रहें। *(सिटी दर्पण)*

कन्या: आज आपका आत्मविश्वास मजबूत रहेगा और कार्यक्षेत्र में प्रभाव भी बढ़ेगा। संतान के प्रति आपका लगाव बढ़ेगा। करियर को लेकर सतर्क रहने की जरूरत है। विरोधी कमजोर पड़ सकते हैं। आप अपने लक्ष्यों के प्रति पूरी तरह केंद्रित रहेंगे। *(सिटी दर्पण)*

तुला: आज दूसरों पर अपनी राय थोपने से बचें। घरेलू मामलों को सार्वजनिक न करें, वरना लोग मजाक बना सकते हैं। मौसम में बदलाव के कारण सिरदर्द या थकान हो सकती है। काम के प्रति आपकी प्रतिबद्धता मजबूत रहेगी। *(सिटी दर्पण)*

वृश्चिक: दाम्पत्य जीवन में प्रेम और सामंजस्य बढ़ेगा। आज का दिन अधिकतर मामलों में शुभ रहेगा। प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता के योग हैं। आपको कोई सम्मान या पुरस्कार मिल सकता है। लोग आपकी बातों को गंभीरता से सुनेंगे। *(सिटी दर्पण)*

धनु: आज व्यापार से जुड़ी जटिल समस्याओं का समाधान मिल सकता है। दोपहर तक आप किसी निर्णय को लेकर विचारमग्न रहेंगे। बड़ा निवेश फायदेमंद साबित हो सकता है। व्यक्तित्व और जीवनशैली में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे। *(सिटी दर्पण)*

मकर: व्यापारियों के लिए आय में वृद्धि के संकेत हैं। मन प्रसन्न रहेगा और ऊर्जा बनी रहेगी। हालांकि परिवार में सामंजस्य थोड़ा कमजोर हो सकता है। मार्केटिंग से जुड़े लोगों को विशेष लाभ मिलेगा। बातचीत करते समय शब्दों का चयन सोच-समझकर करें। *(सिटी दर्पण)*

कुंभ: आज खर्च करते समय बजट का ध्यान रखना जरूरी है। स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही नुकसानदायक हो सकती है। यात्रा के दौरान कुछ परेशानियां आ सकती हैं। विवादों से दूर रहना बेहतर होगा। अपनी वाणी में मधुरता बनाए रखें। *(सिटी दर्पण)*

मीन: आज आपका आत्मविश्वास और मनोबल उच्च रहेगा। अपनी उपलब्धियों पर गर्व महसूस करेंगे। दाम्पत्य जीवन सुखद रहेगा। स्वास्थ्य भी अच्छा बना रहेगा। बुद्धिमान लोगों की संगति से लाभ मिलेगा और भविष्य के प्रति सकारात्मक सोच बनी रहेगी। *(सिटी दर्पण)*

भारतीय शासन व्यवस्था की पटकथा फिर से लिख रहा है मिशन कर्मयोगी

कल्पना करें कि राजस्थान के दूरदराज के किसी कोने में जिला कलेक्टर को एक ऐसी महत्वाकांक्षी कल्याण योजना की जिम्मेदारी सौंपी जाती है जिसके बारे में उसकी जानकारी बहुत कम है। एक दशक पहले उसे जानकारी के लिए कहीं धूल खा रही किसी नियमावली का सहारा लेना होता। या फिर वह अपने किसी वरिष्ठ सहयोगी की तीन बैठकों और लंच के बाद खाली होने का इंतजार करता। उसकी उम्मीद उस प्रशिक्षण कार्यक्रम पर भी टिकी हो सकती थी जो शायद एक या दो साल में कभी आता। लेकिन आज वह अपने फोन के जरिए आईगॉट (इंटिग्रेटेड गर्वनमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म) पर लॉग ऑन करता है। उसे मिनटों में ही अपनी जरूरत के अनुरूप एक सुव्यवस्थित कार्यकुशलता आधारित पाठ्यक्रम मिल जाता है। वह शाम तक सूचनाओं और आत्मविश्वास से लैस होकर योजना के लाभार्थियों की पहली बैठक की अध्यक्षता कर रहा होता है। यह बदलाव देखने में छोटा लग सकता है मगर हकीकत में किसी क्रांति से कम नहीं है।

चमक-दमक से दूर धैर्य के साथ पांच साल पहले शुरू किया गया मिशन कर्मयोगी एक क्रांति ला रहा है। यह नए भारत के लिए एक नई तरह के प्रशासनिक अधिकारी तैयार करने के उद्देश्य से चुपचाप काम कर रहा है।

इसके महत्व को समझने के लिए हमें पहले संदर्भ को जानना होगा। 2047 तक विकसित भारत के प्रधानमंत्री के निर्धारित लक्ष्य तक यूं ही नहीं पहुंचा जा सकता। इस मंजिल तक पहुंचने के लिए हमें भारत गणतंत्र को चलाने वाली संस्थाओं और व्यक्तियों के जरिए सावधानी से एक-एक कदम आगे बढ़ना होगा। इस यात्रा में सबसे महत्वपूर्ण पूंजी, प्रौद्योगिकी या नीति नहीं है। सबसे ज्यादा अहमियत उन लगभग 3.5 करोड़ प्रशिक्षित, उत्साही और नागरिक केंद्रित सरकारी कर्मियों की क्षमता की है जो हर सुबह उठ कर भारतीय शासन को संचालित करते हैं।

स्वतंत्र भारत के इतिहास में ज्यादातर समय क्षमता निर्माण का मॉडल सांयोगिक रहा है। किसी नौजवान अधिकारी को सेवा की शुरूआत के समय औपचारिक प्रशिक्षण दिया जाता था। फिर करियर के बीच में यदा-कदा उसे कुछ पाठ्यक्रमों में हिस्सा लेने का अवसर मिल सकता था। बाकी, उसे काम करते हुए और दूसरों को देख कर ही सीखना होता था। एक स्थिर और धीमी गति से आगे बढ़ते विश्व में यह काफी था। लेकिन कृत्रिम मेधा, जलवायु अवरोध, जनसांख्यिकीय दबाव और जबर्दस्त प्रौद्योगिकीय परिवर्तन के युग में यह सरासर नाकाफी है। प्रशासन के सामने चुनौतियां जिस रफ्तार से आती हैं उसके सामने प्रशिक्षण की पुरानी प्रणालियों की गति कहीं नहीं टिकती।

'मिशन कर्मयोगी' को इसी बेमेल स्थिति के समाधान के रूप में की गई थी। 2021 में शुरू किया गया यह मिशन–जिसे उसी वर्ष अप्रैल में स्थापित 'क्षमता निर्माण आयोग' द्वारा संस्थागत रूप से संचालित किया गया, एक सचमुच महत्वाकांक्षी लक्ष्य को पूरा करने के लिए आगे बढ़ा। भारतीय सिविल सेवाओं की सीखने की संस्कृति को, समय-समय पर होने वाली और केवल नियमों के पालन तक सीमित प्रक्रिया से बदलकर, एक निरंतर चलने वाली, भूमिका-आधारित और स्वयं-निर्देशित विकास यात्रा में रूपांतरित करना इसका मकसद है। जैसा कि आयोग इसका वर्णन करता है, यह बदलाव 'कर्मचारी'–यानी नियमों का पालन करने वाले एक पदाधिकारी से 'कर्मयोगी' बनने की ओर है: एक ऐसा लोक सेवक जो किसी उद्देश्य, सेवा-भाव और उत्कृष्टता से प्रेरित हो।

पाँच वर्षों के बाद, ये आंकड़े अत्यंत शिक्षाप्रद हैं। 'आईगॉट' (इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग) प्लेटफॉर्म पर अब 1.5 करोड़ से अधिक सरकारी अधिकारी सक्रिय शिक्षार्थी के रूप में जुड़े हैं – यह एक ऐसी संख्या है जो शुरूआत के समय काल्पनिक लगती थी। 4,600 से अधिक योग्यता-आधारित पाठ्यक्रमों के माध्यम से, इन अधिकारियों ने 8.3 करोड़ से अधिक पाठ्यक्रम पूरे किए हैं। अकेले पिछले 'राष्ट्रीय शिक्षण सप्ताह' के दौरान, भागीदारी के परिणामस्वरूप 4.5 मिलियन घंटे के पाठ्यक्रम नामांकन और 3.8 मिलियन घंटे की वास्तविक शिक्षा दर्ज की गई। ये केवल अमूर्त आंकड़े नहीं हैं। दर्ज किया गया प्रत्येक घंटा भारत में कहीं न कहीं एक लोक सेवक का प्रतिनिधित्व करता है – छत्तीसगढ़ में एक राजस्व निरीक्षक, पुणे में एक शहरी स्थानीय निकाय अधिकारी, मणिपुर में एक स्वास्थ्य कार्यकर्ता, ये सब अपने साथी नागरिकों की बेहतर सेवा करने के लिए अपनी क्षमता बढ़ा रहें हैं।

जो बात आईगॉट प्लेटफॉर्म को वास्तव में परिवर्तनकारी बनाती है, वह केवल इसका पैमाना नहीं है, बल्कि इसकी 'पहुँच की संरचना' है। यह किसी भी समय और कहीं भी, स्मार्टफोन या डेस्कटॉप पर, कई भाषाओं में उपलब्ध है, और इसे

डॉ जितेंद्र सिंह

शिक्षार्थी के पेशेवर प्रोफाइल के अनुसार बनाया गया है। पाठ्यक्रमों को हर तीन से छह महीने में अपडेट किया जाता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि शासन में एआई टूल का उपयोग कैसे करें या नए वित्तीय नियमों को कैसे समझें, इससे संबंधित सामग्री वर्तमान और प्रासंगिक बनी रहे। दूसरे शब्दों में, यह प्लेटफॉर्म धूल फांकने वाली कोई डिजिटल लाइब्रेरी नहीं है – बल्कि यह सीखने का एक जीवंत और अनुकूलन योग्य तंत्र है। इस पर विचार कीजिए कि एक आदिवासी जिले की जूनियर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के लिए इसका क्या अर्थ है, जिसे उसकी अपनी भाषा में बाल पोषण मूल्यांकन के नवीनतम प्रोटोकॉल समझाने वाला एक मॉड्यूल प्राप्त होता है। उसे अपने ब्लॉक में किसी प्रशिक्षक के आने का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। वह सीखती है, और कार्य करती है। यही इस मिशन का 'लोकतांत्रिक लाभांश' है।

क्षमता निर्माण आयोग, इस तंत्र के रणनीतिक संरक्षक के रूप में, एक साथ 'वास्तुकार' और 'संचालक' दोनों की भूमिका निभाता है। राष्ट्रीय नीति बनाने वाले एक सचिव से लेकर ग्राम स्तर पर इसे लागू करने वाले एक पंचायत पदाधिकारी तक, यह पहचान करता है कि सार्वजनिक भूमिकाओं के विशाल स्पेक्ट्रम में किन योग्यताओं की आवश्यकता है। यह सिविल सेवा प्रशिक्षण संस्थानों के लिए राष्ट्रीय मानक 2.0 ढांचे के माध्यम से देश के प्रशिक्षण संस्थानों के लिए गुणवत्ता मानक निर्धारित करता है, जिसके तहत देश भर के 200 से अधिक प्रशिक्षण संस्थान पहले ही मान्यता प्राप्त कर चुके हैं। यह राज्यों के साथ मिलकर काम करता है। सभी 30 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश अब औपचारिक समझौता ज्ञापनों के माध्यम से जुड़ चुके हैं ताकि ऐसी विशिष्ट 'क्षमता निर्माण योजनाएं' तैयार की जा सकें जो कार्यबल की दक्षताओं को संगठनात्मक लक्ष्यों के साथ जोड़ती हैं। 'राष्ट्रीय कर्मयोगी जन सेवा कार्यक्रम' जैसी ऐतिहासिक पहलों के माध्यम से, इसने एक मिलियन से अधिक प्रमाणित अधिकारियों को बड़े पैमाने पर व्यवहार प्रशिक्षण दिया है, जो प्रत्येक नागरिक को अंतिम हितधारक के रूप में मानने की सूक्ष्म लेकिन महत्वपूर्ण कला है।

मिशन के इस अंतिम आयाम पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि यह एक ऐसी चीज के बारे में है जिसे 'पूर्णता प्रमाण पत्र' या 'लॉग किए गए घंटों' में आसानी से नहीं मापा जा सकता। मिशन कर्मयोगी की सबसे गहरी आकांक्षाओं में से एक है– दृष्टिकोण में बदलाव। यह राज्य और नागरिक के बीच एक 'लेन-देन' वाले संबंध से हटकर 'नागरिक देवो भव' की भावना से परिभाषित संबंध की ओर एक आंदोलन है: नागरिक ईश्वर के समान है, वह सर्वोच्च अधिकारी है जिसके प्रति राज्य का सेवक जवाबदेह है। जब रेलवे काउंटरों, राजस्व कार्यालयों और स्वास्थ्य केंद्रों पर नागरिक-केंद्रित अधिकारियों को इसके तहत प्रशिक्षित किया गया और बाद में नागरिकों का सर्वेक्षण किया गया तो प्रतिक्रिया आश्चर्यजनक थी। उन्होंने बदलाव को महसूस किया। न केवल दक्षता में, बल्कि व्यवहार की आत्मीयता, तत्परता और बातचीत की मानवीय गुणवत्ता में भी। एक ऐसे युग में जब एआई प्रशासनिक कार्यों के विशाल हिस्सों को स्वचालित करने की चुनौती दे रहा है, यह मानवीय परत, जो सहानुभूतिपूर्ण, सांस्कृतिक रूप से जागरूक और स्थानीय जड़ों से जुड़ी है कोई फालतू चीज नहीं, बल्कि भारत के शासन की सर्वोच्च शक्ति है।

इस मिशन ने अपनी तकनीकी महत्वाकांक्षाओं के साथ-साथ भारत की बौद्धिक विरासत का सम्मान करने का भी एक सचेत प्रयास किया है। 'भारतीय ज्ञान प्रणाली प्रकोष्ठ' के माध्यम से, पारंपरिक ज्ञान जिसमें सामुदायिक शासन और कृषि से लेकर वित्त और स्वास्थ्य सेवा तक के क्षेत्र शामिल हैं – को प्रशिक्षण सामग्री के ताने-बाने में बुना जा रहा है; इसे केवल अतीत की यादों के रूप में नहीं, बल्कि एक जीवंत ज्ञान के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। 'अमृत ज्ञान कोष' भंडार, जिसमें 70 से अधिक पूर्ण केस स्टडीज शामिल हैं, शासन-प्रशासन से जुड़े ऐसे ज्ञान का एक संग्रह तैयार कर रहा है जिसकी जड़ें भारतीय संदर्भों और भारतीय समाधानों में निहित हैं। प्रशासनिक मानसिकता का यह 'वि-औपनिवेशीकरण', जिसके तहत भारतीय लोक सेवकों को आधुनिक चुनौतियों का सामना करते हुए अपनी ही सभ्यतागत विरासत के साथ आत्मविश्वासपूर्ण जुड़ाव स्थापित करने की ओर लौटाया जाता है। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रमुख आकांक्षाओं में से एक है और 'मिशन कर्मयोगी' इसी आकांक्षा को साकार रूप दे रहा है।

'साधना' सप्ताह 2 से 8 अप्रैल तक मनाया जाने वाला राष्ट्रीय शिक्षण सप्ताह – इस पांच वर्षीय यात्रा का उत्सव और इसके अधूरे कार्यों के प्रति पुनर्संकल्प, दोनों है। 'साधना' शब्द यहाँ अत्यंत उपयुक्त है। इसका अर्थ है समर्पित अभ्यास; एक ऐसे व्यक्ति का अनुशासित दैनिक प्रयास जो किसी एक असाधारण कार्य के माध्यम से नहीं, बल्कि अपने कौशल के प्रति निरंतर समर्पण के माध्यम से निपुणता प्राप्त करना चाहता है। जैसे ही हम सिविल सेवा प्रशिक्षण संस्थानों के एक 'राष्ट्रीय सम्मेलन' के साथ इस सप्ताह का उद्घाटन कर रहे हैं, जिसमें लगभग 700 वरिष्ठ अधिकारी व्यक्तिगत रूप से और 3,000 से अधिक वर्चुअल माध्यम से शामिल हो रहे हैं, हम केवल एक वर्षगाँठ नहीं मना रहे हैं। हम अगले पांच वर्षों के लिए अपना लक्ष्य निर्धारित कर रहे हैं – एक ऐसे भविष्य की ओर जिसमें हर स्तर पर प्रत्येक सिविल सेवक निरंतर सीखने वाला, एक 'नागरिक-चैंपियन' और भारत की आकांक्षाओं का एक आत्मविश्वासी संरक्षक होगा।

विकसित भारत 2047 के लक्ष्य

सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज से लेकर शून्य शुद्ध उत्सर्जन के संकल्प तक, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना से लेकर वैश्विक विनिर्माण नेतृत्व तक, केवल नीतिगत माध्यम से पूरे नहीं होंगे। वे लोगों के माध्यम से पूरे होंगे: उस जिला अधिकारी द्वारा जो योजना को सही ढंग से समझ कर उसे पूरी शुद्धता के साथ लागू कर सके; उस शहरी योजनाकार द्वारा जो स्थानिक डेटा टूल का उपयोग कर सके; उस अग्रिम पंक्ति के स्वास्थ्य कार्यकर्ता द्वारा जो सार्वजनिक स्वास्थ्य अलर्ट को इस तरह संप्रेषित करे कि उसका समुदाय उस पर भरोसा करे। मिशन कर्मयोगी न केवल कल के लिए, बल्कि आने वाले दशकों के लिए उसी दल का निर्माण कर रहा है। भारत की शासन-व्यवस्था की कहानी के लंबे और प्रकाशमान सफर में, यह शायद वह अध्याय है जिसमें शासन ने आखिरकार 'सीखना' सीख लिया।

(लेखक केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञान राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा प्रधानमंत्री कार्यालय, परमाणु ऊर्जा विभाग, अंतरिक्ष विभाग और कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन राज्यमंत्री हैं)

भारत के लिए मुद्रा योजना बनी सूक्ष्म उद्यमों की ताकत

डॉ. मयंक चतुर्वेदी (हि.स)

भारत की अर्थव्यवस्था की जड़ों में यदि किसी क्षेत्र की सबसे अधिक भूमिका है, तो वह है सूक्ष्म और लघु उद्यमों का विशाल नेटवर्क की। यही कारण है कि वर्ष 2015 में शुरू की गई 'प्रधानमंत्री मुद्रा योजना' ने बीते एक दशक में देश के करोड़ों लोगों को वित्तीय सहारा देने के साथ आर्थिक संरचना को भीतर से मजबूत करने का कार्य किया है। हालिया फैक्ट-शीट के अनुसार, इस योजना के तहत अब तक 52.37 करोड़ से अधिक ऋण स्वीकृत किए जा चुके हैं और इनके माध्यम से 33.65 लाख करोड़ रुपये की राशि वितरित की गई है।

वस्तुतः भारत में लंबे समय तक छोटे उद्यमियों के सामने सबसे बड़ी समस्या रही है कि बिना गारंटी के सुलभ ऋण की उपलब्धता कैसे संभव हो सकती है। पारंपरिक बैंकिंग व्यवस्था में जटिल प्रक्रियाओं और गारंटी की शर्तों के कारण छोटे कारोबारी अक्सर वित्तीय सहायता से वंचित रह जाते थे। ऐसे में मुद्रा योजना ने इस बाधा को तोड़ते हुए बैंक, एनबीएफसी और माइक्रोफाइनेंस संस्थानों के माध्यम से बिना गारंटी ऋण उपलब्ध कराकर उद्यमिता को नई दिशा दी। यही कारण है कि विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसी वैश्विक संस्थाओं ने भारत में वित्तीय समावेशन की दिशा में इस प्रकार के प्रयासों को महत्वपूर्ण माना है। विश्व बैंक की रिपोर्टों में यह स्पष्ट किया गया है कि वित्तीय पहुंच का विस्तार आर्थिक असमानता को कम करने और विकास को समावेशी बनाने में निर्णायक भूमिका निभाता है।

मुद्रा योजना की सबसे उल्लेखनीय उपलब्धियों में से एक है महिलाओं की बढ़ती भागीदारी। कुल ऋणों में लगभग 70 प्रतिशत महिला उद्यमियों को दिए गए हैं, जोकि यह दशार्ता है कि उक्त योजना सामाजिक परिवर्तन का भी माध्यम बनी है। ग्रामीण और अर्धशहरी क्षेत्रों में महिलाएं अब स्वरोजगार के माध्यम से आत्मनिर्भर बन रही हैं और अपने परिवारों की आर्थिक स्थिति को भी मजबूत कर रही हैं।

नीति आयोग की विभिन्न रिपोर्टों में इस तथ्य को रेखांकित किया गया है कि महिलाओं की आर्थिक भागीदारी बढ़ने से समग्र विकास दर पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है और सामाजिक संतुलन भी मजबूत होता है। इसी तरह, सामाजिक न्याय की दृष्टि से भी यह योजना अत्यंत प्रभावी साबित हुई है। लगभग 50 प्रतिशत ऋण अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लाभार्थियों को दिए गए हैं। वस्तुतः यह आंकड़ा इस बात का प्रमाण है कि योजना ने आर्थिक अवसरों को समाज के उन वर्गों तक पहुंचाया है। इसके साथ ही भारतीय रिजर्व बैंक की रिपोर्टों में भी इस बात पर बल दिया गया है कि समावेशी विकास के लिए वित्तीय संसाधनों का समान वितरण आवश्यक है और मुद्रा योजना इस दिशा में एक मजबूत कदम है। दरअसल योजना की संरचना को देखें तो इसे तीन प्रमुख श्रेणियों शिशु, किशोर और तरुण में विभाजित किया गया है, जिसे कि उद्यमों के विभिन्न विकास चरणों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। शिशु श्रेणी में 50 हजार रुपये तक के ऋण दिए जाते हैं और कुल ऋणों का लगभग 78 प्रतिशत इसी श्रेणी में है।

वस्तुतः यह दशार्ता है कि देश में बड़ी संख्या में लोग छोटे स्तर पर व्यवसाय शुरू कर रहे हैं। वहीं किशोर श्रेणी, जिसमें 50 हजार से पांच लाख रुपये तक के ऋण शामिल हैं। कुल संख्या का लगभग 20 प्रतिशत है, लेकिन राशि के लिहाज से इसकी हिस्सेदारी 40 प्रतिशत है। इससे यह संकेत मिलता है कि छोटे व्यवसाय अब विस्तार की ओर बढ़ रहे हैं। तरुण श्रेणी में पांच से 10 लाख रुपये तक के ऋण दिए जाते हैं, जिसकी संख्या भले ही सिर्फ दो प्रतिशत है, किंतु कुल राशि में इसकी हिस्सेदारी 24 प्रतिशत है, जोकि यह दशार्ती है कि विकसित हो रहे उद्यमों की पूंजी आवश्यकताएं तेजी से बढ़ रही हैं।

सरकार ने इस योजना को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए 'तरुण प्लस' श्रेणी की शुरूआत की है जिसके तहत 10 लाख से 20 लाख रुपये तक का ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। यह उन उद्यमियों के लिए एक बड़ा अवसर है, जिन्होंने पहले मुद्रा ऋण लेकर अपने व्यवसाय को सफलतापूर्वक स्थापित किया है और अब उसे आगे बढ़ाना चाहते हैं। इसके साथ ही 'क्रेडिट गारंटी फंड फॉर माइक्रो यूनिट्स' के माध्यम से ऋण पर गारंटी कवरेज प्रदान किया जा रहा है, जिससे वित्तीय संस्थानों का जोखिम कम होता है और उद्यमियों को आसानी से ऋण मिल पाता है।

यहां अच्छी बात यह है कि मुद्रा योजना का प्रभाव व्यक्तिगत स्तर तक सीमित न होकर इसका व्यापक आर्थिक प्रभाव भी देखने को मिला है। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन की रिपोर्टों के अनुसार, छोटे और सूक्ष्म उद्यम विकासशील देशों में रोजगार सृजन का सबसे बड़ा स्रोत होते हैं। भारत में भी इस योजना के माध्यम से करोड़ों लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार मिला है। इससे देश की बेरोजगारी में कमी आई है, साथ में स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं को भी मजबूती मिली है। इसके अतिरिक्त, यह योजना असंगठित क्षेत्र को औपचारिक अर्थव्यवस्था में लाने का एक महत्वपूर्ण माध्यम भी बनी है। जब कोई उद्यमी बैंकिंग प्रणाली से जुड़ता है, तो उसका वित्तीय रिकॉर्ड तैयार होता है, जिससे उसे भविष्य में और अधिक वित्तीय अवसर प्राप्त होते हैं। विश्व आर्थिक मंच ने भी अपनी रिपोर्टों में भारत को डिजिटल और वित्तीय समावेशन के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ती अर्थव्यवस्था के रूप में स्वीकार किया है और मुद्रा योजना इस परिवर्तन की एक महत्वपूर्ण कड़ी है।

इस तरह समग्र रूप से देखें और इसके बारे में कहें तो आज यही कहना होगा कि कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ने भारत की अर्थव्यवस्था में एक संरचनात्मक परिवर्तन की नींव रखी है। यह योजना उद्यमिता को प्रोत्साहित करने, सामाजिक समावेशन को बढ़ावा देने और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को साकार करने का एक सशक्त माध्यम है। आने वाले समय में यदि इसे कौशल विकास, डिजिटल प्लेटफॉर्म और वैश्विक बाजारों से जोड़ दिया जाएगा तो यह भारत को विश्व की अग्रणी उद्यमशील अर्थव्यवस्थाओं में स्थापित करने में निर्णायक भूमिका निभा सकती है। देखते हैं भारत सरकार अब इस बारे में क्या निर्णय लेती है!

मान सरकार द्वारा सार्वजनिक सेवाओं में सुधार के लिए लंबित आर.सी. और ड्राइविंग लाइसेंस आवेदनों के समयबद्ध निपटारे के निर्देश: हरपाल चीमा

देरी वाले आवेदनों की सख्त निगरानी के आदेश; परिवहन विभाग में लंबित कार्यों के लिए जवाबदेही तय की जाएगी: हरपाल सिंह चीमा

सिटी दर्पण संवाददाता
चंडीगढ़

पंजाब के वित्त, परिवहन, आबकारी एवं कर मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा ने रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (आर.सी.) और ड्राइविंग लाइसेंस (डी.एल.) जारी करने से जुड़े मुद्दों के समाधान के लिए आज यहां परिवहन विभाग की एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में परिवहन सचिव वरुण रूजम, स्टेट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर परनीत शेरगिल, सचिव आर.टी.ए., आर.टी.ओ. और विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।

परिवहन मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने बताया कि सार्वजनिक सेवाओं को सुचारू बनाने के उद्देश्य से परिवहन विभाग की व्यापक समीक्षा की गई, जिसमें मुख्य ध्यान आर.सी. और ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने से संबंधित समस्याओं के समाधान पर केंद्रित था।

उन्होंने कहा कि वर्तमान में सत्यापन और अनुमोदन स्तर पर लंबित सभी आवेदनों का सख्त संज्ञान लिया गया है और अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि इन लंबित आवेदनों का जल्द से जल्द निपटारा किया जाए।

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार की प्रतिबद्धता दोहराते हुए उन्होंने कहा कि सरकार समयबद्ध सार्वजनिक सेवाएं प्रदान करने के लिए वचनबद्ध है और निर्धारित समय सीमा से अधिक देरी वाले सभी मामलों की बारीकी से निगरानी की जाएगी।

उन्होंने आगे बताया कि जवाबदेही सुनिश्चित करने और प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए विभाग द्वारा लंबित आवेदनों के साथ-साथ देरी के कारणों का विस्तृत डेटा भी एकत्र किया जा रहा है। डिजिटल गवर्नेंस पर जोर देते हुए मंत्री ने कहा कि फेसलेस और संपर्क रहित माध्यम से दी जा रही ड्राइविंग लाइसेंस सेवाओं की समीक्षा की गई है और अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि इन श्रेणियों में लंबित आवेदनों का समय पर निपटारा सुनिश्चित किया जाए।

नागरिकों को हो रही परेशानियों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि केंद्रीकृत प्रिंटिंग शाखा में आर.सी. और ड्राइविंग लाइसेंस की छपाई के बैकलॉग को प्राथमिकता के आधार पर समाप्त किया जाएगा और इसके लिए सख्त निर्देश जारी किए गए हैं। सड़क सुरक्षा और परिवहन संचालन के संदर्भ में उन्होंने बताया कि पूरे पंजाब में बेहतर ट्रैफिक प्रबंधन और सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हाईवे ट्रैफिक कैमरों की तैनाती और निगरानी पर भी विस्तार से चर्चा की गई है। उन्होंने आगे कहा कि हमने परिवहन नेटवर्क की कुशलता भरोसेयोगिता और पहुंच को ओर अधिक यकीनी बनाने के लिए समय-सारिणी की समीक्षा कर और शेष रूटों को ध्यान में रखते हुए परिवहन सेवाओं को अधिक कुशल, विश्वसनीय और सुलभ बनाने पर भी काम किया जा रहा है।

भगवंत सिंह मान सरकार की रोजगार क्रांति: हरपाल चीमा ने 11 जूनियर ऑडिटरों को सौंपे नियुक्ति पत्र

सिटी दर्पण संवाददाता
चंडीगढ़

पंजाब के वित्त मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा ने मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में चल रही ह्यरोजगार क्रांतिह्न पहल के तहत एक औपचारिक समारोह के दौरान नव-नियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे और पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से चयनित 11 उम्मीदवारों को एग्जामिनर, लोकल फंड अकाउंट्स के कार्यालय में जूनियर ऑडिटर के रूप में शामिल किया।

नव-नियुक्त अधिकारियों को बधाई देते हुए वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने सार्वजनिक सेवा में ईमानदारी और जिम्मेदारी के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा, मैं सभी नव-नियुक्त युवाओं को दिल से बधाई देता हूं और उनसे अपील करता हूं कि वे अपनी प्रशासनिक जिम्मेदारियों को पूरी लगन, पारदर्शिता और ईमानदारी के साथ निभाएं। राज्य की सार्वजनिक संस्थाओं की वित्तीय सेहत और जवाबदेही बनाए रखने के लिए आपकी ईमानदारी अत्यंत आवश्यक है।

भर्ती प्रक्रिया की विश्वसनीयता को रेखांकित करते हुए वित्त मंत्री चीमा ने बताया कि यह पूरी प्रक्रिया पंजाब लोक सेवा आयोग (पी.पी.एस.सी.) के माध्यम से सख्ती से मेरिट के आधार पर संपन्न की गई है। उन्होंने कहा, यह भर्ती अभियान पूरी तरह मेरिट आधारित रहा है। मुझे विश्वास है कि इस नई और योग्य प्रतिभा के शामिल होने से वित्त विभाग के अंतर्गत एग्जामिनर, लोकल फंड अकाउंट्स विंग की कार्यकुशलता और समग्र उत्पादकता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। रोजगार सृजन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए उन्होंने मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में अब तक की गई प्रगति का उल्लेख किया। उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के गतिशील नेतृत्व में पंजाब सरकार अब तक 65,000 से अधिक युवाओं को सुरक्षित रोजगार प्रदान करने में सफल रही है। यह उपलब्धि राज्य के प्रतिभाशाली युवाओं को स्थायी रोजगार उपलब्ध कराने के वादे की ऐतिहासिक पूर्ति है।

रोजगार पर निरंतर ध्यान देने की आवश्यकता पर जोर देते हुए वित्त मंत्री ने कहा, ह्यरोजगार क्रांतिह्न पंजाब सरकार की एक प्रमुख प्राथमिकता है। हम यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि सभी विभागों में एक मजबूत, कुशल और युवाओं के नेतृत्व वाला प्रशासनिक ढांचा तैयार करने के लिए पारदर्शी भर्ती प्रक्रियाओं का निरंतर पालन किया जाए।

हलवारा हवाई अड्डा उड़ानों के लिए पूरी तरह तैयार; बुकिंग जल्द होगी शुरू, 15 मई से उड़ानें शुरू; कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा ने पहली टिकटें कीं बुक

सिटी दर्पण संवाददाता
चंडीगढ़

पंजाब की औद्योगिक राजधानी लुधियाना क्षेत्रीय संपर्क को बेहतर बनाने की दिशा में एक बड़ी छलांग लगाने के लिए पूरी तरह तैयार है, क्योंकि हलवारा हवाई अड्डे से 15 मई, 2026 को उड़ानें शुरू हो जाएंगी और जल्द ही फ्लाइट बुकिंग भी शुरू होगी। शुरूआत में एयर इंडिया की दो उड़ानें लुधियाना को दिल्ली से जोड़ेंगी, जिससे 30 वर्षों का सपना साकार होगा।

कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा ने अपनी पत्नी के साथ 15 मई, 2026 को दिल्ली से हलवारा जाने वाली पहली फ्लाइट बुक करवाई है, जो इस ऐतिहासिक सफर में एक निजी और सार्वजनिक मील का पत्थर है। एयरलाइन सूत्रों के अनुसार, दिल्ली-लुधियाना-दिल्ली सेक्टर की टिकटें तेजी से बिक रही हैं। उड़ानों की शुरूआत निरंतर प्रयासों का परिणाम है, जो संजीव अरोड़ा की क्षेत्रीय संपर्क को मजबूत करने और पंजाब, विशेष रूप से लुधियाना और इसके आसपास के जिलों के आर्थिक विकास में तेजी लाने की दृढ़ प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में राज्य सरकार ने इस लंबे समय से लंबित परियोजना को पुनर्जीवित करने और इसमें तेजी लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिससे लुधियाना के निकट एक कार्यशील हवाई अड्डे का सपना साकार होगा।

हलवारा हवाई अड्डे के चालू होने से व्यापार, उद्योग और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा तथा निवासियों और व्यावसायिक समुदाय को निर्बाध यात्रा सुविधा मिलेगी। इससे निर्यातकों, उद्योगपतियों और उद्यमियों के लिए बेहतर संपर्क सुनिश्चित होगा, जिससे लुधियाना की स्थिति एक प्रमुख आर्थिक केंद्र के रूप में और मजबूत होगी।

युद्ध नशेयां विरुद्ध के 13 महीने: 2458 किलो हेरोइन सहित 56 हजार से अधिक नशा तस्कर गिरफ्तार

चंडीगढ़। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के निर्देशों पर शुरू की गई नशों के खिलाफ निर्णायक मुहिम ह्ययुद्ध नशेयां विरुद्धह्न के 13 महीने पूरे हो गए हैं। पंजाब पुलिस ने 1 मार्च 2025 से अब तक 39,760 एफआईआर दर्ज करते हुए 56,372 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया है। इस दौरान पुलिस ने तस्करों से 2458 किलो हेरोइन भी बरामद की है। इस मुहिम की शुरूआत के बाद, पंजाब पुलिस द्वारा डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस (डीजीपी) पंजाब गौरव यादव के निर्देशों के तहत राज्य के सभी 28 पुलिस जिलों में रोजाना एक ही समय पर ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने पुलिस कमिश्नरों, डिप्टी कमिश्नरों और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों को पंजाब को नशा मुक्त राज्य बनाने के निर्देश दिए हैं। विशेष डीजीपी कानून एवं व्यवस्था अर्पित शुक्ला ने बताया कि 2458 किलो हेरोइन के अलावा पुलिस ने 724 किलो अफीम, 345 क्विंटल भुक्की, 69 किलो चरस, 843 किलो गांजा, 37 किलो आईसीई, 51 लाख नशीली गोलियां/कैप्सूल और 17.28 करोड़ रुपये की ड्रग मनी भी जब्त की है। पंजाब पुलिस ने नशों के खिलाफ इस अभियान के 396वें दिन 86 नशा तस्करों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 269 ग्राम हेरोइन, 1000 नशीली गोलियां/कैप्सूल और 3050 रुपये की ड्रग मनी बरामद की है। इसके साथ ही केवल 396 दिनों में गिरफ्तार किए गए कुल तस्करों की संख्या 56,458 हो गई है। यह भी उल्लेखनीय है कि नशा छुड़ाओ अभियान के तहत आज 21 व्यक्तियों को नशा छोड़ने और पुनर्वास के लिए उपचार लेने हेतु प्रेरित किया गया। इसके साथ ही पुलिस टीमों ने लगातार 71वें दिन ह्यगैंगस्टरां ते वारह्न अभियान जारी रखते हुए 483 छापेमारी के बाद 184 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया। इसके अलावा 87 व्यक्तियों के खिलाफ एहतियाती कार्रवाई की गई और पांच भगोड़े अपराधियों (पी.ओ.) को गिरफ्तार किया गया। उल्लेखनीय है कि लोग एंटी-गैंगस्टर हेल्पलाइन नंबर 93946-93946 के माध्यम से वांछित अपराधियों और गैंगस्टरों से संबंधित जानकारी गोपनीय रूप से दे सकते हैं तथा अपराध और आपराधिक गतिविधियों के बारे में भी सूचना साझा कर सकते हैं।

19,000 आशा कार्यकर्ता मुख्यमंत्री सेहत योजना के राज्यव्यापी सेहत कार्ड पंजीकरण अभियान से जुड़े

सिटी दर्पण संवाददाता
चंडीगढ़

इलाज के खर्च के कारण कोई परिवार परेशान न हो, भगवंत मान सरकार घर-घर पहुंचा रही स्वास्थ्य की गारंटी: डॉ. बलबीर सिंह जी

स्वास्थ्य सेवाओं की अंतिम पंक्ति तक पहुंच को और मजबूत करते हुए, मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान जी के नेतृत्व में पंजाब सरकार ने मुख्यमंत्री सेहत योजना के तहत पंजीकरण प्रक्रिया को तेज करने के लिए अपने व्यापक आशा कार्यकर्ता नेटवर्क को सक्रिय किया है। इस अभियान के तहत 19,000 से अधिक आशा कार्यकर्ता और 900 सहायक पंजाब के गांवों में पंजीकरण को गति दे रहे हैं।

आशा कार्यकर्ता इस योजना की पहुंच को जमीनी स्तर तक विस्तारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। प्रत्येक कार्यकर्ता को लगभग 1,000 लोगों और करीब 250 परिवारों की ज़िम्मेदारी सौंपी गई है, जहां वे घर-घर जाकर जागरूकता फैला रहे हैं और परिवारों को सेवा केंद्रों तथा कॉमन सर्विस सेंटरों में पंजीकरण के लिए सहयोग प्रदान कर रहे हैं। यह पहल विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में यह सुनिश्चित कर रही है कि योजना की जानकारी सीधे हर घर तक पहुंचे और पंजीकरण एवं सत्यापन की प्रक्रिया बिना किसी भ्रम या देरी के सुचारु रूप से पूरी हो सके।

जमीनी स्तर पर किए जा रहे इस निरंतर प्रयास का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। पिछले 20 दिनों में ही आशा कार्यकताओं के माध्यम से लगभग 10 लाख पंजीकरण किए गए हैं, जिससे पूरे पंजाब में स्वास्थ्य कवरेज का दायरा तेजी से बढ़ा है। इस गति को बनाए रखने के लिए आशा कार्यकताओं को सफल पंजीकरण पर प्रोत्साहन दिया जा रहा है, जिससे जवाबदेही और निरंतर कार्य सुनिश्चित हो सके।

इस पहल के उद्देश्य पर प्रकाश डालते हुए, पंजाब के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. बलबीर सिंह जी ने कहा, मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान जी ने स्पष्ट कर दिया है कि पंजाब में कोई भी परिवार इलाज के खर्च के कारण परेशान नहीं होना चाहिए। हमारे आशा कार्यकर्ता इस भरोसे को लोगों के घर तक पहुंचा रहे हैं, ताकि हर परिवार योजना से अवगत हो और आसानी से पंजीकरण कर सके। यह केवल कागजों तक सीमित योजना नहीं है, बल्कि एक ऐसी गारंटी है जिसे हम हर घर तक पहुंचा रहे हैं।

मुख्यमंत्री सेहत योजना का दायरा लगातार बढ़ रहा है। वर्तमान में प्रतिदिन लगभग 50,000 लोग पंजीकरण कर रहे हैं और अब तक 35 लाख से अधिक सेहत कार्ड जारी किए जा चुके हैं। लुधियाना, पटियाला और जालंधर जैसे जिले पंजीकरण के मामले में अग्रणी बने हुए हैं, जो शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में व्यापक भागीदारी को दर्शाता है।

पंजीकरण के साथ-साथ योजना के तहत स्वास्थ्य सेवाएं भी तेजी से प्रदान की जा रही हैं। अब तक 300 करोड़ से अधिक की कुल लागत वाले 2 लाख से अधिक उपचार किए जा चुके हैं, जिनमें 40,000 से अधिक सर्जिकल प्रक्रियाएं शामिल हैं। इन उपचारों में हृदय रोग, डायलिसिस, अस्थि शल्य चिकित्सा (आर्थोपेडिक्स), कैंसर उपचार और आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं प्रमुख रूप से शामिल हैं। योजना के विस्तार के लिए पंजाब बजट 2026-27 में 2,000 करोड़ का प्रावधान भी किया गया है।

जोगिंद्रा ग्रुप का स्टील में 700 करोड़ और नवीकरणीय ऊर्जा में 400 करोड़ का निवेश पंजाब में निवेशकों के बढ़ते विश्वास को दर्शाता है: अरोड़ा

जोगिंद्रा ग्रुप द्वारा किया जा रहा 1,100 करोड़ रुपये का निवेश पंजाब के औद्योगिक विकास और ग्रीन ऊर्जा को बड़ा बढ़ावा देगा: संजीव अरोड़ा

सिटी दर्पण संवाददाता
चंडीगढ़

पंजाब के उद्योग और वाणिज्य, निवेश प्रोत्साहन, बिजली तथा स्थानीय निकाय मंत्री संजीव अरोड़ा ने बताया कि जोगिंद्रा ग्रुप द्वारा 1,100 करोड़ रुपये के निवेश के साथ रणनीतिक विस्तार की योजना की घोषणा की गई है, जिससे पंजाब के औद्योगिक विकास और ग्रीन ऊर्जा के उपयोग को बड़ा बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि यह निवेश पंजाब की प्रगतिशील नीतियों और कारोबार अनुकूल माहौल के प्रति उद्योगों के बढ़ते विश्वास को दर्शाता है।

संजीव अरोड़ा ने कहा कि यह निवेश पंजाब की प्रगतिशील नीतियों और कारोबार अनुकूल माहौल के प्रति उद्योगों के बढ़ते विश्वास को दर्शाता है।

जोगिंद्रा ग्रुप द्वारा किए जा रहे विस्तार से रोजगार के अवसर पैदा होंगे, क्षमता में वृद्धि होगी और पंजाब के औद्योगिक आधार को मजबूती मिलेगी: संजीव अरोड़ा

उन्होंने बताया कि इस विस्तार के तहत स्टील क्षेत्र में 700 करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा, जो मुख्य रूप से जोगिंद्रा कास्टिंग्स और वर्धमान आदर्श के माध्यम से किया जाएगा। इसमें जोगिंद्रा ग्रीन इंडिया के माध्यम से नवीकरणीय ऊर्जा में 400 करोड़ रुपये का निवेश शामिल है।

इस विस्तार की महत्वता को रेखांकित करते हुए संजीव अरोड़ा ने कहा, जोगिंद्रा ग्रुप का टर्नओवर 3,000 करोड़ रुपये से बढ़कर 5,000 करोड़ रुपये होने की संभावना है और इसके कर्मचारियों की संख्या 1,800 से बढ़कर 3,000 हो जाएगी, जिससे रोजगार के बड़े अवसर पैदा होंगेह्व उन्होंने आगे कहा कि नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 37 मेगावाट से बढ़कर 120 मेगावाट हो जाएगी।

जोगिंद्रा ग्रुप के पृष्ठभूमि के बारे में जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि 1992 में स्थापित जोगिंद्रा ग्रुप उत्तरी भारत की एक अग्रणी औद्योगिक समूह है, जो स्टील निर्माण के क्षेत्र में निरंतर कार्यरत है और यह कंपनी नवीकरणीय ऊर्जा में भी पैर पसार रही है। उन्होंने आगे कहा, इस ग्रुप की अगुवाई सीएमडी आदर्श गर्ग द्वारा डायरेक्टर संजय गुप्ता और निमित गुप्ता के साथ की जाती है।

इस संबंध में क्षेत्रीय प्रभाव पर प्रकाश डालते हुए संजीव अरोड़ा ने कहा कि मंडी गोबिंदगढ़ हमेशा से पंजाब के स्टील उद्योग की रीढ़ की हड्डी रहा है।

उन्होंने कहा, आज भगवंत मान सरकार के अधीन यह नए निवेश, आधुनिकीकरण और साफ-सुथरे तथा अधिक कुशल उत्पादन के साथ अपनी स्थिति को और मजबूत कर रहा है। जोगिंद्रा ग्रुप द्वारा किया गया विस्तार इस बात का स्पष्ट संकेत है कि गोबिंदगढ़ एक बार फिर पंजाब की औद्योगिक अर्थव्यवस्था के लिए विकास का मुख्य केंद्र बन रहा है।

उन्होंने आगे कहा कि पंजाब निर्माण और ग्रीन ऊर्जा में निवेश के लिए एक पसंदीदा स्थान के रूप में उभर रहा है और यह 1,100 करोड़ रुपये का निवेश औद्योगिक आधार को मजबूत करेगा, रोजगार के महत्वपूर्ण अवसर पैदा करेगा और स्थायी विकास को सुनिश्चित करेगा।

भगवंत मान सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए मंत्री ने कहा, आप सरकार उद्योग अनुकूल माहौल प्रदान करने, कारोबार करने में आसानी सुनिश्चित करने और पूरे सूबे में पर्यावरण संरक्षण पर केंद्रित निवेशों को प्रोत्साहित करने के लिए वचनबद्ध है।

संक्षिप्त-समाचार

भारत-पाकिस्तान अटारी-बाघा सीमा पर रिट्रीट सेरेमनी का समय बदला

चंडीगढ़। भारत-पाकिस्तान अटारी-बाघा सीमा पर रिट्रीट सेरेमनी के समय में बुधवार से बदलाव कर दिया गया। यहां रोजाना हजारों की संख्या में देश के विभिन्न हिस्सों से लोग पहुंचते हैं। इस बदलाव के बाद उम्मीद है कि लोग समय से पहुंचकर इस अद्भुत दृश्य का आनंद ले पाएंगे। बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी भारत और पाकिस्तान के सैनिकों द्वारा की जाने वाली एक विशेष परंपरा है, जिसमें जोश, अनुशासन और देशभक्ति की झलक देखने को मिलती है। सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) ने लोगों से अपील की है कि वे समय का विशेष ध्यान रखें और निर्धारित समय से पहले ही पहुंचकर अपनी सीट सुनिश्चित करें, ताकि किसी प्रकार की असुविधा न हो। नए नियम के अनुसार अब रिट्रीट सेरेमनी शाम 5:30 बजे से शुरू होकर 6:00 बजे तक चलेगी। इससे पहले रिट्रीट सेरेमनी 5 बजे शुरू होकर साढ़े 5 बजे खत्म होती थी। मौसम और दिन की घटती-बढ़ती रोशनी को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने यह फैसला लिया है। अधिकारियों का कहना है कि दर्शकों को बेहतर अनुभव देने और सुरक्षा व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने के लिए समय में यह बदलाव जरूरी था। रिट्रीट का नया समय 1 अप्रैल से लागू कर दिया गया है।

घनौर में 9 सालों से कोई विकास नहीं, बुनियादी सुविधाएं नदारद: सरबजीत सिंह झिंजर

घनौर। युवा अकाली दल के प्रधान सरबजीत सिंह झिंजर ने अपने हलके का दौरा कर स्थानीय निवासियों से मुलाकात की और उनकी समस्याओं को जाना। इस दौरान उन्होंने राजपुरा के नजदीक स्थित पंजाब एन्क्लेव और चौहान कॉलोनी में लोगों के साथ बैठकें कीं। इस अवसर पर झिंजर ने लोगों की शिकायतों को ध्यानपूर्वक सुना और आश्वासन दिया कि पिछले 9 वर्षों से रुके हुए विकास कार्यों को उनकी सरकार बनने पर प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राजपुरा के आसपास के क्षेत्रों–खासकर पंजाब एन्क्लेव और चौहान कॉलोनी–में बुनियादी सुविधाओं की स्थिति बेहद खराब है। यहां सीवरेज, पीने के पानी की आपूर्ति, नालियों और सड़कों की उचित व्यवस्था नहीं है, जिससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पूर्व की कांग्रेस और आम आदमी पार्टी सरकारों पर निशाना साधते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले 9 वर्षों में घनौर हलके में कोई खास विकास नहीं हुआ है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि इन मूलभूत समस्याओं का जल्द समाधान किया जाएगा और क्षेत्र के समग्र विकास को गति दी जाएगी।

पंजाब की भाईचारे की एकता को तोड़ नहीं सकतीं अलगाववादी ताकतें : जाखड़

चंडीगढ़। चंडीगढ़ स्थित पंजाब भाजपा मुख्यालय के बाहर हुए बम धमाके के बाद सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से कटघरे में आ गई है। भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष एवं विधायक अश्वनी शर्मा दो दिन से इसी कार्यालय में रूके हुए थे और धमाके से कुछ समय पहले ही वह दिल्ली के लिए रवाना हुए। बम धमाके के बाद पंजाब भाजपा अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने कहा कि पहले से पंजाब के थानों पर लगातार ग्रेनेड हमले हो रहे हैं। फिर बीते दिन होशियारपुर में बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति को खंडित किया गया और आज चंडीगढ़ में भाजपा के राज्य स्तरीय कार्यालय पर हमला हुआ है। यह घटनाओं की श्रृंखला राज्य की साम्प्रदायिक एकता को तोडऩे की कोशिशों का संकेत है। दूसरी ओर सीमावर्ती राज्य की सरकार इन सबको रोकने में असफल साबित हो रही है, जिसके कारण अब पंजाब की बिगड़ती कानून-व्यवस्था की स्थिति का असर चंडीगढ़ तक पहुंचने लगा है। अलगाववादी ताकतें चाहे जितनी भी कोशिश कर लें, वे पंजाब की भाईचारे की एकता को तोड़ नहीं सकतीं। ाजपा के प्रवक्ता आरपी सिंह ने कहा कि चंडीगढ़ में भाजपा पंजाब कार्यालय के बाहर बम ब्लास्ट की घटना चौंकाने वाली और बेहद चिंताजनक है। गंभीर बात यह है कि पंजाब भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष अश्विनी शर्मा पिछले दो दिनों से उसी कार्यालय में मौजूद थे और कुछ समय पहले ही दिल्ली में एक राजनीतिक कार्यक्रम के लिए रवाना हुए हैं। उन्होंने कहा कि 15 दिन पहले पठानकोट के एसएसपी ने उन्हें एक विशिष्ट खतरे की आशंका के चलते अपनी मॉर्निंग वॉक रोकने की चेतावनी दी थी। यह चेतावनी और आज का ब्लास्ट दोनों में कोई संबंध है या नहीं, यह जांच का विषय है, लेकिन इस संयोग को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यह केवल एक नेता या एक पार्टी कार्यालय की बात नहीं है। यह पंजाब में सुरक्षा, खुफिया समन्वय और समग्र कानून-व्यवस्था की स्थिति पर गंभीर सवाल उठाता है। जिम्मेदार लोगों की पहचान की जानी चाहिए और उन्हें जल्द से जल्द न्याय के कटघरे में लाया जाना चाहिए। ऐसे आतंकवादी कृत्यों के लिए शून्य सहनशीलता होनी चाहिए।ेंद्रीय राज्यमंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने कहा कि पिछले एक हफ्ते से इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। पहले अमृतसर थाने में धमाका हुआ। फिर जालंधर में हुआ। इसे पुलिस ने कवर किया। अब यह चंडीगढ़ तक पहुंच गए हैं। अब यह कहेंगे कि चंडीगढ़ तो सेंटर के अ ीन आता है। चंडीगढ़ के एसएसपी भी पंजाब से आते हैं। हम तो बहुत दिनों से कह रहे थे कि हालत बिगड़ रहे हैं। पंजाब से ये चीजें आ रही हैं।

ए.बी.सी. प्रोग्राम के तहत वार्ड नंबर 8, 9, 10 और 11 में आवारा कुत्तों की स्टेरलाइजेशन पूरी

जालंधर। जिला प्रशासन की हिदायतों पर नगर निगम जालंधर द्वारा लगातार किए गए प्रयासों के कारण शहर के 21 वार्डों को पूरी तरह बेसहारा पशुओं से मुक्त करने में सफलता हासिल की गई है। डिप्टी कमिश्नर डा. हिमांशु अग्रवाल ने आज यहां सोसाइटी फॉर प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स, जिला पशु भलाई सोसाइटी और एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स 2023 संबंधी समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए बेसहारा पशुओं और नागरिकों दोनों की सुरक्षा सुनिश्चित बनाने की वचनबद्धता दोहराई। उन्होंने बताया कि नगर निगम की टीमों द्वारा विभिन्न वार्डों की चेकिंग करके बेसहारा पशुओं को गौशालाओं में पहुंचाया गया, जिससे शहर के अंदरूनी हिस्सों में बेसहारा पशुओं की समस्या को सफलतापूर्वक निपटाया गया है। उन्होंने बताया कि इस संबंध में नगर निगम को संबंधितों द्वारा वार्ड बेसहारा पशु मुक्त होने संबंधी सर्टिफिकेट भी सौंपे गए है।

डब्लूयूडी में वर्ष 2026-27 के लिए डिजाइन, बिजनेस और टेक्नोलॉजी प्रोग्राम्स में प्रवेश शुरू

चंडीगढ़। वर्ल्ड युनिवर्सिटी ऑफ डिजाइन (डब्लूयूडी) ने विज्ञान, वाणिज्य और कला जैसे सभी अकादमिक पृष्ठभूमि से आने वाले विद्यार्थियों को डिजाइन, टेक्नोलॉजी और रचनात्मक अर्थव्यवस्था में उभरते करियर के मार्गों में संभावना तलाशने के लिए आमंत्रित किया है। आज के तेजी से उभर रहे पेशेवर परिदृश्य में करियर में सफलता एक स्कूली क्षेत्र तक सीमित नहीं रह गई है। डिजाइन एक ताकतवर, अंतरक्षेत्रीय क्षेत्र के तौर पर उभरा है जो रचनात्मकता को टेक्नोलॉजी, बिजनेस और मानव केंद्रित नवप्रवर्तन के साथ एकीकृत करते हुए विविध रुचियों और क्षमताओं वाले विद्यार्थियों के लिए अवसरों के द्वार खोल रहा है। प्रवेश डब्लूयूडी एप्टीट्यूड टेस्ट (डब्लूयूडीएटी) 2026 के जरिए लिया जाएगा जो 11 एवं 12 अप्रैल, 2026 को प्रस्तावित है। इसके बाद, छांटे गए उम्मीदवारों के लिए एक कैंपस इंटरव्यू होगा। इस अवसर पर, वर्ल्ड युनिवर्सिटी ऑफ डिजाइन के कुलपति डाक्टर संजय गुप्ता ने कहा कि आज कई विद्यार्थी बोर्ड के परिणाम आने के बाद खुद को एक असमंजस की स्थिति में पाते हैं खासकर वे लोग जो परंपरागत रास्तों पर जाना नहीं चाहते। डब्लूयूडी में हम विद्यार्थियों को विज्ञान, वाणिज्य या कला जैसे लेबल से परे देखने के लिए प्रोत्साहित करते हैं ताकि वे उन चीजों को तलाशें जहां सही मायने में उनकी उत्सुकता और ताकत मौजूद है। डिजाइन की शिक्षा आज केवल ड्राइंग के बारे में नहीं है, बल्कि यह वास्तविक दुनिया की समस्याओं को हल करने, सार्थक अनुभवों का सृजन करने और सभी उद्योगों में भविष्य को आकार देने के बारे में है।

पीटीसी पंजाबी और पीटीसी न्यूज चैनल डीडी फ्री डिश पर

चंडीगढ़। दुनिया के सबसे बड़े पंजाबी टेलीविजन नेटवर्क पीटीसी नेटवर्क के मशहूर चैनल पीटीसी पंजाबी और पीटीसी न्यूज 1 अप्रैल से डीडी फ्री डिश पर देखे जा सकते हैं। जल्द ही पीटीसी गोल्ड - को लॉन्च करके अपने प्रसारण क्षेत्र में एक बड़े विस्तार की घोषणा की है। इस लॉन्च के तहत पूरे भारत में दर्शक इन चैनलों को देख सकेंगे: पीटीसी पंजाबी चैनल नंबर 59 पर, पीटीसी न्यूज चैनल नंबर 62 पर और पीटीसी गोल्ड जल्द ही इस प्लेटफॉर्म पर जोड़ा जाएगा। डीडी फ्री डिश भारत की एकमात्र फ्री-टू-एयर डायरेक्ट-टू-होम सेवा है जो बिना किसी मासिक सब्सक्रिप्शन शुल्क के टेलीविजन देखने की सुविधा देती है। पीटीसी नेटवर्क के विभिन्न कार्यक्रम अब शहरी और ग्रामीण भारत के लाखों घरों तक बिना किसी लागत के पहुँच सकेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात ये भी है कि पीटीसी न्यूज और पीटीसी पंजाबी के माध्यम से श्री हरमंदिर साहिब (स्वर्ण मंदिर), अमृतसर से लाइव गुरबानी डीडी फ्री डिश जुड़े हर घर तक पहुँच सकेगी। पीटीसी नेटवर्क खबर, मनोरंजन और खेल के पेशकश के लिए भरोसेमंद मंच के तौर पर जाना जाता है।

अमेरिका और ईरान शांति पथ पर, ट्रंप को तीन हफ्ते में युद्ध खत्म होने की उम्मीद

सीधी बातचीत पर ईरान का इनकार, मध्यस्थों के जरिए संदेशों के आदान-प्रदान की पुष्टि

एजेंसी (हि.स.)
वाशिंगटन

- स्ट्रेट ऑफ होर्मुज की सुरक्षा से पीछे हटे कदम; ट्रंप बोले- 'दूसरे देश अपनी सुरक्षा खुद करें'

अमेरिकी-इजराइल और ईरान के बीच 28 फरवरी से चल रहे युद्ध की लपटों से तेल और गैस को लेकर मचे हाहाकार के बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दावे से राहत की कुछ उम्मीद जगी है। राष्ट्रपति ने कहा कि अमेरिका की ईरान से युद्ध रोकने पर सीधी बात हो रही है। हालांकि ईरान ने ट्रंप के इस दावे से इनकार किया है। मगर कहा है कि मध्यस्थों के जरिये संदेशों का आदान-प्रदान हुआ है।

सीबीएस न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, ट्रंप ने मंगलवार को पत्रकारों से कहा कि उन्हें उम्मीद है कि अमेरिका, ईरान के खिलाफ अपने सैन्य अभियान को दो या तीन सप्ताह में खत्म कर लेगा। उन्होंने कहा कि अमेरिका और ईरान बातचीत कर रहे हैं और यह मुमकिन है कि दोनों देश उससे पहले ही किसी समझौते पर पहुंच जाएं। उन्होंने कहा कि युद्ध खत्म करने के लिए किसी औपचारिक समझौते की जरूरत नहीं है। ईरान ने इस बात से इनकार किया है कि कोई सीधी बातचीत हो रही है। लेकिन इस बात की पुष्टि की है कि देश ने मध्यस्थों के जरिए अमेरिका के साथ संदेशों का आदान-प्रदान किया है। राष्ट्रपति ट्रंप से पूछा गया कि गैस की बढ़ी कीमतें कब कम होंगी? ट्रंप ने कहा, मुझे बस ईरान युद्ध से बाहर निकलना है और हम बहुत जल्द ऐसा करने वाले हैं। उन्होंने कहा कि ईरान के साथ युद्ध खत्म होने के बाद अगर दूसरे देशों को स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के रास्ते मिडिल ईस्ट से तेल या नेचुरल गैस आयात करने की जरूरत पड़ती है, तो उन्हें अपनी सुरक्षा खुद करनी होगी। होर्मुज में किसी के साथ कुछ भी होता है तो अमेरिका का उससे कोई लेना-देना नहीं होगा। रही बात चीन और फ्रांस जैसे दूसरे देशों की तो वह अपनी सुरक्षा करने में सक्षम हैं। इस समय तेल टैंकरों ने होर्मुज से गुजरना लगभग बंद कर दिया है। पहले ट्रंप ने वहां से गुजरने वाले जहाजों को अमेरिकी सेना की सुरक्षा देने का प्रस्ताव रखा था, लेकिन हाल में उन्होंने रुख बदल लिया है। अब वह कह रहे हैं कि इस जलमार्ग को फिर से खोलने की जिम्मेदारी उन देशों की होनी चाहिए जो मिडिल ईस्ट के तेल पर निर्भर हैं।

फोटोः हि.स.

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप आज ईरान के संबंध में राष्ट्र को करेंगे संबोधित

वाशिंगटन। व्हाइट हाउस ने घोषणा की है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कल राष्ट्र को संबोधित करेंगे। वह ईरान के संबंध में देश को महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। 28 फरवरी से अमेरिका-इजराइल और ईरान के बीच छिड़ी जंग के बीच व्हाइट हाउस की इस घोषणा से यह साफ है कि ट्रंप कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने आज सुबह एक्स पोस्ट पर लिखा, ''देखना न भूलें। आज रात 9 बजे (पूर्वी समय 'ईटी') राष्ट्रपति ट्रंप ईरान के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए राष्ट्र को संबोधित करेंगे।'' कैरोलिन की पोस्ट ऐसे समय पर आई है जब ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका और ईरान के बीच सीधी बात चल रही है। हालांकि ईरान ने इससे इनकार किया है। उसने यह जरूर माना है कि मध्यस्थों के जरिये दोनों देशों के बीच संदेशों का आदान प्रदान हुआ है।

बांग्लादेश में संवैधानिक सुधारों पर सरकार और विपक्ष में विश्वास का संकट

एजेंसी (हि.स.)
ढाका

बांग्लादेश में संवैधानिक सुधारों पर बहस तेज हो गई। इस मुद्दे पर सरकार और विपक्ष के बीच विश्वास का संकट खड़ा हो गया है। जातीय संसद में विपक्ष के नेता और बांग्लादेश जमात-ए-इस्लामी के अमीर शफीकुर रहमान ने कहा है कि संवैधानिक सुधारों पर संसदीय चर्चा के दौरान कानून मंत्री ने उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया। उन्होंने यह बात मंगलवार देररात एक ब्रीफिंग के दौरान कही। यह ब्रीफिंग 'जुलाई राष्ट्रीय चार्टर कार्यान्वयन आदेश' के तहत 'संविधान सुधार परिषद' बुलाने के प्रस्ताव पर हुई बहस के बाद हुई थी।

द डेली स्टार की रिपोर्ट के अनुसार, उन्होंने कहा, बातचीत के दौरान सत्ताधारी दल ने एक समिति बनाने का प्रस्ताव रखा। हमने कहा कि हम यहां संकट को सुलझाने आए हैं, न कि कोई नया संकट खड़ा करने। इसलिए, हम समाधान चाहते हैं। लेकिन अब यह मामला कुछ हद तक पेचीदा हो गया है। इस प्रस्ताव के संबंध में, हमने कहा कि यह नोटिस सुधार परिषद को बुलाने और उसकी बैठक से संबंधित है। यदि इस मामले को लेकर सुधार से जुड़ी कोई समिति बनाई जाती है, तो हम उसे सकारात्मक रूप से स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। विपक्ष के नेता ने आगे कहा, हालांकि, शर्त यह है कि समिति में दोनों पक्षों का समान प्रतिनिधित्व होना चाहिए। यदि सदस्यों की नियुक्ति समानता के बजाय आनुपातिक अनुपात के आधार पर की जाती है, तो किसी सकारात्मक परिणाम की संभावना बहुत कम है। शफीकुर ने कहा, जब हमने प्रस्ताव पर लचीले ढंग से विचार किया, तो कानून मंत्री ने एक भाषण दिया और मेरे बयान को गलत तरीके से पेश करते हुए कहा कि हमने संवैधानिक संशोधन के उनके प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। असल में, हमने संवैधानिक संशोधन के किसी भी प्रस्ताव पर कोई टिप्पणी नहीं की थी। हमने साफ तौर पर कहा था कि यह मामला संवैधानिक सुधार से जुड़ा है। इसलिए, मुझे उम्मीद है कि कोई गलतफहमी नहीं होगी। मेरा बयान स्पष्ट था, उसमें कोई अस्पष्टता नहीं थी। उन्होंने कहा, बाद में, जब हम इस मामले पर स्पष्टीकरण देना चाहते थे, तब तक संसदीय सत्र समाप्त हो चुका था। स्पीकर ने घोषणा कर दी कि आज की चर्चा समाप्त हो गई है। जब मैंने कहा कि हमें एक बयान देना है और बोलने का अवसर मांगा, तो उन्होंने जवाब दिया कि हमें कल मौका दिया जाएगा। इस प्रकार, यह मामला फिलहाल के लिए टल गया है। अगर हमें कल फिर से बोलने का अवसर मिलता है, तो हम आपको सूचित करेंगे।

शफीकुर ने कहा कि मौजूदा संसद का गठन एक विशेष संदर्भ में हुआ था। 1952 के भाषा आंदोलन, 1971 के मुक्ति संग्राम, 1990 के जन आंदोलन और 2004 के जन-विद्रोह के माध्यम से लोगों के अधिकारों और आकांक्षाओं की पूर्ति नहीं हो पाई थी। इस संदर्भ में, संवैधानिक सुधार आवश्यक हो गया है। उन्होंने बताया कि छह अंतरिम सरकारी सुधार आयोगों और बाद में राष्ट्रीय आम सहमति आयोग द्वारा व्यापक चर्चा के बाद, जुलाई चार्टर में प्रमुख प्रस्तावों को अंतिम रूप दिया गया था। उन्होंने कहा, संसद के गठन के 30 कार्य दिवसों के भीतर सुधार परिषद की बैठक होनी अनिवार्य है।

कोलकाता में ईडी का छापा, कारोबारी 'सोना पप्पू' के ठिकानों पर कार्रवाई

एजेंसी (हि.स.)
कोलकाता

फोटोः हि.स.

पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने एक बार फिर अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। बुधवार सुबह कोलकाता के कई स्थानों पर एक साथ छापेमारी अभियान चलाया गया। इनमें दक्षिण कोलकाता के कसबा इलाके के कारोबारी विश्वजीत पोद्दार उर्फ सोना पप्पू का आवास भी शामिल है। इसके अलावा बालीगंज स्थित एक कंपनी के कार्यालय सहित कई जगहों पर भी तलाशी ली गई।

ईडी सूत्रों के अनुसार सोना पप्पू के खिलाफ पहले से ही कई प्राथमिकी दर्ज हैं। उन पर वसूली, धमकी और अन्य आपराधिक गतिविधियों के आरोप हैं। इनमें से चार-पांच मामलों पर पिछले कुछ दिनों से जांच चल रही थी, जिसके बाद बुधवार को यह कार्रवाई की गई। जानकारी के मुताबिक सुबह लगभग सात बजे ईडी अधिकारी फर्न रोड स्थित उनके घर पहुंचे। इस दौरान केंद्रीय बल के जवान भी मौजूद रहे।

ईडी के अनुसार, कसबा और बालीगंज क्षेत्रों में कई सिंडिकेट पर सोना पप्पू का नियंत्रण होने के आरोप हैं। जांच में यह भी सामने आया है कि वह कथित तौर पर विभिन्न निर्माण कंपनियों से करोड़ों रुपये की वसूली करता था और यह रकम प्रभावशाली लोगों तक पहुंचाई जाती थी। इन्हीं आरोपों की जांच के सिलसिले में यह छापेमारी की गई है। सोना पप्पू के आवास के अलावा दक्षिण कोलकाता के अन्य कई स्थानों पर भी ईडी की कार्रवाई जारी है। वित्तीय अनियमितताओं से जुड़े एक मामले में बालीगंज स्थित 'सन एंटरप्राइज' नामक कंपनी के कार्यालय में भी तलाशी ली जा रही है।

बांग्लादेश में संवैधानिक सुधारों पर रार

- गृहमंत्री ने 'जुलाई चार्टर' आदेश को बताया 'राष्ट्रीय धोखा'

एजेंसी (हि.स.)
ढाका

फोटोः हि.स.

बांग्लादेश के गृहमंत्री सलाहुद्दीन अहमद ने जुलाई 2025 राष्ट्रीय चार्टर (संवैधानिक सुधार) कार्यान्वयन आदेश, 2025 की कड़ी आलोचना करते हुए इसे छल का अंतहीन दस्तावेज और राष्ट्रीय धोखाधड़ी करार दिया। विपक्ष के नेता की शुरू की गई चर्चा का जवाब देते हुए गृहमंत्री ने मंगलवार देररात संसद में जोर देकर कहा कि इस आदेश की कोई कानूनी वैधता नहीं है। यह शुरू से ही अवैध है।

उन्होंने अंतरिम सरकार पर यह भी आरोप लगाया कि दस्तावेज पेश करने से पहले उसने विभिन्न राजनीतिक दलों के विरोध के नोट को शामिल नहीं किया। उन्होंने कहा, राजनीतिक दलों की असहमति वाली राय को बाहर रखना राष्ट्रीय धोखा के बराबर है। सलाहुद्दीन अहमद ने हालिया राष्ट्रपति के आदेश पर कानूनी आपत्तियां उठाते हुए तर्क दिया कि ऐसे निर्देश जारी करने का अधिकार 7 अप्रैल, 1973 के बाद समाप्त हो गया था। उन्होंने सवाल किया, 7 अप्रैल, 1973 के बाद, राष्ट्रपति के पास ऐसा आदेश जारी करने की शक्ति नहीं रही थी। तो फिर यह आदेश कैसे जारी किया गया? उन्होंने कहा कि जो आदेश अपनी शुरूआत से ही अमान्य हो, वह कानूनी भाषा में 'शुरू से ही शून्य' कहलाता है और इसलिए उसे न तो अध्यादेश माना जा सकता है और न ही कानून। गृहमंत्री ने जनमत संग्रह के मतपत्र की संरचना की आलोचना करते हुए कहा कि मतदाताओं को चार अलग-अलग सवालों का जवाब केवल हां या नहीं में देने के लिए मजबूर किया गया। उन्होंने तर्क दिया कि जनता पर किसी भी कानून को इस तरह से थोपा नहीं जाना चाहिए। अंतरिम प्रशासन की भूमिका का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि एक कार्यवाहक सरकार के पास मौलिक राष्ट्रीय मुद्दों पर निर्णय लेने का अधिकार क्षेत्र नहीं होता है। गृहमंत्री ने संवैधानिक सुधार परिषद के सदस्यों के शपथ ग्रहण के संबंध में चुनाव आयोग की भी आलोचना की, और कहा कि अस्तित्वहीन निकाय के सदस्यों को शपथ दिलाने के लिए कोई कानूनी प्रावधान नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्य चुनाव आयुक्त ने संसद को शपथ पत्र भेजकर अपने अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन किया, और इस तरह संविधान को बनाए रखने की अपनी ही संवैधानिक शपथ का भी उल्लंघन किया।

बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) के रुख को स्पष्ट करते हुए सलाहुद्दीन अहमद ने कहा, पूरे देश में यह भ्रम फैलाने की जानबूझकर कोशिश की जा रही है कि बीएनपी सुधार नहीं चाहती या 'जुलाई राष्ट्रीय चार्टर' का समर्थन नहीं करती। हालांकि, हम ऐतिहासिक रूप से हस्ताक्षरित 'जुलाई राष्ट्रीय चार्टर' के हर अक्षर, शब्द और वाक्य का पूरी तरह से पालन करते हैं। हम राजनीतिक आम सहमति पर आधारित सुधार चाहते हैं, न कि किसी अवैध आदेश पर। उन्होंने यह भी दावा किया कि देश की जनता ने 51 प्रतिशत वोटों के साथ बीएनपी को अपना जनादेश दिया है।

एयर इंडिया, इंडिगो ने दुबई, अबू धाबी और खाड़ी के अन्य गंतव्यों के लिए उड़ानों को लेकर जारी की एडवाइजरी

एजेंसी (हि.स.)
नई दिल्ली

फोटोः हि.स.

पश्चिम एशिया में जारी संकट के बीच आज इस तरफ आने-जाने वाली एयर इंडिया समूह की 30 उड़ानें निर्धारित हैं। इसमे कुल 16 उड़ानें यूएई के लिए हैं। इंडिगो ने यात्रियों से एयरपोर्ट जाने से पहले अपनी उड़ान का स्टेटस चेक करने का आग्रह किया है।

इंडिगो एयरलाइन ने जारी यात्रा परामर्श में कहा कि 1 अप्रैल को इंडिगो एयरलाइन के निर्धारित शेड्यूल के अनुसार पश्चिम एशिया के लिए कुल 30 उड़ानें संचालित की जाएंगी। एयरलाइन ने तनावपूर्ण परिस्थितियों के बीच में दुबई, अबू धाबी, रियाद, कुवैत, बहरीन, मस्कट और दोहा के लिए उड़ानें चालू रखने की पुष्टि की है। कंपनी ने यात्रियों को सलाह दी है कि वे हवाई अड्डे पर जाने से पहले इंडिगो की वेबसाइट या मोबाइल ऐप पर अपनी उड़ान की नवीनतम स्थिति देखें। एयरलाइन ने कहा कि पश्चिम एशिया में जारी संकट के बीच यात्रा की स्थितियों में हो रहे बदलावों को देखते हुए, अपडेटेड रहना जरूरी है, क्योंकि फ़्लाइट के शेड्यूल बदल सकते हैं। इसलिए यात्रियों से अनुरोध है कि एयरपोर्ट जाने से पहले अपनी फ़्लाइट के ताजा स्टेटस जरूर देख लें। इंडिगो ने फ़्लाइट्स को ऑपरेट करने का शेड्यूल तय किया है। इसके अलावा इंडिगो ने बताया कि आपके रजिस्टर्ड संपर्क विवरणों पर अपडेट साझा किए जा रहे हैं, और हमारी सहायता टीमें आपकी मदद के लिए उपलब्ध हैं। वहीं, लगातार हो रही बारिश और तूफान के कारण फि लहाल दिल्ली में उड़ानों के संचालन में देरी हो रही है। कंपनी ने कहा कि हमारी टीमें स्थिति पर बारीकी से नजर रख रही हैं, ताकि हालात बेहतर होते ही आपकी यात्रा जल्द से जल्द शुरू हो सके। इंडिगो ने कहा कि अगर आप आज यात्रा कर रहे हैं, तो हम आपको सलाह देते हैं कि एयरपोर्ट के लिए निकलने से पहले हमारी वेबसाइटः https://goindigo.in/check-flight-status.html या ऐप पर अपनी फ़्लाइट का स्टेटस जरूर देख लें। कृपया यात्रा के लिए थोड़ा ज्यादा समय लेकर चलें, क्योंकि सड़कों पर ट्रैफि क सामान्य से धीमा हो सकता है।

एयर इंडिया ने एक बयान में कहा कि एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस पश्चिम एशिया के लिए 30 उड़ानें संचालित करेंगी, जिनमें यूएई के लिए कुल 16 उड़ानें भी शामिल हैं। एयरलाइन ने कहा कि एयर इंडिया समूह जिसमें एयर इंडिया और उसकी कम लागत वाली शाखा, एयर इंडिया एक्सप्रेस शामिल हैं, 1 अप्रैल को पश्चिम एशिया क्षेत्र के लिए और वहां से कुल 30 उड़ानें संचालित करेगा।

ओडिशा में विधायकों के वेतन वृद्धि से जुड़े चार विधेयक वापस

फोटोः हि.स.

एजेंसी (हि.स.)
भुवनेश्वर

ओडिशा में विधायकों, मंत्रियों, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन वृद्धि से संबंधित चारों विधेयकों को अंततः राज्य सरकार ने वापस ले लिया है। इन विधेयकों की वापसी का निर्णय विधानसभा में सर्वसम्मति से लिया गया। संसदीय कार्य मंत्री मुकेश महालिंग ने मंगलवार को विधानसभा में इन चारों विधेयकों को वापस लेने का प्रस्ताव पेश किया, जिसे वॉयस वोट से मंजूरी दे दी गई। उन्होंने बताया कि यद्यपि विधेयक पहले सर्वसम्मति से पारित हुए थे, लेकिन बाद में कई सदस्यों ने इसमें पुनर्विचार की आवश्यकता जताई। सरकार ने सदस्यों की राय को ध्यान में रखते हुए विधेयकों को वापस लेने का निर्णय लिया है। उल्लेखनीय है कि ये विधेयक पिछले शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन सर्वसम्मति से पारित किए गए थे। उस समय सत्तापक्ष और विपक्ष दोनों ने एक स्वर में इसका समर्थन किया था। हालांकि, बाद में इन विधेयकों में प्रस्तावित वेतन और भत्तों में एकमुश्त वृद्धि को लेकर व्यापक प्रतिक्रिया सामने आई।

रमन सिंह ने अमित शाह को लिखा पत्र

नक्सलवाद मुक्त भारत पर जताया आभार

एजेंसी (हि.स.)
रायपुर

फोटोः हि.स.

छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर नक्सलवाद मुक्त भारत पर उनका आभार जताया है। डॉ. सिंह ने अपने पत्र में लिखा कि 31 मार्च 2026 का यह ऐतिहासिक दिन राष्ट्र के लिए एक नई आशा और नई सुबह लेकर आया है। छत्तीसगढ़ विस अध्यक्ष ने पत्र में लिखा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व और आपके दृढ़ संकल्प से दशकों से नक्सलवाद का कष्ट झेल रही भारत भूमि अब अलोकतांत्रिक विचारधारा से पूरी तरह मुक्त हुई है। संविधान विरोधी शक्तियों ने दशकों से भारत भूमि को भीतर से चोट पहुंचाई है। माओ और लेनिन जैसी लोकतंत्र विरोधी विचारधारा ने नक्सलबाड़ी से लेकर बस्तर तक हजारों निर्दोष लोगों को अपना शिकार बनाया, विकास को बाधित कर आदिवासियों को मुख्यधारा से अलग करने का काम किया और इसका परिणाम हमनें छत्तीसगढ़ की धरती पर देखा है। जिस छत्तीसगढ़ में धान का कटोरा बनने का सामर्थ्य था, उसे भुखमरी और पलायन के दौर से गुजरना पड़ा। डॉ. रमन सिंह ने पूर्व संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (यूपीए) सरकार पर आरोप लगाते हुए आगे लिखा कि जब मैं मुख्यमंत्री के रूप में राष्ट्रीय स्तर की बैठकों में जाया करता था, तब यूपीए सरकार के मंत्री नक्सलवाद को राज्य की समस्या मानकर स्वयं को किनारे कर लेते थे। बाद में यूपीए सरकार के प्रधानमंत्री रहे मनमोहन सिंह ने स्पष्ट रूप से यह माना कि नक्सलवाद किसी राज्य की समस्या नहीं बल्कि राष्ट्र की समस्या है और देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है। वो इसे समस्या तो मानते थे लेकिन समाधान नहीं करते थे।

महंगा

कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में भारी उछाल

195.50 रुपये की बढ़ोतरी के साथ नई दरें लागू

- व्यापारिक वर्ग पर बढ़ा बोझ, घरेलू रसोई गैस की कीमतें स्थिर, पेट्रोल और डीजल के दामों में भी कोई बदलाव नहीं

एजेंसी (हि.स.)
नई दिल्ली

फोटोः हि.स.

1 अप्रैल, 2026 वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में जारी अस्थिरता और पश्चिम एशिया में गहराते संकट का असर अब भारतीय बाजार पर दिखने लगा है। सार्वजनिक क्षेत्र की तेल एवं गैस विपणन कंपनियों ने बुधवार को 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 195.50 रुपये की भारी बढ़ोतरी की घोषणा की है। तेल कंपनियों द्वारा संशोधित की गई ये नई दरें 1 अप्रैल से तत्काल प्रभाव से लागू हो गई हैं। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार, इस ताजा वृद्धि के बाद राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 19 किलोग्राम के वाणिज्यिक सिलेंडर की कीमत अब बढ़कर 2,078.50 रुपये हो गई है। गौरतलब है कि इससे पहले 1 मार्च को भी इन कीमतों में 114.5 रुपये की वृद्धि की गई थी। लगातार दूसरे महीने हुई इस बढ़त ने होटल, रेस्टोरेंट और खान-पान के व्यवसाय से जुड़े व्यापारियों की चिंता बढ़ा दी है।

कमर्शियल गैस के दामों में लगी आग के बीच आम जनता के लिए राहत की बात यह है कि 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। दिल्ली में घरेलू सिलेंडर की कीमत वर्तमान में 913 रुपये पर स्थिर बनी हुई है। हालांकि, पिछले महीने 7 मार्च को घरेलू सिलेंडर के दामों में 60 रुपये की बढ़ोतरी की गई थी। इसके साथ ही, पिछले साल मार्च में पेट्रोल-डीजल की कीमतों में की गई 2 रुपये की कटौती के बाद से ईंधन दरें भी स्थिर हैं। दिल्ली में आज पेट्रोल 94.72 रुपये और डीजल 87.62 रुपये प्रति लीटर की दर से मिल रहा है। तेल विपणन कंपनियों द्वारा की गई इस समीक्षा का मुख्य कारण अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में आया उछाल और विनिमय दर में होने वाले उतार-चढ़ाव को माना जा रहा है। कंपनियां हर महीने की पहली तारीख को एविएशन टर्बाइन फ्यूल और एलपीजी की कीमतों की समीक्षा करती हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि पश्चिम एशिया में जारी तनाव यदि जल्द शांत नहीं हुआ, तो आने वाले समय में ऊर्जा की कीमतों पर दबाव और बढ़ सकता है।

दिल्ली में 195.50 रुपये की वृद्धि के बाद नई कीमत 2,078.50 रुपये हो गई है। इसी अनुपात में कोलकाता, मुंबई और चेन्नई जैसे अन्य महानगरों में भी कीमतों में बड़ा बदलाव देखा गया है। वाणिज्यिक गैस की बढ़ती कीमतों का सीधा असर खाद्य वस्तुओं की महंगाई पर पड़ने की आशंका जताई जा रही है, क्योंकि बाहर खाना और कैटरिंग सेवाएं अब महंगी हो सकती हैं। कंपनियों का कहना है कि वे अंतरराष्ट्रीय मानकों और बाजार की स्थितियों के आधार पर ही कीमतों का निर्धारण करती हैं।

संक्षिप्त-समाचार

स्टॉक मार्केट में टिप्को इंजीनियरिंग की फीकी शुरूआत, घाटे में आईपीओ निवेशक

नई दिल्ली। इंडस्ट्रियल मशीनरी कंपोनेंट बनाने वाली कंपनी टिप्को इंजीनियरिंग इंडिया के शेयरों ने बुधवार स्टॉक मार्केट में फीका प्रदर्शन कर अपने आईपीओ निवेशकों को निराश कर दिया। आईपीओ के तहत कंपनी के शेयर 89 रुपये के भाव पर जारी किए गए थे। बुधवार बीएसई के एसएमई प्लेटफॉर्म पर इसकी लिस्टिंग सिर्फ 0.28 प्रतिशत प्रीमियम के साथ 89.25 रुपये के स्तर पर हुई। लिस्टिंग के बाद बिकवाली का दबाव बनने पर कंपनी के शेयर 84.81 रुपये के स्तर तक गिर गए। हालांकि बाद में लिवालों ने खरीदारी का जोर बना कर इस शेयर को सहारा दिया, जिससे इसकी स्थिति में सुधार होने लगा। दोपहर 11:45 बजे ये शेयर 88.50 रुपये के स्तर पर कारोबार कर रहा था। इस तरह अभी तक के कारोबार के बाद कंपनी के आईपीओ निवेशक 0.56 प्रतिशत के नुकसान में थे। टिप्को इंजीनियरिंग इंडिया 60.55 करोड़ रुपये का आईपीओ 23 से 25 मार्च के बीच सब्सक्रिप्शन के लिए खुला था। इस आईपीओ को निवेशकों की ओर से एवरेज रिस्पॉन्स मिला था, जिसके कारण ये ओवरऑल 1.70 गुना सब्सक्राइब हो सका था। इनमें क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स (क्यूआईबी) के लिए रिजर्व पोर्शन 3.20 गुना सब्सक्राइब हुआ था। वहीं नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स (एनआईआई) के लिए रिजर्व पोर्शन में 2.12 गुना सब्सक्रिप्शन आया था। रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए रिजर्व पोर्शन फुली सब्सक्राइब नहीं हो सका था। रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए रिजर्व पोर्शन सिर्फ 0.66 गुना ही सब्सक्राइब हो सका था। इस आईपीओ के तहत 10 रुपये फेस वैल्यू वाले कुल 68,03,200 शेयर जारी किए गए हैं।

सर्राफा बाजार में महंगा हुआ सोना, चांदी की भी बढ़ी चमक

नई दिल्ली। घरेलू सर्राफा बाजार में बुधवार शुरूआती कारोबार के दौरान तेजी का रुख नजर आ रहा है। सोना बुधवार 1,150 रुपये प्रति 10 ग्राम से लेकर 1,250 रुपये प्रति 10 ग्राम तक महंगा हो गया है। इसी तरह चांदी ने भी बुधवार 5,200 रुपये प्रति किलोग्राम की छलांग लगाई है। सोने की कीमत में आए उछाल के कारण देश के ज्यादातर सर्राफा बाजार में 24 कैरेट सोना बुधवार 1,49,520 रुपये प्रति 10 ग्राम से लेकर 1,49,670 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार कर रहा है। वहीं 22 कैरेट सोना बुधवार 1,37,060 रुपये प्रति 10 ग्राम से लेकर 1,37,210 रुपये प्रति 10 ग्राम के बीच बिक रहा है। सोना की तरह ही चांदी के भाव में भी बुधवार तेजी आई है, जिसकी वजह से ये चमकीली धातु बुधवार शुरूआती कारोबार के दौरान दिल्ली सर्राफा बाजार में 2,50,100 रुपये प्रति किलोग्राम के स्तर पर ही बिक रही है। घरेलू बाजार की तरह ही अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी बुधवार सोना और चांदी दोनों चमकीली धातुओं की कीमत में तेजी नजर आ रही है। सिंगापुर गोल्ड एक्सचेंज में बुधवार हाजिर सोना 4,652.31 डॉलर प्रति औंस के स्तर पर नजर आ रहा है। वहीं लंदन सिल्वर मार्केट में हाजिर चांदी की कीमत 74.64 डॉलर प्रति औंस के स्तर पर आ गई है। दिल्ली में बुधवार 24 कैरेट सोना 1,49,670 प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार कर रहा है, जबकि 22 कैरेट सोने की कीमत 1,37,210 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज की गई है। वहीं देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में 24 कैरेट सोना 1,49,520 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोना 1,37,060 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बिक रहा है। इसी तरह अहमदाबाद में 24 कैरेट सोने की रिटेल कीमत 1,49,570 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोने की कीमत 1,37,110 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज की गई है।

शुरूआती कारोबार में शेयर बाजार में जोरदार तेजी, सेंसेक्स और निफ्टी उछले

नई दिल्ली। पश्चिम एशिया में जारी युद्ध के जल्द थमने का संकेत मिलने और मजबूत ग्लोबल संकेतों की वजह से घरेलू शेयर बाजार ने भी बुधवार शुरूआती कारोबार के दौरान जोरदार तेजी का रुख बना हुआ है। बुधवार सेंसेक्स और निफ्टी दोनों सूचकांकों ने दो प्रतिशत से भी अधिक की मजबूती के साथ कारोबार की शुरूआत की। हालांकि बीच-बीच में मुनाफा वसूली के चक्कर में बिकवाली का झटका भी लगता रहा, लेकिन बाजार में हो रही जोरदार खरीदारी के कारण ये दोनों सूचकांक लगातार शानदार मजबूती के साथ कारोबार करते रहे। सुबह 10:30 बजे तक का कारोबार होने के बाद सेंसेक्स 2.10 प्रतिशत और निफ्टी 2.09 प्रतिशत की मजबूती के साथ कारोबार कर रहे थे। बुधवार प्रातः 10:30 बजे तक का कारोबार होने के बाद स्टॉक मार्केट के दिग्गज शेयरों में से इंटर ग्लोब एविएशन, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, ट्रेंट लिमिटेड, अदानी पोर्ट्स और अडानी इंटरप्राइजेज के शेयर 8.74 प्रतिशत से लेकर 5.50 प्रतिशत की मजबूती के साथ कारोबार कर रहे थे। दूसरी ओर, निफ्टी 50 में शामिल इकलौता एचडीएफसी लाइफ का शेयर 0.01 प्रतिशत की सांकेतिक कमजोरी के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा था।

ग्लोबल मार्केट से पॉजिटिव संकेत, एशिया में भी चौतरफा तेजी का रुख

नई दिल्ली। पश्चिम एशिया में जारी युद्ध के खत्म होने की संभावना के कारण ग्लोबल मार्केट से बुधवार पॉजिटिव संकेत मिल रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका अगले एक से दो सप्ताह में ईरान के युद्ध से बाहर हो सकता है। ट्रंप के इस बयान के बाद ईरान युद्ध खत्म होने की संभावना बढ़ी है, जिसके कारण ग्लोबल मार्केट से बुधवार मजबूती के संकेत मिल रहे हैं। अमेरिकी बाजार पिछले सत्र के दौरान शानदार मजबूती के साथ कारोबार करने के बाद बंद हुए। डाउ जॉन्स फ्यूचर्स भी बुधवार बढ़त के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। यूरोपीय बाजार में भी पिछले सत्र के दौरान लगातार खरीदारी होती रही। इसी तरह एशियाई बाजार में भी बुधवार चौतरफा तेजी का माहौल बना हुआ है। ईरान युद्ध से जल्दी ही बाहर निकलने का संकेत देकर डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले सत्र के दौरान अमेरिकी बाजार में उत्साह का माहौल बना दिया, जिसकी वजह से वॉल स्ट्रीट के सूचकांक जोरदार बढ़त के साथ बंद होने में सफल रहे। एस एंड पी 500 इंडेक्स 184.80 अंक यानी 2.91 प्रतिशत उछल कर 6,528.52 अंक के स्तर पर बंद हुआ। इसी तरह नैस्डेक ने 795.99 अंक यानी 3.83 प्रतिशत की मजबूती के साथ 21,590.63 अंक के स्तर पर पिछले सत्र के कारोबार का अंत किया। वहीं डाउ जॉन्स फ्यूचर्स आज फिलहाल 0.17 प्रतिशत की तेजी के साथ 46,421.02 अंक के स्तर पर कारोबार कर रहा है।

मेसी के जादू से अर्जेंटीना की भव्य जीत

मैत्री मैच में जाम्बिया को 5-0 से रौंदा

कप्तान मेसी का शानदार कमबैक, एक गोल और निर्णायक असिस्ट से जाम्बिया पस्त

एजेंसी (हि.स.)
ब्यूनस आयर्स

- मेसी का 116वां अंतरराष्ट्रीय गोल

अर्जेन्टीना की राष्ट्रीय फुटबॉल टीम ने मंगलवार रात को खेले गए एक अंतरराष्ट्रीय मैत्री मैच में जाम्बिया के खिलाफ 5-0 की एकतरफा और शानदार जीत दर्ज की है। ब्यूनस आयर्स के ऐतिहासिक ला बोम्बोनेरा स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में कप्तान लियोनेल मेसी ने अपनी जादुई फॉर्म का प्रदर्शन करते हुए टीम की जीत में मुख्य भूमिका निभाई। कोच लियोनेल स्कालोनी द्वारा प्लेइंग इलेवन में वापस बुलाए जाने के बाद मेसी ने खेल के हर विभाग में अपना प्रभाव छोड़ा।

मैच की शुरूआत से ही अर्जेंटीना ने आक्रामक रुख अपनाया। खेल के मात्र चौथे मिनट में मेसी ने जाम्बिया के रक्षापंक्ति को भेदते हुए एक सटीक पास दिया, जिस पर जूलियन अल्वारेज ने बिना कोई गलती किए गोल दागकर टीम को 1-0 की बढ़त दिला दी। इसके बाद भी अर्जेंटीना का दबाव बना रहा और पहले हाफ के समापन से ठीक पहले मेसी ने एलेक्सिस मैक एलिस्टर के साथ बेहतरीन तालमेल दिखाते हुए खुद गोल किया। यह मेसी के अंतरराष्ट्रीय करियर का 116वां गोल था। मुकाबले के दूसरे हाफ में अर्जेंटीना को पेनल्टी मिली, जहां मेसी ने खेल भावना का परिचय देते हुए गेंद निकोलस ओटामेंडी को सौंपी, जिन्होंने इसे सफलतापूर्वक गोल में बदलकर स्कोर 3-0 कर दिया। जाम्बिया की मुश्किलें तब और बढ़ गईं जब डोमिनिक चांदा ने एक आत्मघाती गोल कर दिया, जिससे अर्जेंटीना 4-0 से आगे हो गया। मैच के अंतिम क्षणों (इंजरी टाइम) में युवा खिलाड़ी वैलेन्टिन बार्को ने पांचवां गोल कर जाम्बिया की हार पर अंतिम मुहर लगा दी। सांख्यिकी के अनुसार, अर्जेंटीना ने पूरे मैच में 70% से अधिक बॉल पजेशन बनाए रखा।

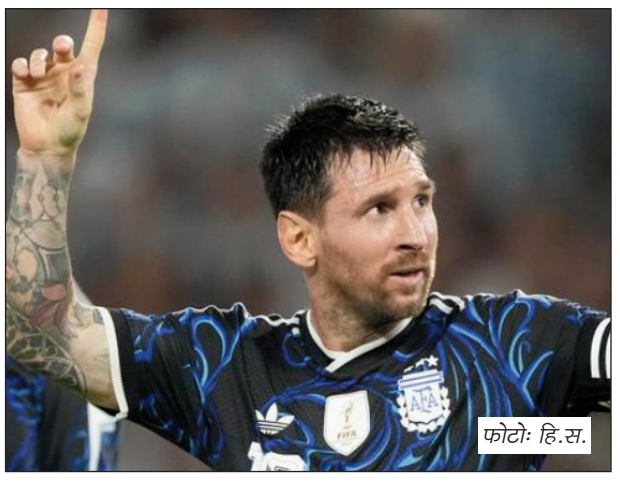
फोटोः हि.स.

यह मुकाबला अर्जेंटीना के लिए बेहद महत्वपूर्ण था क्योंकि आगामी जून में होने वाले विश्व कप से पहले यह उनके घरेलू मैदान पर आखिरी मैच था। विश्व चैंपियन अर्जेंटीना अब अपने खिताब का बचाव करने के लिए पूरी तरह तैयार नजर आ रही है। टूर्नामेंट के शुरूआती दौर में अर्जेंटीना का सामना अल्जीरिया, ऑस्ट्रिया और जॉर्डन जैसी टीमों से होना तय है। प्रशंसकों को उम्मीद है कि कप्तान मेसी की अगुवाई में टीम एक बार फिर विश्व विजेता बनने का गौरव हासिल करेगी।

कोच लियोनेल स्कालोनी ने इस मैच के माध्यम से टीम संयोजन को परखने का प्रयास किया है। विशेष रूप से मेसी, अल्वारेज और मैक एलिस्टर के बीच का तालमेल टीम के लिए सकारात्मक संकेत है। जाम्बिया के खिलाफ इस बड़ी जीत ने न केवल टीम का मनोबल बढ़ाया है, बल्कि विपक्षी टीमों के लिए भी एक चेतावनी जारी की है। अर्जेंटीना की टीम अब अंतरराष्ट्रीय दौरों और अंतिम अभ्यास सत्रों के लिए रवाना होगी, जहां उनका लक्ष्य अपनी फिटनेस और रणनीतिक कौशल को और अधिक निखारना होगा।

इटली लगातार तीसरी बार फीफा वर्ल्ड कप से बाहर

- प्लेऑफ में बोस्निया से पेनल्टी शूटआउट में मिली हार

एजेंसी (हि.स.)
जेनिका

फोटोः हि.स.

चार बार की विश्व चैंपियन इटली राष्ट्रीय फुटबॉल टीम एक बार फिर फीफा वर्ल्ड कप के लिए क्वालीफाई करने में नाकाम रही है। यूरोपीय प्लेऑफ मुकाबले में इटली को 66वीं रैंकिंग वाली बोस्निया और हजेगोविना के खिलाफ पेनल्टी शूटआउट में हार का सामना करना पड़ा।

मुकाबले की शुरूआत में मोइज कीन ने गोल कर इटली को बढ़त दिलाई, लेकिन पहले हाफ में ही सेंटर-बैक अलेसांद्रो बास्तोनी को रेड कार्ड मिलने से टीम 10 खिलाड़ियों तक सिमट गई। इसका फायदा उठाते हुए बोस्निया के सब्स्टीट्यूट हारिस तबाकोविक ने 79वें मिनट में बराबरी का गोल दाग दिया, जिससे मैच अतिरिक्त समय में चला गया।

अतिरिक्त समय में भी कोई नतीजा नहीं निकल सका और मुकाबला पेनल्टी शूटआउट तक पहुंचा, जहां इटली को हार झेलनी पड़ी। इस हार के साथ ही इटली लगातार तीसरी बार वर्ल्ड कप में जगह बनाने से चूक गई है। इससे पहले टीम को पिछले दो वर्ल्ड कप क्वालीफायर प्लेऑफ में स्वीडन और नॉर्थ मैसिडोनिया के हाथों बाहर होना पड़ा था। 1934, 1938, 1982 और 2006 में खिताब जीत चुकी इटली अब कम से कम 16 साल तक वर्ल्ड कप में एक भी मैच खेले बिना रह सकती है। टीम का खराब प्रदर्शन 2010 और 2014 वर्ल्ड कप से ही शुरू हो गया था, जहां वह ग्रुप स्टेज से आगे नहीं बढ़ सकी थी। हालांकि, इटली ने 2021 में यूरोपीय चैम्पियनशिप जीतकर वापसी की झलक जरूर दिखाई थी।

इटली का आखिरी वर्ल्ड कप नॉकआउट मैच 2006 में था, जब उसने फाइनल में फ्रांस को हराकर खिताब जीता था। 1958 के बाद यह पहली बार है जब इटली इतनी बार वर्ल्ड कप में क्वालीफाई करने में असफल रही है, जिससे टीम के प्रदर्शन पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं।

पंजाब किंग्स के कप्तान श्रेयस अय्यर पर 12 लाख रुपये का जुमार्ना

फोटोः हि.स.

एजेंसी (हि.स.)
मुल्लांपुर

पंजाब किंग्स के कप्तान श्रेयस अय्यर पर गुजरात टाइटन्स के खिलाफ मंगलवार को यहां खेले गए आईपीएल मैच के दौरान धीमी ओवर बनाए रखने के लिए 12 लाख रुपये का जुमार्ना लगाया गया है। पंजाब किंग्स ने इस मैच में गुजरात टाइटन्स को तीन विकेट से हराकर आईपीएल 2026 में जीत से शुरूआत की। आईपीएल ने एक विज्ञप्ति में कहा, आईपीएल की न्यूनतम ओवर रेट से जुड़ी आचार संहिता के अनुच्छेद 2.22 के तहत यह उनकी टीम का इस सत्र का पहला अपराध था, इसलिए अय्यर पर 12 लाख रुपये का जुमार्ना लगाया गया। तेज गेंदबाज वैशाक विजयकुमार और लेग स्पिनर युजवेंद्र चहल ने मिलकर पांच विकेट लिए, जिससे पंजाब ने गुजरात टाइटन्स को छह विकेट पर 162 रन पर रोक दिया। पंजाब ने 19.1 ओवर में लक्ष्य हासिल कर लिया। ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज कूपर कॉनली ने 44 गेंदों पर नाबाद 72 रन बनाकर टीम को जीत दिलाई।

वर्ल्ड कप से पहले ब्राजील की दमदार तैयारी

- क्रोएशिया को 3-1 से हराया

एजेंसी (हि.स.)
ऑरलैंडो

फोटोः हि.स.

ब्राजील राष्ट्रीय फुटबॉल टीम ने वर्ल्ड कप की तैयारियों के तहत खेले गए मैत्री मुकाबले में क्रोएशिया राष्ट्रीय फुटबॉल टीम को 3-1 से हराकर शानदार जीत दर्ज की। मुकाबला मंगलवार को कैम्पिंग वर्ल्ड स्टेडियम में खेला गया। मैच के पहले हाफ में ब्राजील ने गेंद पर पूरी तरह नियंत्रण बनाए रखा और कई मौके बनाए। 20वें मिनट में दानिलो का प्रयास क्रोएशियाई गोलकीपर डोमिनिक लिवाकोविच ने रोक दिया। इसके बाद भी ब्राजील लगातार आक्रामक खेल दिखाता रहा।

आखिरकार पहले हाफ के अंत में ब्राजील को सफलता मिली, जब माथियस कुन्हा के पास पर विनीसियस जूनियर ने बेहतरीन रन बनाते हुए दानिलो को पास दिया, जिन्होंने शानदार फिनिश के साथ टीम को बढ़त दिलाई।

दूसरे हाफ में क्रोएशिया ने वापसी की कोशिश की और 84वें मिनट में लोवरो माजेर ने टोनी फ्रुक के क्रॉस पर गोल कर स्कोर 1-1 कर दिया।

हालांकि, इसके बाद ब्राजील ने तेजी से जवाब दिया। 88वें मिनट में इगोर थियागो ने पेनल्टी को गोल में बदलकर टीम को फिर से बढ़त दिलाई। इंजरी टाइम में गेब्रियल मार्टिनेली ने गोल कर जीत 3-1 से पक्की कर दी।

मैच के बाद कैसेमिरो ने कहा कि टीम को अभी और सुधार की जरूरत है, लेकिन वे वर्ल्ड कप में पूरी ताकत के साथ उतरेंगे। अब ब्राजील जून में मित्र राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के खिलाफ एक और अभ्यास मैच खेलेगा, जबकि वर्ल्ड कप में उसका पहला मुकाबला मोरक्को से होगा। वहीं, क्रोएशिया टूर्नामेंट से पहले बेल्जियम और स्लोवेनिया के खिलाफ अभ्यास मैच खेलेगा।

वेदरल्ड और डॉगेट को क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का अनुबंध, मैक्सवेल और कॉन्स्टास बाहर

एजेंसी (हि.स.)
मेलबर्न

फोटोः हि.स.

क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया (सीए) ने बुधवार को सलामी बल्लेबाज जेक वेदरल्ड और तेज गेंदबाज ब्रेंडन डॉगेट को पहली बार केंद्रीय अनुबंधित खिलाड़ियों की सूची में शामिल किया लेकिन ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल और सलामी बल्लेबाज सैम कॉन्स्टास को 2026-2027 के सत्र के लिए इस सूची से बाहर कर दिया गया। वेदरल्ड और डॉगेट ने एशेज के दौरान टेस्ट क्रिकेट में पदार्पण किया था। इन दोनों खिलाड़ियों को उनके अच्छे प्रदर्शन का इनाम मिला है जबकि तेज गेंदबाज माइकल नेसर ने श्रृंखला में उपयोगी योगदान के कारण सूची में अपनी जगह बरकरार रखी है। अगले साल की शुरूआत में भारत में होने वाले पांच टेस्ट मैचों की श्रृंखला को देखते हुए ऑफ स्पिनर टॉड मर्फी को भी अनुबंधित खिलाड़ियों की सूची में शामिल किया गया है। नाथन लियोन की चोट के कारण एशेज के दौरान मर्फी को टेस्ट टीम में शामिल किया गया था, लेकिन उन्हें खेलने का मौका नहीं मिला। चयनकर्ताओं ने अनुबंध सूची में 21 खिलाड़ियों के नाम शामिल किए हैं, जो उपलब्ध 24 स्थानों से तीन कम हैं। पिछले साल 23 खिलाड़ियों को इस सूची में जगह मिली थी। युवा सलामी बल्लेबाज सैम कॉन्स्टास और मैक्सवेल के अलावा बल्लेबाज मैथ्यू रेनशॉ, तेज गेंदबाज झाई रिचर्डसन, लांस मॉरिस और मैथ्यू शॉर्ट को भी अनुबंध नहीं मिला है। ऑस्ट्रेलिया की पुरुष चयनसमिति के अध्यक्ष जॉर्ज बेली ने कहा, अनुबंध सूची टीम के आगामी कार्यक्रम को देखते हुए तैयार की गई है। अगले 12 महीनों में हमारा काफी व्यस्त कार्यक्रम है जिसमें हमें दक्षिण अफ्रीका, भारत और इंग्लैंड जैसी टीमों के खिलाफ टेस्ट मैच खेलने हैं।

वश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस 2026

'समावेशिता' की ओर बढ़ते वैश्विक कदम

आज पूरा विश्व 'विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस' मना रहा है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2007 में घोषित यह दिन अब केवल जागरूकता तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि इसका विस्तार 'स्वीकार्यता' और 'समावेशिता' तक हो चुका है। वर्ष 2026 के लिए संयुक्त राष्ट्र ने इस दिन का मुख्य विषय 'ऑटिज्म और मानवता - हर जीवन का मूल्य है' निर्धारित किया है। यह विषय ऑटिज्म से ग्रसित व्यक्तियों की गरिमा और उनके अधिकारों को समाज की मुख्यधारा में शामिल करने पर जोर देता है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने अपने संदेश में स्पष्ट किया कि ऑटिस्टिक व्यक्तियों को भी अपने जीवन को आकार देने और हमारे साझा भविष्य में योगदान देने का उतना ही अधिकार है, जितना किसी अन्य व्यक्ति को। उन्होंने समान शिक्षा, निष्पक्ष रोजगार और सुलभ स्वास्थ्य प्रणालियों के माध्यम से उन्हें अवसर प्रदान करने की अपील की है। विशेषज्ञों का मानना है कि ऑटिज्म को 'ठीक' की जाने वाली बीमारी के बजाय 'न्यूरो-डाइवर्सिटी' (मस्तिष्क की कार्यक्षमता में भिन्नता) के रूप में देखा जाना चाहिए। परंपरा के अनुसार, आज दुनिया भर की प्रमुख इमारतों को नीली रोशनी से सजाया गया है। 'लाइट इट अप ब्लू' अभियान के तहत यह नीला रंग ऑटिज्म के प्रति शांति, समझ और एकजुटता का प्रतीक माना जाता है। वैश्विक स्तर पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में इस बार इस बात पर चर्चा की जा रही है कि कैसे कार्यस्थलों और स्कूलों को ऑटिस्टिक व्यक्तियों के अनुकूल बनाया जाए।

सांख्यिकी और तथ्यः एक नजर में

विश्व स्वास्थ्य संगठन के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, विश्व स्तर पर लगभग 100 में से 1 बच्चा ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार से प्रभावित है। भारत के संदर्भ में स्थिति और भी गंभीर है। हालिया शोध और 'इनक्लेन ट्रस्ट' की रिपोर्ट बताती है कि भारत में लगभग 1.8 करोड़ से अधिक लोग ऑटिज्म से प्रभावित हो सकते हैं। शहरी क्षेत्रों में जागरूकता बढ़ने के कारण रिपोर्ट किए जा रहे मामलों में वृद्धि देखी गई है। भारत के राष्ट्रीय जनगणना आंकड़ों और स्वतंत्र शोधों के बीच एक बड़ा अंतर पाया गया है, जो इस क्षेत्र में और अधिक सटीक डेटा संग्रहण की आवश्यकता को दशार्ता है। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर मुख्य रूप से मस्तिष्क के विकास से जुड़ी एक स्थिति है, जो किसी व्यक्ति के बातचीत करने, व्यवहार करने और दूसरों के साथ सामाजिक संबंध बनाने की क्षमता को प्रभावित करती है। डॉक्टरों के अनुसार, इसके लक्षण आमतौर पर बच्चे के जन्म के शुरूआती 3 वर्षों में दिखाई देने लगते हैं। मुख्य लक्षणों में नजरें मिलाकर बात न करना, नाम पुकारे जाने पर प्रतिक्रिया न देना, एक ही शब्द या क्रिया को बार-बार दोहराना और सामाजिक मेल-जोल से कतराना शामिल है। भारत में इस दिशा में काम कर रहे विशेषज्ञों का कहना है कि शुरूआती पहचान सबसे महत्वपूर्ण है। बेंगलुरु और दिल्ली जैसे महानगरों में विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि यदि 18 से 24 महीने की उम्र में ही लक्षणों की पहचान कर ली जाए, तो 'एप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस' (ABA) और स्पीच थेरेपी जैसी तकनीकों के माध्यम से बच्चे के विकास की दिशा को काफी हद तक सुधारा जा सकता है।

प्रमुख चुनौतियां और समाधान

भारत में वर्तमान में ऑटिज्म से जुड़ी सबसे बड़ी चुनौती नैदानिक उपकरणों की उपलब्धता है। रिपोर्टों के अनुसार, ऑटिज्म की जांच के लिए मानक उपकरण भारत की 22 आधिकारिक भाषाओं में से केवल 5 से कम भाषाओं में उपलब्ध हैं। इसके अलावा, बीमा कवरेज में कमी और समावेशी शिक्षा के सीमित प्रावधान भी एक बड़ी बाधा हैं। विशेषज्ञों का सुझाव है कि माता-पिता की भागीदारी और शिक्षकों का प्रशिक्षण इस दिशा में सकारात्मक बदलाव ला सकता है। भारत में 'इंडियन स्केल फॉर असेसमेंट ऑफ ऑटिज्म' (ISAA) का उपयोग अब नैदानिक केंद्रों में व्यापक रूप से किया जा रहा है। जैसे-जैसे दुनिया डिजिटल और तकनीकी रूप से आगे बढ़ रही है, ऑटिस्टिक व्यक्तियों के लिए रोजगार के नए द्वार भी खुल रहे हैं। कई वैश्विक कंपनियों ने अब 'न्यूरो-डाइवर्सिटी' भर्ती कार्यक्रम शुरू किए हैं, क्योंकि ऑटिस्टिक व्यक्तियों में पैटर्न पहचानने, गहरी एकाग्रता और रचनात्मक समस्या समाधान जैसी अद्वितीय क्षमताएं होती हैं। 2026 का यह दिवस इसी संदेश को पुख्ता करता है कि अंतर को स्वीकार करना ही समाज की असली ताकत है। संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतरराष्ट्रीय संगठन आज एक वर्चुअल कार्यक्रम के माध्यम से इस बात पर भी चर्चा कर रहे हैं कि कैसे ऑटिज्म को सतत विकास लक्ष्यों के साथ जोड़ा जाए, ताकि कोई भी पीछे न छूटे। यह दिन हमें याद दिलाता है कि सहानुभूति से ज्यादा जरूरी है 'समानता' का भाव रखना।

अंतरराष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस 2026

'कहानियां बोओ और दुनिया महक उठेगी'

आज दुनिया भर में 'अंतरराष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस' मनाया जा रहा है। प्रतिवर्ष 2 अप्रैल को प्रसिद्ध डेनिश लेखक हंस क्रिश्चियन एंडरसन की जयंती के अवसर पर यह दिन मनाया जाता है, जिन्होंने 'द लिटिल मरमेड' और 'द अगली डकलिंग' जैसी कालजयी कहानियों से बच्चों के साहित्य को समृद्ध किया। वर्ष 2026 के लिए इस वैश्विक आयोजन की कमान 'इंटरनेशनल बोर्ड ऑन बुक्स फॉर यंग पीपल' के साइप्रस विभाग को सौंपी गई है। इस वर्ष का मुख्य विषय 'कहानियां बोओ और दुनिया महक उठेगी' साइप्रस द्वारा तैयार किए गए इस वर्ष के संदेश में कहानियों को एक 'बीज' की तरह बताया गया है, जो बच्चों के मन में सहानुभूति, ज्ञान और कल्पना का विस्तार करते हैं। इस अवसर पर जारी आधिकारिक पोस्टर को प्रसिद्ध चित्रकार सैंड्रा एलिफ्थेरियो ने डिजाइन किया है, जबकि वैश्विक संदेश लेखिका ऐलेना पेरिक्लियस द्वारा लिखा गया है। यह विषय न केवल साहित्य के महत्व को दशार्ता है, बल्कि बच्चों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करने और प्रकृति से जुड़ने के लिए भी प्रेरित करता है।

दिवस का इतिहास और महत्व

अंतरराष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस की स्थापना वर्ष 1967 में 'इंटरनेशनल बोर्ड ऑन बुक्स फॉर यंग पीपल' द्वारा की गई थी। इसका प्राथमिक उद्देश्य बच्चों में पढ़ने की आदत को बढ़ावा देना और उत्कृष्ट बाल साहित्य की ओर दुनिया का ध्यान आकर्षित करना है। हर साल IBBY का एक अलग राष्ट्रीय खंड इस दिन का अंतरराष्ट्रीय प्रायोजक बनता है और एक विशिष्ट विषय व संदेश का चयन करता है। 2 अप्रैल की तारीख हंस क्रिश्चियन एंडरसन के सम्मान में चुनी गई है, जिनका जन्म 1805 में इसी दिन हुआ था। विशेषज्ञों का मानना है कि डिजिटल युग में बच्चों का किताबों से जुड़ाव कम हो रहा है, ऐसे में यह दिन अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। नई दिल्ली के प्रमुख शिक्षाविदों और बाल साहित्यकारों के अनुसार, 2026 का विषय 'कहानियां बोना' इस बात का प्रतीक है कि बचपन में पढ़ी गई कहानियां वयस्क होने पर व्यक्ति के चरित्र और दृष्टिकोण का निर्माण करती हैं। इस वर्ष कई देशों में 'बुक स्वैप' (किताबों का आदान-प्रदान) और 'कहानी सुनाने के सत्र' आयोजित किए जा रहे हैं, ताकि बच्चों को मोबाइल स्क्रीन से हटाकर पन्नों की दुनिया की ओर लाया जा सके। साइप्रस IBB ने इस वर्ष के लिए एक विशेष गीत भी जारी किया है, जो बच्चों को कहानियों के माध्यम से दुनिया को एक बेहतर और 'हरा-भरा' स्थान बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। स्कूलों और पुस्तकालयों में आज 'रीड-अलोन' (साथ मिलकर पढ़ना) कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें माता-पिता को भी शामिल किया गया है ताकि घर में पढ़ने के अनुकूल माहौल तैयार हो सके।

बाल साहित्य और साक्षरता के आंकड़े

यूनेस्को और विभिन्न अंतरराष्ट्रीय साक्षरता संगठनों के हालिया आंकड़ों के अनुसार, जिन बच्चों के पास घर में अपनी पसंद की कम से कम 20 किताबें होती हैं, उनकी शैक्षणिक प्रगति उन बच्चों की तुलना में कहीं बेहतर होती है जिनके पास किताबों का अभाव है। भारत में भी 'नेशनल बुक ट्रस्ट' और विभिन्न प्रकाशन संस्थाएं क्षेत्रीय भाषाओं में बाल साहित्य को बढ़ावा देने के लिए नए प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि मातृभाषा में उपलब्ध कहानियां बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में 30% अधिक प्रभावी साबित होती हैं। आज का दिन केवल किताबों का जश्न नहीं है, बल्कि यह बच्चों की कल्पना की स्वतंत्रता का भी उत्सव है। साइप्रस के संदेश में इस बात पर जोर दिया गया है कि कहानियां केवल मनोरंजन का साधन नहीं हैं, बल्कि वे सीमाओं को पार करने और अलग-अलग संस्कृतियों को समझने का एक सशक्त माध्यम हैं। 2026 का यह आयोजन बच्चों को यह विश्वास दिलाने का प्रयास है कि वे अपनी कहानियों और विचारों के माध्यम से दुनिया में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं।

पीजीआई ने फेशियल रीकंस्ट्रक्शन शानदार उपलब्धि हासिल की

सिटी दर्पण संवाददाता
चंडीगढ़

पीजीआई के डॉक्टरों ने मेडिकल क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए जटिल चेहरे के पुनर्निर्माण (फेशियल रीकंस्ट्रक्शन) में नई मिसाल पेश की है। डॉक्टरों की टीम ने एक युवा महिला के गंभीर चेहरे के विकार को ठीक करने के लिए हाइब्रिड डिजिटल और पारंपरिक तकनीकों का सफल उपयोग किया। इस उल्लेखनीय केस को प्रतिष्ठित मेडिकल जर्नल बीएमजे केस रिपोर्टस में प्रकाशित किया गया है। यह मामला एक 30 वर्षीय महिला का था, जो चारा काटने वाली मशीन से हुए हादसे में बुरी तरह घायल हो गई थी। इस दुर्घटना में उसके चेहरे के दाहिने हिस्से की कई अहम संरचनाएं नष्ट हो गई थीं, जिनमें माथे की हड्डी, आंख, गाल, ऊपरी होंठ और पूरा नाक शामिल था। इस गंभीर शारीरिक चोट के साथ-साथ महिला को मानसिक रूप से भी गहरा आघात लगा, जिससे वह सामाजिक रूप से अलग-थलग पड़ गई और आत्मविश्वास में भारी कमी आ गई। पीजीआई के ओरल हेल्थ साइंसेज सेंटर की डॉक्टरों की टीम–डॉ. भविता वाधवा, डॉ. सुधीर भंडारी और डॉ. मनीषा खन्ना–ने इस चुनौतीपूर्ण केस का

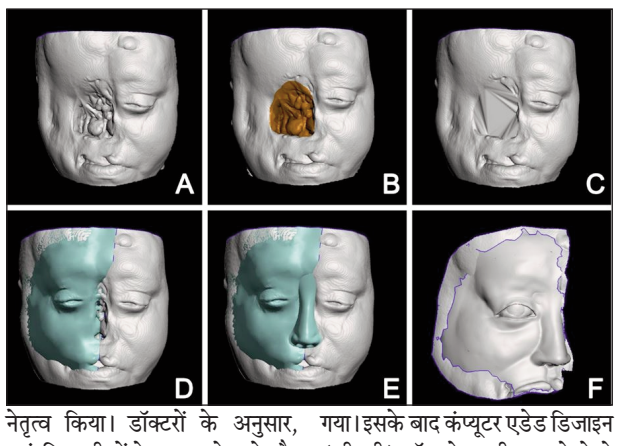

नेतृत्व किया। डॉक्टरों के अनुसार, पारंपरिक तरीकों से इस तरह के बड़े और जटिल चेहरे के दोष का सटीक उपचार संभव नहीं था।

इसके बाद डॉक्टरों ने पंजाब यूनिवर्सिटी के यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी (यूआईईटी) और डिजाइन इनोवेशन सेंटर (डीआईसी) के विशेषज्ञों के साथ मिलकर एक आधुनिक डिजिटल तकनीक अपनाई। इस टीम का नेतृत्व प्रोफेसर प्रशांत जिंदल, प्रोफेसर ममता जुनेजा और प्रशांत प्रकाश ने किया। डिजिटल प्रक्रिया के तहत स्ट्रक्चर्ड लाइट फेशियल स्कैनिंग के जरिए मरीज के चेहरे का सटीक 3डी मॉडल तैयार किया गया। इसके बाद कंप्यूटर एडेड डिजाइन (सीएडी) सॉफ्टवेयर की मदद से चेहरे के स्वस्थ हिस्से को आधार बनाकर क्षतिग्रस्त हिस्से का पुनर्निर्माण किया गया। इस तकनीक ने एकदम सटीक और मरीज के अनुरूप कृत्रिम अंग (प्रोस्थेसिस) तैयार करने में मदद की। इस केस की सबसे खास बात 3डी डिजाइनिंग और 3डी प्रिंटिंग तकनीक का इस्तेमाल रहा, जिसके जरिए एक विशेष मोल्ड तैयार किया गया। साथ ही, प्रोस्थेसिस के अंदर हल्का लेकिन मजबूत ढांचा (शिम) बनाया गया, जिससे उसका वजन कम रखा जा सके और पहनने में आराम रहे। अंतिम प्रोस्थेसिस को मेडिकल ग्रेड सिलिकॉन से पारंपरिक तकनीक द्वारा तैयार किया गया, जिससे उसे प्राकृतिक रूप और बेहतर सौंदर्य मिला। इस उपचार के बाद महिला के जीवन में बड़ा बदलाव आया। उसका आत्मविश्वास बढ़ा और वह दोबारा सामान्य जीवन जीने लगी। अब वह बिना किसी डर या झिझक के समाज में लोगों से मिल-जुल पा रही है।

पीजीआई में स्वच्छता पखवाड़ा 2026 का शुभारंभ

चंडीगढ़। पीजीआई में स्वच्छता पखवाड़ा 2026 का शुभारंभ उत्साह और जनभागीदारी के साथ किया गया। 1 से 15 अप्रैल तक चलने वाले इस अभियान का उद्देश्य स्वच्छता, सुरक्षित कचरा प्रबंधन और जनजागरूकता को बढ़ावा देना है। यह अभियान केंद्र सरकार के परिवार कल्याण एवं स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के अनुसार आयोजित किया जा रहा है। कार्यक्रम की शुरुआत पीजीआई के डायरेक्टर प्रो. विवेक लाल ने स्वच्छता शपथ दिलाकर की। इस दौरान मेडिकल सुपरिटेंडेंट, फैकल्टी सदस्य, रेजिडेंट डॉक्टर, सफाई कर्मचारी और अन्य स्टाफ मौजूद रहे। डायरेक्टर ने स्वच्छता कर्मयोगियों के योगदान की सराहना करते हुए कहा कि स्वच्छता केवल एक अभियान नहीं, बल्कि जीवनशैली है। उन्होंने हाल ही में पीजीआई को राष्ट्रीय कायाकल्प अवॉर्ड 2025-26 में दूसरा स्थान मिलने को संस्थान की बड़ी उपलब्धि बताया। इस अवसर पर स्वच्छता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। साथ ही स्वच्छता वॉकाथॉन और प्लॉगिंग अभियान भी आयोजित किया गया, जिसमें 300 से अधिक स्वयंसेवकों और कर्मचारियों ने भाग लिया। स्वच्छता पखवाड़ा के

पहले दिन प्रमुख गतिविधियों में शपथ ग्रहण, जागरूकता रैली, सामुदायिक कार्यक्रम और दो डिब्बों वाले कचरा पृथक्करण किट का वितरण शामिल रहा। पीजीआई रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन के सहयोग से आवासीय क्षेत्र में विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान निवासियों को कचरा पृथक्करण के बारे में जागरूक किया गया और उन्हें दो-बिन किट वितरित किए गए। अस्पताल के विभिन्न विभागों द्वारा मरीजों और उनके तीमारदारों को भी स्वच्छता शपथ दिलाई गई। इससे यह संदेश दिया गया कि स्वच्छता केवल कर्मचारियों की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि सभी की साझा जिम्मेदारी है।

राज्यसभा में रेखा शर्मा ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सामान्य प्रशासन) विधेयक, 2026 का समर्थन किया

सिटी दर्पण संवाददाता
पंचकूला

राज्यसभा में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सामान्य प्रशासन) विधेयक, 2026 पर हुई चर्चा के दौरान हरियाणा से राज्यसभा सांसद श्रीमती रेखा शर्मा ने विधेयक का दृढ़ समर्थन करते हुए इसे देश की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने तथा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के अधिकारियों एवं जवानों के मनोबल, सेवा-शर्तों और संस्थागत संरचना को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। सदन में अपने वक्तव्य के दौरान उन्होंने कहा कि केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल देश की आंतरिक सुरक्षा प्रणाली का एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्तंभ हैं, जो आतंकवाद-रोधी अभियानों, वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में शांति स्थापना, सीमावर्ती क्षेत्रों में सहयोगात्मक सुरक्षा, कानून-व्यवस्था बनाए रखने तथा आपदा प्रबंधन जैसे अनेक संवेदनशील दायित्वों का निर्वहन अत्यंत कठिन परिस्थितियों में करते हैं। उन्होंने कहा कि केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सामान्य प्रशासन) विधेयक, 2026 केवल एक प्रशासनिक या प्रक्रियात्मक संशोधन नहीं है, बल्कि यह एक दूरदर्शी और संरचनात्मक सुधार है, जिसका उद्देश्य प्रशासनिक ढांचे को सुदृढ़ करना, सेवा-शर्तों में सुधार करना तथा अधिकारियों और जवानों के कैरियर प्रगति के अवसरों को और अधिक व्यवस्थित एवं प्रभावी बनाना है। ग्रुप अ जनरल ड्यूटी अधिकारियों की पदोन्नति से संबंधित विपक्ष द्वारा उठाए गए मुद्दों पर प्रतिक्रिया देते हुए रेखा शर्मा ने कहा कि इस संबंध में प्रस्तुत किए गए कुछ आरोप तथ्यात्मक रूप से भ्रामक हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि पिछले वर्षों में अधिकारियों को नियमित पदोन्नतियाँ प्रदान की गई हैं तथा अनेक अधिकारी वरिष्ठ नेतृत्व स्तर तक पहुँचे हैं, जो यह दर्शाता है कि सरकार अधिकारियों के कैरियर विकास के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने आगे कहा कि प्रशासनिक ढांचे को मजबूत करना सीधे तौर पर उनकी परिचालन क्षमता, समन्वय तंत्र तथा राष्ट्रीय सुरक्षा चुनौतियों से प्रभावी ढंग से निपटने की क्षमता को सुदृढ़ करता है। रेखा शर्मा ने कहा कि केंद्र सरकार अधिकारियों और जवानों के सेवा-परिस्थितियों में सुधार, कैरियर प्रगति के अवसरों के विस्तार, प्रशासनिक पारदर्शिता को बढ़ावा देने तथा आधुनिकीकरण से जुड़े प्रयासों को निरंतर आगे बढ़ा रही है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सामान्य प्रशासन) विधेयक, 2026 केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की संस्थागत क्षमता, प्रशासनिक दक्षता और कार्य-प्रणाली को और अधिक प्रभावी बनाएगा तथा इससे देश की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था को नई मजबूती प्राप्त होगी।

इग्नू क्षेत्रीय केंद्र चंडीगढ़, रायपुररानी स्थित सरकारी पीजी कॉलेज परिसर से कार्य शुरू

सिटी दर्पण संवाददाता
पंचकूला

इग्नू क्षेत्रीय केंद्र चंडीगढ़ के वरिष्ठ क्षेत्रीय निदेशक डॉ. भानु प्रताप सिंह ने बताया कि इग्नू क्षेत्रीय केंद्र चंडीगढ़ ने पंचकूला के रायपुररानी स्थित सरकारी पीजी कॉलेज में स्थित अपने नए परिसर से पूर्णतः कार्य करना शुरू कर दिया है। इससे पहले, क्षेत्रीय केंद्र चंडीगढ़ का उप-कार्यालय सेक्टर 28, चंडीगढ़ स्थित सीडीसीएल भवन से संचालित हो रहा था, जबकि इसका मुख्य कार्यालय सेक्टर 12, करनाल में स्थित था। डॉ. भानु प्रताप सिंह ने बताया कि यह महत्वपूर्ण विकास, क्षेत्र में विश्वविद्यालय की पहुंच और शैक्षणिक सहायता सेवाओं को मजबूत करने की दिशा में एक नए चरण का प्रतीक है। क्षेत्रीय केंद्र चंडीगढ़, चंडीगढ़, अंबाला, पंचकुला (हरियाणा), पटियाला, रूपनगर, मोहाली और फतेहगढ़ साहिब (पंजाब) जिलों को

कवर करता है। नए परिसर का उद्देश्य विद्यार्थियों, अकादमिक सलाहकारों और कर्मचारियों के लिए बेहतर बुनियादी ढांचा और अधिक सुलभ वातावरण प्रदान करना है। इस बदलाव से संचालन की समग्र दक्षता में वृद्धि होने और छात्र सहायता सेवाओं की बेहतर डिलीवरी में सहायता मिलने की उम्मीद है। डॉ. भानु प्रताप सिंह ने आगे बताया कि अपनी शैक्षणिक गतिविधियों को जारी रखते

- 39वां दीक्षांत समारोह 7 अप्रैल 2026 को : डॉ. भानु प्रताप सिंह

हुए, इग्नू का 39वां दीक्षांत समारोह 7 अप्रैल 2026 को आयोजित किया जाएगा। यह दीक्षांत समारोह नई दिल्ली स्थित मुख्यालय में और साथ ही चंडीगढ़ सहित सभी क्षेत्रीय केंद्रों में एक साथ आयोजित किया जाएगा। समारोह के दौरान कुल 5498 छात्र डिग्री, डिप्लोमा और प्रमाण पत्र प्राप्त करने के पात्र हैं और उन्हें समारोह में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है। क्षेत्रीय केंद्र सभी सफल छात्रों को शुभकामनाएं देता है।

उन्होंने बताया कि हाल ही में क्षेत्रीय केंद्र चंडीगढ़ के अंतर्गत शिक्षार्थियों के लिए कई नए शैक्षणिक कार्यक्रम शुरू किए गए हैं, जिससे विश्वविद्यालय की शैक्षणिक पहुंच और भी व्यापक हो गई है।

रबी विपणन सीजन 2026 के दौरान मंडी में गेट पास जारी करने के लिए दिशा निर्देश जारी

सिटी दर्पण संवाददाता
पंचकूला

रबी विपणन सीजन 2026 के दौरान गेट पास जारी करने एवं बोली प्रक्रिया प्रारंभ करने से संबंधित हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा किसान भाइयों के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं । यह जानकारी देते हुए मंडी बोर्ड के प्रवक्ता ने बताया किसान भाइयों को कोई भी असुविधा न हो, इसलिए इसलिए गेट पास को लेकर जो भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं उन्हें दूर करने हेतु मंडी बोर्ड द्वारा आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए हैं । सभी किसान भाई इन दिशा निदेर्शों के अनुसार बहुत आसानी से मंडी में अपनी फसल को बेच सकते हैं ।यदि किसी किसान भाई को फिर भी कोई दिक्कत आती है तो वह टोल फ्री नंबर 18001802060 पर कॉल करके सहायता प्राप्त कर सकते हैं।

- किसान भाइयों से अपील अफवाहों पर ध्यान ना दे
- असुविधा से बचने हेतु नियमों का पालन करें

उन्होंने बताया की जारी दिशा निदेर्शों के अनुसार किसान अपनी फसल को ट्रेक्टर ट्राली के अलावा अन्य पारम्परिक साधन जैसे की बैलगाड़ी इत्यादि द्वारा मंडी में ला सकता है। यदि ट्रेक्टर ट्राली पर नंबर प्लेट नहीं है तो भी किसान ट्रेक्टर के नंबर प्लेट पर पेंट द्वारा रजिस्ट्रेशन नंबर लिख कर या रजिस्ट्रेशन नंबर को पेपर स्टीकर इत्यादि पर लिख कर भी ला सकता है गेट पास को काटने के लिए हरियाणा कौशल रोजगार निगम से कर्मचारियों को रखा गया है जिससे गेट पास काटने के लिए किसानों को अधिक समय तक इंतजार न करना पड़े । इसलिए ऐसी व्यवस्था की गयी है जिससे उपयुक्त समय यानि सुबह 6 बजे से रात 8 बजे तक किसान अपनी फसल को बिक्री हेतु मंडी में ला सकें। उन्होंने बताया की मंडी के निर्धारित क्षेत्र की इस बार जीओ फेंसिंग की गई है। जीओ फेंसिंग एरिया में ही गेटपास कटेगा। फसल का गेट पास कटने से लेकर गेट निकासी तक की सारी प्रक्रिया मंडी के जीओ फेंसड क्षेत्र में ही पूरी की जाएगी । मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर किसान द्वारा जब रजिस्ट्रेशन किया जाता है तो जमीन का मालिक या जमीन को पट्टे पर ले कर खेती कर रहा व्यक्ति भी रजिस्ट्रेशन करा सकता है। इस तरह किसान या जमीन का मालिक या जमीन को पट्टे पर ले कर खेती कर रहा व्यक्ति भी अपने नामित व्यक्तियों ;रिश्तेदार या कोई भी परिचित व्यक्तिद्ध को मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकृत कर सकता है।

संक्षिप्त-समाचार

पंचकूला में सजेगा 500 मूक-बधिर महिलाओं की प्रतिभा का संगम

पंचकूला। हरियाणा फाउंडेशन ऑफ डेफ वुमन ट्रस्ट (अखिल भारतीय बधिर महिला संस्थान की इकाई) द्वारा आगामी 16 से 18 अप्रैल तक पंचकूला के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस ऑडिटोरियम में '6ठा राष्ट्रीय सांस्कृतिक उत्सव - बधिर महिलाएँ' का भव्य आयोजन किया जा रहा है। संस्थान की चेयरपर्सन राज्यलक्ष्मी राव के नेतृत्व में आयोजित होने वाले इस तीन दिवसीय महोत्सव में पूरे भारत से लगभग 500 दिव्यांग (मूक-बधिर) महिलाएँ भाग लेने पंचकूला पहुँच रही हैं। कार्यक्रम की जानकारी देते हुए आयोजकों ने बताया कि इस महोत्सव में मुख्य अतिथि के रूप में हरियाणा की सिंचाई मंत्री श्रीमती श्रुति चौधरी शिरकत करेंगी। साथ ही, अनेक प्रसिद्ध कलाकार भी विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे। फिल्म जगत की अन्य नामचीन हस्तियां भी इस मंच पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगी। इस विशाल आयोजन की रूपरेखा को सफल बनाने में मुख्यमंत्री हरियाणा के राजनीतिक सचिव श्री तरुण भंडारी का विशेष योगदान रहेगा। उनके सहयोग और देखरेख में ही देशभर से आने वाली इन 500 महिलाओं के रहने, भोजन और अन्य सभी व्यवस्थाओं को सुनिश्चित किया गया है। उनके ही विशेष आग्रह पर फिल्म जगत के कलाकार इन दिव्यांग महिलाओं का उत्साह बढ़ाने पंचकूला आ रहे हैं। उत्सव के दौरान प्रतिभागियों द्वारा विभिन्न सांस्कृतिक प्रस्तुतियां और नृत्य कार्यक्रम पेश किए जाएंगे। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य मूक-बधिर महिलाओं के आत्मविश्वास को बढ़ाना और उन्हें अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने के लिए एक राष्ट्रीय मंच प्रदान करना है। यह आयोजन समाज में महिला सशक्तिकरण और समावेशिता का एक उत्कृष्ट उदाहरण पेश करेगा।

ट्राइसिटी ओपन लॉन टेनिस टूर्नामेंट 2026 के संबंध में संशोधन एवं समय-सीमा विस्तार सूचना

चंडीगढ़। ट्राइसिटी ओपन लॉन टेनिस टूर्नामेंट-2026 हेतु एंट्री प्रोफार्मा जमा करने की अंतिम तिथि को बढ़ाकर अब 05.04.2026 सायं 04:00 बजे तक कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त, आयु पात्रता के लिए कट-ऑफ तिथियां अब के नियमों के अनुसार, अर्थात संबंधित वर्ष की 31 दिसंबर तक मानी जाएंगी। संशोधित आयु पात्रता इस प्रकार हैः ओपन पुरुष एवं महिला एकलः 31.12.2011 या उससे पूर्व जन्म, 35+ पुरुष एकल एवं युगलः 31.12.1991 या उससे पूर्व जन्म, 35+ महिला एकलः 31.12.1981 या उससे पूर्व जन्म, 45+ पुरुष एकल एवं युगलः 31.12.1981 या उससे पूर्व जन्म, 55+ पुरुष एकल एवं युगलः 31.12.1971 या उससे पूर्व जन्म। अन्य सभी नियम एवं शर्तें यथावत रहेंगी।

लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह ने पश्चिमी कमान की कमान संभाली

सिटी दर्पण संवाददाता
चंडीगढ़

लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह ने 1 अप्रैल 2026 को पश्चिमी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ के रूप में कार्यभार संभाल लिया है। उन्होंने लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार का स्थान लिया है, जो 31 मार्च 2026 को एक गौरवपूर्ण कार्यकाल पूरा करने के बाद सेवानिवृत्त हुए। पैराशूट रेजिमेंट (स्पेशल फोर्सेस) के अधिकारी लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह को दिसंबर 1987 में 4वीं बटालियन, द पैराशूट रेजिमेंट (स्पेशल फोर्सेस) में कमीशन मिला था। वे भारतीय सैन्य अकादमी, देहरादून और लखनऊ विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र हैं।

लगभग चार दशकों के अपने करियर में उन्होंने कमान और स्टाफ से जुड़े अनेक महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया है। उन्होंने उत्तरी और पश्चिमी सीमाओं के उच्च-ऊंचाई और संवेदनशील क्षेत्रों में विभिन्न सैन्य

फॉर्मेशन्स का नेतृत्व किया है। उनके ऑपरेशनल अनुभव में ऑपरेशन पवन में भागीदारी के साथ-साथ नियंत्रण रेखा और अंतरराष्ट्रीय सीमा पर कई बार काउंटर-इंसर्जेंसी अभियानों का अनुभव शामिल है। वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के रूप में नियुक्ति से पहले, उन्होंने सेना मुख्यालय में महानिदेशक परिचालन लॉजिस्टिक्स (डीजीओएल) के रूप में कार्य किया, जहां उन्होंने ऑपरेशनल मोबिलिटी, लॉजिस्टिक्स एकीकरण और स्थायित्व क्षमताओं को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वीसीओएएस के रूप में उन्होंने सेना की संरचना, क्षमता विकास और ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस की तैयारी में महत्वपूर्ण योगदान दिया।

उन्होंने कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट, सिकंदराबाद से डिफेंस मैनेजमेंट कोर्स और भारतीय लोक प्रशासन संस्थान से एडवांस्ड प्रोफेशनल प्रोग्राम इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन किया है। उनके पास पंजाब विश्वविद्यालय से फिलॉसफी में मास्टर डिग्री है। उनकी उत्कृष्ट सेवा और वीरता के लिए उन्हें अति विशिष्ट सेवा मेडल और सेना मेडल (दो बार) से सम्मानित किया गया है।

कार्यभार संभालते हुए लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह ने उच्च स्तर की परिचालन तैयारी बनाए रखने, इनोवेशन्स को बढ़ावा देने तथा सभी रैंकों के कल्याण और मनोबल सुनिश्चित करने के अपने संकल्प की पुनः पुष्टि की। यह बदलाव नेतृत्व की निरंतरता और भारतीय सेना की ऑपरेशनल एक्सीलेंस तथा राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

उनके नेतृत्व में पश्चिमी कमान बहु-क्षेत्रीय अभियानों, ड्रोन और काउंटर-ड्रोन जैसी उन्नत तकनीकों के समावेश, इंटेलिजेंस-ड्रिवन ऑपरेशन्स और इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास पर ध्यान केंद्रित करती रहेगी, साथ ही नागरिक प्रशासन के साथ समन्वय बनाए रखेगी।

भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई: सी.ई.वी. केन्द्र घरौंडा के विषय विशेषज्ञ रिश्वत मामले में चालान पेश

सिटी दर्पण संवाददाता
करनाल

राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, करनाल ने भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल्स (सी.ई.वी.), घरौंडा में कार्यरत विषय वस्तु विशेषज्ञ प्रमोद कुमार के विरुद्ध माननीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, करनाल की अदालत में चालान प्रस्तुत किया है। यह चालान भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 7 व 13(1)(ए) के तहत दाखिल किया गया है।

मामले की शुरूआत नूंह (मेवात) जिले के गांव हसनपुर सोहना ब्लॉक इन्द्री निवासी राहुल की शिकायत से हुई। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि प्रमोद कुमार ने सी.ई.वी. केन्द्र, घरौंडा में अवैध रूप से उगाए गए 10,000 खरबूजे के पौधों को 3.5 रुपये प्रति पौधा की दर से बेचने के एवज में 35,000 रुपये रिश्वत की मांग की।

शिकायत की गंभीरता को देखते हुए ब्यूरो ने त्वरित कार्रवाई करते हुए योजनाबद्ध ट्रैप लगाया। इस दौरान आरोपी प्रमोद कुमार को गवाह सुनील कुमार (निवासी गांव बलहेड़ा, करनाल) के माध्यम से शिकायतकर्ता से 35,000 रुपये नकद रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया।

इस संबंध में आरोपी के खिलाफ अभियोग संख्या 01 दिनांक 02.02.2026 थाना राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, करनाल में दर्ज किया गया था। विस्तृत जांच के उपरांत अब आरोपी के विरुद्ध न्यायालय में चालान प्रस्तुत कर दिया गया है। राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, करनाल की इस कार्रवाई से स्पष्ट संदेश गया है कि भ्रष्टाचार के मामलों में किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा और कानून के तहत सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

श्री कृष्ण आयुष विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र के विद्यार्थियों ने प्रकृति के साथ नेचर कैम्प थापली मे बिताए पल

युवाओं को सीखने और नेतृत्व विकास के लिए मंच दे रही हरियाणा सरकार: नरेंद्र सिंह

सिटी दर्पण संवाददाता
पंचकुला

हरियाणा सरकार के युवा कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत आयोजित नेचर कैम्प थापली में इन दिनों हरियाणा के साथ-साथ पंजाब के विभिन्न विश्वविद्यालयों के विद्यार्थी भी सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं। इस भ्रमण कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को प्रकृति के निकट लाना तथा पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करना है। युवा कल्याण संयोजक नरेंद्र सिंह ने श्री कृष्ण आयुष विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र के विद्यार्थियों के साथ संवाद किया। उन्होंने छात्रों से उनके अनुभव साझा करने को कहा तथा प्रकृति संरक्षण में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि कि हरियाणा सरकार युवाओं को ऐसे मंच प्रदान कर रही है ,जहां वे सीखने के साथ-साथ नेतृत्व क्षमता भी विकसित कर सकें। उन्होंने विद्यार्थियों को पर्यावरण संरक्षण

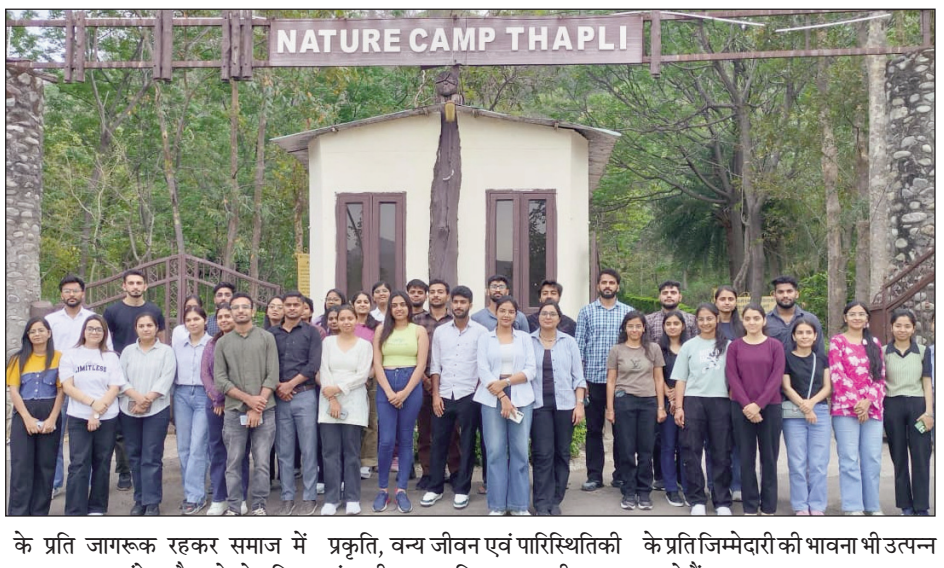

के प्रति जागरूक रहकर समाज में सकारात्मक संदेश फैलाने के लिए प्रेरित किया।

कैंप संयोजक नैन्सी नैन ने बताया कि हरियाणा सरकार द्वारा संचालित इस विशेष कार्यक्रम के तहत विद्यार्थियों को प्रकृति, वन्य जीवन एवं पारिस्थितिकी तंत्र की व्यावहारिक जानकारी प्रदान की जा रही है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के आयोजन युवाओं में साहसिक गतिविधियों के प्रति रुचि विकसित करने के साथ.साथ पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी की भावना भी उत्पन्न करते हैं।

इसी कड़ी में आज श्री कृष्ण आयुष विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र के छात्रों ने नेचर कैम्प थापली का भ्रमण किया तथा ट्रैकिंग गतिविधियों में उत्साहपूर्वक भाग लिया। विद्यार्थियों ने प्राकृतिक वातावरण को नजदीक से अनुभव किया और पर्यावरण के विभिन्न पहलुओं को समझा।

इस अवसर पर डिप्टी रेंज ऑफिसर ने उपस्थित विद्यार्थियों को जलवायु परिवर्तनए पारिस्थितिकी तंत्र एवं जैव विविधता के संरक्षण के विषय में विस्तृत जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में युवाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। कार्यक्रम के अंत में विद्यार्थियों ने इस अनुभव को ज्ञानवर्धक एवं प्रेरणादायक बताते हुए भविष्य में भी ऐसे आयोजनों में भाग लेने की इच्छा व्यक्त की।

उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजन युवाओं में नेतृत्व क्षमता, अनुशासन और सामाजिक जिम्मेदारी की भावना विकसित करते हैं। विद्यार्थियों ने प्रकृति संरक्षण के संदेश को समाज तक पहुंचाने का संकल्प किया।

एनएसएस स्वयंसेविका रजनप्रीत कौर को वर्ल्ड यूथ पार्लियामेंट 2026 में सर्वश्रेष्ठ वक्ता पुरस्कार हेतु शिक्षा सचिव द्वारा सम्मानित

सिटी दर्पण संवाददाता
चंडीगढ़

चंडीगढ़ एवं राज्य एनएसएस प्रकोष्ठ के लिए गर्व का विषय है कि पोस्ट ग्रेजुएट गवर्नमेंट कॉलेज, सेक्टर-11, चंडीगढ़ की एनएसएस स्वयंसेविका सुश्री रजनप्रीत कौर को वर्ल्ड यूथ पार्लियामेंट 2026 में उनकी उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए चंडीगढ़ प्रशासन की शिक्षा सचिव सुश्री प्रेरणा पुरी, आईएएस द्वारा सम्मानित किया गया। यह प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम 24 से 26 मार्च 2026 तक बेंगलुरु, कर्नाटक में आयोजित किया गया, जिसका आयोजन राज्य एनएसएस प्रकोष्ठ द्वारा युवा सशक्तिकरण एवं खेल विभाग, कर्नाटक सरकार तथा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज, जीकेवीके के सहयोग से किया गया। इस कार्यक्रम में 29 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। सुश्री रजनप्रीत कौर ने युवा और लोकतंत्र विषय के अंतर्गत प्रश्नकाल के दौरान सर्वश्रेष्ठ वक्ता (उपविजेता) पुरस्कार प्राप्त किया। उन्होंने ग्लोबल एंटी-मिसइन्फॉर्मेशन एंड मीडिया लिटरेसी फ्रेमवर्क बिल 2026 विषय पर अपने विचार प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किए, जिसकी जूरी एवं प्रतिनिधियों द्वारा सराहना की गई। सुश्री भूमि सहित 4 अन्य एनएसएस स्वयंसेवकों तथा कार्यक्रम अधिकारी खुशवंत ने भी इस वैश्विक मंच पर चंडीगढ़ का प्रतिनिधित्व किया। इस उल्लेखनीय उपलब्धि की सराहना करते हुए शिक्षा सचिव सुश्री प्रेरणा पुरी ने कहा कि एनएसएस स्वयंसेवकों की ऐसी उपलब्धियां युवाओं के नेतृत्व की शक्ति को दर्शाती हैं तथा ऐसे मंच छात्रों में लोकतांत्रिक मूल्यों, संवाद कौशल और वैश्विक जागरूकता को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। डॉ. नेमी चंद गोलिया, एनएसएस राज्य संपर्क अधिकारी, चंडीगढ़ ने रजनप्रीत कौर एवं अन्य स्वयंसेवकों को बधाई देते हुए कहा कि उनकी सफलता एनएसएस की जीवंत भावना और युवाओं की वैश्विक नागरिक बनने की क्षमता को प्रदर्शित करती है। एनएसएस कार्यक्रम अधिकारी डॉ. मोनिका दारा ने भी रजनप्रीत कौर के समर्पण एवं परिश्रम की सराहना की। श्री जय भगवान, क्षेत्रीय निदेशक, एनएसएस चंडीगढ़, युवा मामले एवं खेल मंत्रालय भी इस अवसर पर उपस्थित रहे।